हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 2001 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 8 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)26
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)30
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई	(4)59
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना आदि	(4)60
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव — नीलगायों (रोज) द्वारा फसलों की क्षति सम्बन्धी	(4)62
वक्तव्य— उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्य संसदीय सचिव द्वारा—	(4)63
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)66
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— चौधरी बंसी लाल एम०एल०ए० द्वारा	(4)79
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)79
वाक-आउट	(4)97
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)97
बैठक का समय बढ़ाना	(4)99
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)99
वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(4)100
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश करना	(4)100

मूल्य : 114 00

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 8 मार्च, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Agriculture College, Bahin

***530. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an agriculture College in Bahin?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं, श्रीमान।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहां उपस्थित हैं जनता दरबार में दो बार हथीन और पलवल में इन्होंने ग्राम पंचायत बहीन में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया था। वहां बहीन पंचायत के पास 440 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि क्या बहीन में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज या दूसरी एजूकेशनल इंस्टीच्यूशन खोलने का सरकार का विचार है?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हरियाणा प्रांत एक कृषि प्रधान प्रदेश है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हमेशा इस बारे में नर्म रवैया रहता है तथा जहां एग्रीकल्चर से संबंधित बात आती है उस तरफ वे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1977 में हिसार में हुई थी। उसके तहत दो एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। एक तो हिसार यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और दूसरा कॉलेज कुरुक्षेत्र जिले के कौल में खोला गया है। पहले इन कॉलेजों में 160 सीटें थीं लेकिन वे सीटें पूरी न भरने के कारण उन सीटों को घटाकर 106 कर दिया गया था। आज के दिन इन 106 सीटों पर भी पूरा एडमिशन नहीं हुआ है और कुछ सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। अगर बहीन के छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे हिसार या कौल में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए फिलहाल बहीन में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक दृष्टि से हथीन क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है। विशेषकर यह क्षेत्र स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना संभव नहीं है तो कोई दूसरा एजूकेशनल इंस्टीच्यूट वहां पर खोलने की व्यवस्था यह सरकार करेगी जिससे हथीन और मेवात क्षेत्र के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई ऐसा आश्वासन दिया है तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, शायद सम्मानित साथी को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी रही होगी। मैंने कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। ये स्वयं ही कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं तो कोई दूसरा कॉलेज खोल दिया जाए इसलिए यह प्रश्न एग्रीकल्चर मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है।

Auto Market in Jhajjar

* 569. **Shri Daryao Singh :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an Auto Market in Jhajjar ; and

(b) if not, whether the Government will consider the proposal for the construction of said Auto Market ?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ, सरकार इस बारे प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार करेगी।

श्री दरियाव सिंह : स्पीकर सर, अगर सरकार विचार करेगी तो इसके लिए सरकार का धन्यवाद।

Purchase of New Buses

* 319 **Sh. Padam Singh Dahiya :** Will the Minister for Transport be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase new buses; if so, the total expenditure to be incurred thereon alongwith the time by which these are likely to be purchased.

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : हां श्री मान् जी। 1100 बसें 93.50 करोड़ की लागत से खरीद करने का निर्णय लिया गया है। नई बसों की खरीद 31-7-2001 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो 1100 बसें खरीदने के लिए साढ़े 93 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया है, इस साढ़े 93 करोड़ रुपये से, 1100 कौन सी बसें खरीदी जाएंगी?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना

चाहूंगा कि हमने बताया है कि हम साढे 93 करोड़ रुपये की लागत से 1100 बसें खरीदने का काम करेंगे। यह सरकार जब से बनी है तब से अब तक 500 नई बसें खरीद ली गई हैं तथा बाकी बसों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है और ये बसें 31-7-2001 तक आ जाएंगी और इन पर जितना खर्च आएगा वह हम करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 1100 नई बसें आएंगी, उन बसों से कौन सी फ्लीट रिप्लेस होगी? यह तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एक आम आदमी को यातायात की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वह बस ही है क्योंकि हर आदमी के पास कार या मोटर साइकिल नहीं है। सरकार की पुरानी पॉलिसी में सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइयटीज की बसों को गांवों के 10-10, 15-15 किलोमीटर के रूट्स दिए हुए थे और उनमें से आधी बसें तो चल नहीं रही थीं क्योंकि ज्यादातर रूट्स वायेबल नहीं हैं। कुछ प्राइवेट बसों वाले कोई बारात या सत्संग में अपनी बसें ले जाते हैं और निर्धारित रूट्स पर बसें नहीं चलती जिसके कारण लोगों को यातायात में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे रूट्स पर आम आदमी को बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार और मुख्य मंत्री चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार की एक ही सोच है कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ा जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और हरियाणा रोडवेज का नाम पूरे देश के अन्दर बरकरार रहे। बसों का जो बैकलॉग चल रहा था उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। पहले बसें आठ साल के बाद बदला करती थीं लेकिन देखा गया है कि आठ साल में बस की हालत खस्ता हो जाती है इसलिए हमारी सरकार ने बसों को 7 साल के बाद बदलने का निर्णय लिया है। अगले साल 539 और बसें रिप्लेस की जाएंगी। 7 साल से ज्यादा समय तक चलने वाली 400 बसों को बदला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी बस सेवा की जरूरत होगी वहां हम बस सर्विस देने का काम करेंगे। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन के बगैर कभी हाऊस में बोलने की कोशिश नहीं करता और जब आप मुझे बैठने के लिए कहते हैं, मैं बैठ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से पूछने का मतलब यह था कि सरकार ने साढे 93 करोड़ रुपये से जो 1100 बसें खरीदने का फैसला किया है उससे कौन सी बसें और किस रेट पर बसें खरीदी जाएंगी?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने एक नई पॉलिसी तय की है। पहले परिवहन व्यवस्था इस प्रकार बिगाड़ी गई थी कि कुछ रूट्ज प्राइवेट बसों को दे दिए गए थे। जैसे अभी बिसला जी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसे-2 रूट्ज जो वायेबल नहीं थे,वहां प्राइवेट बसें चलाई गईं तथा जिनके पास बस परमिट थे, जो बस ओनर थे वे निरन्तर इस प्रयास में रहते थे कि कहीं कोई बारात मिल जाए या कोई और अवसर मिल जाए जिससे उन्हें ज्यादा आमदन हो जाए तो वे वहां बसें ले जाते थे यानि रूट्स वायेबल नहीं थे।

हरियाणा सरकार ने नये सिरे से एक फैसला किया है कि इस प्रकार के वायेबल रूट्स बनाये जाएं कि लम्बे रूट्स पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलें तथा जो 20, 30 और 40 कि०मी०के छोटे टुकड़े हैं वहां पर प्राइवेट सैक्टर की बसें चलें। इस स्कीम के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि रात को हर गांव में बस जाए ताकि सवेरे छात्रों को स्कूल या कॉलेज जाने में और कर्मचारियों को दफ्तर जाने में दिक्कत न आए। इस स्कीम के तहत 1100 बसें लगभग साढे 93 करोड़ रुपये की लागत

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

से खरीदी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी वित्त मंत्री रहे हैं इन्हें भी पता है कि एक साथ इतनी ज्यादा बसों की बॉडीज नहीं बन सकतीं। कुछ बसों की बॉडीज अभी बन रही है और कुछ बसें बाद में खरीद ली जाएंगी। अगर पैसा 93 करोड़ से ज्यादा लगेगा तो भी हम लगाएंगे और ज्यादा बसें खरीदने की आवश्यकता पड़ी तो वे भी खरीदेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ***।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) मांगे राम जी ने अभी जो शब्द कहे हैं वे हाऊस की कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी को बताना चाहूंगा कि एक लेलैंड बस की चेसिज का रेट 5.70 लाख रुपये और एक टाटा बस की चेसिज का रेट 5.80 लाख रुपये पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारें बस की बॉडी बनवाने पर चार या साढे चार लाख रुपये खर्च किया करती थी और बस की बॉडी किसी प्राइवेट पार्टी से बनवाती थी। इसकी जगह हम बस की बॉडी एच.आर.ई.सी., गुड़गांव से बनवा रहे हैं और एक बस की बॉडी पर 2.75 लाख रुपये खर्चा आएगा। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से एक बस पर टोटल खर्चा करीब-करीब 8.55 लाख रुपये आएगा, और 1100 बसों पर 93.50 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, अगर गुप्ता जी चाहें तो इसका हिसाब लगा लें।

Fluoride In Underground Water

***444. Shri Puran Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is an excess quantity of fluoride in the underground water of districts Rewari and Mahendergarh; if so, whether the Government is formulating any scheme to solve the said problem.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हां। सरकार रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में अधिक फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

श्री पूर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह समस्या रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी है और यदि है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : स्पीकर सर, विशेषतौर से यह स्कीम रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के लिए है और यह प्रश्न भी इन्हीं जिलों से संबंधित है। फिर भी मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इन जिलों के अतिरिक्त यह स्कीम सिरसा, झज्जर, हिसार और रोहतक जिलों के ग्रामीण इलाकों में भी लागू की जा रही है। इस स्कीम के लिए नाबार्ड से 40 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत हो चुका है और 106 गांवों में 58 योजनाओं के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी इस स्कीम के तहत दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

जानना चाहूंगा कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है वैसे-वैसे भूमि के नीचे पानी में फ्लोराइड बढ़ रहा है और यह समय के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। क्या सरकार ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है कि सारे हरियाणा के अन्दर नीचे के पानी को टैस्ट करवाया जाए?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, फ्लोराइड की समस्या ज्यादातर रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में ही है और प्रदेश भर में हमने इस मामले का सर्वेक्षण भी करवाया था और प्रदेश की सरकार ने जहां पेयजल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जिसके तहत हरियाणा प्रदेश में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देंगे। इसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कम पानी वाले 500 गांवों में 55 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी बढ़ाने का प्रस्ताव है। 31-1-2001 तक 333 गांवों में जल वितरण स्तर बढ़ाया जा चुका है और शेष गांवों में 31 मार्च, 2001 तक जल वितरण स्तर बढ़ाकर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जांट वाटर सप्लाई स्कीम है और वहां के पानी को लैबोरेट्री में टैस्ट कराने पर यह साबित हो चुका है कि वह पानी पीने लायक नहीं है वह पानी दाँतों और हड्डियों में बीमारियां पैदा करता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उस पीने के पानी को बदलने के लिए कुछ कार्यवाही करेंगे अथवा इसके लिए कोई दूसरा प्रोवीजन रखेंगे? अभी तक भी वही पानी लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो विशेष रूप से महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के एरिया में पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने के सम्बन्ध में सवाल था। माननीय सदस्य इस बारे में अपना अलग से नोटिस दे दें उसका जवाब दे दिया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के पानी में फलोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है इसीलिए मैंने यह बात पूछी थी।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात लिखकर दे दें उसका जवाब इनको मिल जाएगा।

Opening of Treasury in Rajound

*291. **Shri Ram Kumar Nagoora :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open treasury in Rajound, if so, the time by which it is likely to be opened ?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : जी हां, राजौंद में एक उप-खजाना खोलने का निर्णय लिया गया है। यह उप-खजाना शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगा।

श्री राम कुमार नगूरा : स्पीकर सर, मेरे राजनीतिक गुरु श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक घोषणा में दो तहसीलें अलेवा और राजौंद बनाई थीं लेकिन मैं सब-ट्रेजरी के सम्बन्ध में लिखने में चूक गया। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अलेवा में सब-ट्रेजरी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अलेवा के बारे में माननीय सदस्य लिखकर दे दें। हम इस बारे में जांच पड़ताल करवा लेंगे। अगर नार्म्ज पूरे होंगे तो अलेवा में भी सब-ट्रेजरी बना देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या : 463

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Regularisation of Unauthorised Colonies

***521 Shri Shadi Lal Batra :** Will the Minister of state for Local Government be pleased to state —

(a) the name and the number of unauthorised colonies, if any, in the Municipal limits of Rohtak City;

(b) whether the facilities of water, sewerage, roads, electricity etc. have been provided to these colonies and since when;

(c) whether House Tax is being charged from the residents of these unauthorised colonies; and

(d) whether the Government has any proposal under consideration to regularise these colonies, if not the reasons thereof ?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) रोहतक शहर की नगरपरिषद् सीमाओं में, संलग्न सूची अनुसार, 68 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं।

(ख) जलापूर्ति, सीवरेज, सड़कें, बिजली इत्यादि की सुविधाएं जो प्रदान की जा रही हैं, की स्थिति संलग्न सूची में दी गई है।

(ग) जी हां, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की व्यवस्था अनुसार इन अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से गृहकर वसूल किया जा रहा है।

(घ) जी हां, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

विवरण

Name and Number of Unauthorised colonies existing in the Municipal Limits of Rohtak City.

Sr. No.	Name of Colony	Facility of water (in%)	Facility of sewer-age (in%)	Facility of roads (in %)	Facility of electricity (in %)
1	2	3	4	5	6
1.	Tilak Nagar	70	70	40	50
2.	Kamal Colony	80	70	45	70
3.	Bharat Colony	70	75	70	55

1	2	3	4	5	6
4.	Chanakya Colony	60	60	75	60
5.	Ram Gopal Colony	15	nil	15	10
6.	Vinay Nagar	nil	nil	nil	nil
7.	Laxmi Nagar	100	100	100	100
8.	Ram Kuti Colony	100	100	100	100
9.	Vikas Nagar	90	90	90	90
10.	Kishan Pura	80	80	80	60
11.	Kailash Colony	70	75	60	55
12.	Chand Nagar	80	80	80	80
13.	Ram Kala Nagar	80	80	80	80
14.	Durga Colony	80	80	80	80
15.	Prem Nagar	60	80	80	80
16.	Azadgarh	35	35	35	35
17.	Sukhpura	35	35	35	40
18.	Kirpal Nagar	70	70	70	70
19.	Gohana Road	nil	nil	35	nil
20.	Chotu Ram Nagar	nil	nil	35	10
21.	Mahabir Colony	80	nil	80	60
22.	Krishna Colony	80	nil	70	70
23.	Guru Nanak Pura	80	80	80	80
24.	Bhagat Singh Colony	80	nil	80	70
25.	Sanjay Nagar	70	70	70	70
26.	Hanuman Colony	70	nil	80	70
27.	Tej Colony	60	60	60	60
28.	Area/Najdeek Sheetla Mandir	40	40	40	40
29.	Sie Dass Colony	60	60	60	60
30.	Shori Kothi Jind Road	70	60	70	70
31.	Najdeek Nehru Colony	30	nil	40	30
32.	Baba Laxman Puri Colony	40	40	40	20
33.	Roop Nagar	50	nil	50	50
34.	Saini Anandpura	50	nil	50	50
35.	Indira Colony & Bye Pass Ke Beech Ka Area	nil	nil	15	40
36.	Sham Colony & Bye Pass Ke Beech Ka Area	nil	nil	30	50
37.	Shastri Nagar	nil	nil	20	10

[श्री सुभाष गोयल]

1	2	3	4	5	6
38.	Industrial Area	nil	nil	30	10
39.	Sainik Colony	nil	nil	30	10
40.	Ram Sarup Nagar Bhiwani Road	20	nil	30	10
41.	Rajender Nagar	40	nil	50	30
42.	Krishan Colony Bus Stand	70	70	70	70
43.	Local Ramlila Ground	80	80	80	80
44.	Har Singh Colony	50	nil	50	50
45.	Vijay Nagar Jhjjar Road	40	nil	45	40
46.	Opposite Sugar Mill Colony	30	nil	30	30
47.	Kamla Nagar (Shastri Nagar)	40	30	45	30
48.	Azad Nagar	50	50	60	50
49.	Ambedkar Colony	40	nil	40	40
50.	Preet Vihar	50	10	40	40
51.	Sri Nagar Colony	60	60	40	30
52.	Geeta Colony	90	100	10	100
53.	Chawla Colony	100	100	100	100
54.	Area Nadeek Jat College	30	30	30	30
55.	Ram Nagar	80	80	80	80
56.	Shastri Nagar	75	75	75	75
57.	Ravi Dass Nagar/ Basti Pura	80	80	80	80
58.	Dani Pura	80	80	80	80
59.	Nand Colony Hissar Road	40	40	50	20
60.	Krishna Colony Najdeek Gaur School	40	nil	60	50
61.	Chunni Pura	60	30	60	70
62.	J.P. Colony	nil	nil	40	30
63.	Kartar Pura	nil	nil	40	30
64.	Adarsh Colony /Dariya Singh Nagar	80	80	80	80
65.	Jasbir Colony	40	nil	40	40
66.	Uttam Vihar	20	nil	20	nil
67.	Vishan Nagar	10	nil	20	nil
68.	Basant Vihar	10	nil	20	nil

श्री शादी लाल बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला है।

My main Question is :—

"Whether the facilities of water, sewerage, roads, electricity etc. have been provided to these colonies and since when ? इसका क्या जवाब है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे जवाब "ख" में यह दिया गया है कि जिन कॉलोनियों को जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क और बिजली की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनकी सूची संलग्न है। ये और क्या सवाल पूछना चाहते हैं ?

श्री शादी लाल बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि कब से ये सुविधाएं देने जा रहे हैं ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये अनाधिकृत कॉलोनियां हैं और इनको रेगुलेराइज करने में टाईम लगता है और फाईनेंस की भी जरूरत होती है। कब से सुविधाएं दी जाएंगी इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता। जो कॉलोनियां पिछले पन्द्रह-अठारह साल से अनाधिकृत चल रही हैं हम यथासंभव जल्द से जल्द उन सभी पुरानी कॉलोनियों के अन्दर ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इन कॉलोनियों को ठीक करके हम उनमें सुचारू व्यवस्था करेंगे।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अनाधिकृत कॉलोनीज का मामला केवल रोहतक में ही नहीं है यह तो पूरे हरियाणा प्रदेश में है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप स्पैसीफिक सवाल पूछें।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं स्पैसीफिक सवाल ही पूछ रहा हूं। जींद में सफीदों रोड पर तीन जगह अनाधिकृत कॉलोनीज हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा प्रदेश में सरकार के आदेशों के खिलाफ अनाधिकृत कॉलोनीज बसाई जाएंगी ? जींद में तीन जगहों पर जो अनाधिकृत कॉलोनीज बसाई जा रही हैं क्या उन पर रोक लगाई जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल रोहतक के बारे में है इसलिए आप रोहतक के बारे में ही पूछें।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा जिला जींद है इसलिए मैं जींद के बारे में ही पूछूंगा। क्या सरकार उन अनाधिकृत कॉलोनीज पर रोक लगाएगी ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आदरणीय ओमप्रकाश चौटाला जी की नीतियों के अनुसार हम वचनबद्ध हैं कि हरियाणा प्रदेश में हम अनाधिकृत कॉलोनीज नहीं बनने देंगे और जो पुरानी कॉलोनीज हैं उनको रेगुलेराइज करने की हमारी पूरी कोशिश होगी।

Providing of computers to legislators

***471 Shri Jarnail Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

[श्री जरनैल सिंह]

(a) the steps being taken by the Govt. to promote the information technology in the State ; and

(b) whether there is a proposal under consideration of the Govt. to provide a computer to legislators ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) श्री मान् जी सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी हां, विधायकों को कम्प्यूटर प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति

1. हरियाणा में पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई है ताकि प्रदेश आधुनिक युग में समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके।

2. इस नीति का उद्देश्य सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवाओं के स्तर में सुधार लाना, लोक केन्द्रित कुशल एवं कम खर्चीला प्रशासन उपलब्ध करवाना, राज्य में आई०टी०साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार करना, आई०टी उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है।

आप्टीकल फाईबर बिछाने (कम्यूनिकेशन बैकबोन) हेतु राइट ऑफ वे नीति (मार्गाधिकार नीति)

3. सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने 'राइट ऑफ वे नीति' मार्गाधिकार नीति की घोषणा की है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गांवों को भरोसेमंद संचार संयोजकता उपलब्ध करवाई जायेगी। आप्टीकल फाईबर बिछाने वाली हर कम्पनी को प्रदेश में 1500 'सूचना किओस्क' एवं सार्वजनिक सुविधा केन्द्र, फ्रेन्चाईज व बिजनैस माडल के रूप में स्थापित करने होंगे जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा तथा इनसे रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 'ज्ञानोदय' योजना

4. हरियाणा सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने हेतु एक वृहद् एवं व्यापक 'ज्ञानोदय' नामक "ग्राम स्वशक्तिकरण योजना" तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गांव में एक "सुविधा एवं सूचना केन्द्र" स्थापित किया जायेगा। जिसके लिये भारत सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी जा रही है। इन सूचना केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता सरकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। इन सूचना एवं सुविधा केन्द्रों के माध्यम से गांव-गांव में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

महिला स्वशक्ति केन्द्र

5. हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां महिला सशक्तिकरण वर्ष में राज्य सरकार द्वारा "महिला स्वशक्ति केन्द्र" स्थापित किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य के सोनीपत जिले में

पायलट बेसिस पर पांच ''महिला स्वशक्ति केन्द्र'' स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इन ''स्वशक्ति केन्द्रों'' के माध्यम से जहां ग्रामीण महिलाओं को ज्ञानपूरक सूचना उपलब्ध होगी वहीं यह ''स्वशक्ति केन्द्र'' पूरे गांव हेतु सूचना केन्द्र का काम करेगा।

इलैक्ट्रॉनिक शासन (ई-गवर्नेंस)

6. सरकार द्वारा जिलों में डी-मैप, डी-नैट की दो अनूठी योजनायें तैयार की गई हैं जिसके अन्तर्गत जिलों के न्यूनतम कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम हेतु मापदण्ड निर्धारित कर दिये गये हैं।

7. डी-नैट के अन्तर्गत जिला स्तर पर एक कम्प्यूटर का नैटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस कम्प्यूटर नैटवर्क के माध्यम से नागरिक आवश्यक जानकारी एवं पब्लिक डोमेन की किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकेंगे।

8. सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जनसाधारण तक इसकी पहुंच सुगम हो सके।

9. राज्य सरकार का निजी क्षेत्र के सहयोग से स्मार्ट कार्ड तकनीकी का प्रयोग ड्राइविंग लाइसैंस, वाहन पंजीकरण तथा राशन कार्ड इत्यादि में करने का प्रस्ताव है ताकि ये सुविधायें सहजता, सरलता व बिना कठिनाई के प्राप्त की जा सकें।

ई-शासन केन्द्र

10. राज्यवासियों को दक्ष एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिये चण्डीगढ़ में 'इलैक्ट्रॉनिक्स शासन केन्द्र' (ई-शासन केन्द्र) स्थापित किया गया है।

11. इस केन्द्र में हरियाणा के माननीय विधायकों को कम्प्यूटर के प्राथमिक प्रशिक्षण के दो कोर्स आयोजित किये जा चुके हैं।

12. हरियाणा में कर्मचारियों के लिये आई०टी० साक्षरता योजना लागू की जा रही है ताकि वर्ष 2002 तक शत-प्रतिशत आई०टी० साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस केन्द्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

13. इस केन्द्र के माध्यम से हिन्दी भाषा में आई०टी० की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है।

14. इस केन्द्र में प्रशिक्षण के अलावा आई०टी० से सम्बन्धित सुविधायें जैसे कि वैब स्टूडियो, एप्लीकेशन डेवलमैंट केन्द्र, डाटा सैन्टर, विडियो कांफ्रेंसिंग स्टूडियो एवं डी.टी.पी. सैन्टर इत्यादि भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

15. इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार की आई०टी० एप्लीकेशंज तथा वैबसाईट्स भी बनाई जा चुकी है तथा यह एप्लीकेशन्ज विभिन्न विभागों, निगमों एवं बोर्डों में इस्तेमाल की जाएंगी।

16. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं निगमों को क्वालिटी सर्विसीज उपलब्ध करवाने के लिये हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र आई०एस०ओ० 9001 हासिल कर लिया है। हॉरट्रान इस प्रमाण-पत्र को हासिल करने वाला राज्य का पहला उपक्रम

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

है तथा सॉफ्टवेयर एवं वैबसाइट के लिये समूचे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम है।

17. राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ भी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा सके। हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सिविल सचिवालय, राजस्व विभाग, खजाना एवं लेखा विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वास्तुकला विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटरीकरण की योजनाओं को हाल ही में तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा निविदायें भी आमंत्रित की जा चुकी हैं।

18. सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय द्वारा खजाना एवं लेखा विभाग हेतु सॉफ्टवेयर का कार्य एन०आई०सी० एवं माइक्रोसाफ्ट के साथ मिलकर पूर्ण कर लिया है। सॉफ्टवेयर की टैस्टिंग भी हो चुकी है। विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग का कार्य आरम्भ है। हार्डवेयर की आपूर्ति की जा रही है। खजाना एवं लेखा विभाग के कम्प्यूटरीकरण की यह पूरे देश में बेमिसाल योजना है। इस योजना में बैंकों को भी भागीदार बनाया गया है ताकि ट्रेजरी से सम्बन्धित बैंक भी अपना कम्प्यूटरीकरण ट्रेजरी कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ कर लें। इससे राज्य सरकार को प्राप्ति एवं निकासी के आंकड़े आन-लाईन मिल सकेंगे।

19. अभिलेख पंजीकरण (डाक्यूमैंट रजिस्ट्रेशन) हेतु राजस्व विभाग द्वारा एन०आई० सी० के सहयोग से "हैरिस" सॉफ्टवेयर तैयार कर राज्य के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी जारी है।

20. राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 कम्प्यूटरों की खरीद का निर्णय लिया गया है। पूरे उत्तरी भारत में इतनी बड़ी संख्या में कम्प्यूटरीकरण का यह सबसे बड़ा प्रयोग है। कम्प्यूटर आपूर्ति हेतु पूर्णतया पारदर्शी प्रणाली अपनाई जा रही है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप आई०एस०ओ० प्रमाणित 9001 एवं 9002 कम्प्यूटर निर्माता ही इसमें भाग ले सकेंगे ताकि आपूर्ति किये जाने वाले कम्प्यूटर गुणवत्ता के आधार पर श्रेष्ठ हों। हर लिया जाने वाला कम्प्यूटर टैस्ट करने के उपरांत ही स्वीकार किया जायेगा। आपूर्ति हेतु जो निर्माता पूर्व निर्धारित अहर्तायें पूर्ण करेंगे उन्हीं की निविदायें विचारार्थ स्वीकार की जाएंगी।

21. राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग भारत सरकार से विशेष प्रयास करके विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई गयी है इस राशि से शिक्षा विभाग, मद्यनिषेध आबकारी एवं कराधान विभाग, खजाना एवं लेखा विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग एवं सचिवालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

22. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया है।

23. विश्व प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कम्पनी माईक्रोसाफ्ट से एम०ओ०यू० किया गया है।

24. डिजीटल सिक्योरिटी में अग्रणी कम्पनी बाल्टीमोर यू०के० के साथ भी हारट्रॉन द्वारा

एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

25. डिजीटल डाक्यूमेंटेशन में न्यूजैन कम्पनी के साथ काम किया जा रहा है।

26. भारत सरकार की संस्था सी–डैक के साथ हिन्दी में सॉफ्टवेयर में काम करने एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विषयों पर सहयोग हेतु एम०ओ०यू० करने के लिये विचार–विमर्श जारी है।

27. सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार विश्व प्रसिद्ध कम्पनी आई०बी०एम०, सनमाईक्रोसिस्टम, ओरेकल, सैनमीडिया, आटोडैस्क इत्यादि के साथ सम्भावनायें तलाश रही है।

28. सरकारी गजट अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नीतियों तथा कार्यक्रम दस्तावेजों तथा लोकोपयोगी सूचनाओं को वर्ष 2001 के अंत तक वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

आई०टी० साक्षरता

29. राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है।

30. सरकार सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये इंटरनैट क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

31. सरकारी स्कूलों और कालेजों में आई० टी० साक्षरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

32. प्रदेश में सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी एवं अनूठी योजना के तहत छठी कक्षा से कम्प्यूटर शिक्षा शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। राज्य के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल व कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य निजी क्षेत्र के सहयोग से किए जाने की व्यवस्था की गई है। आगामी सत्र से कम्प्यूटर शिक्षा विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों एवं कालेजों में शुरू हो जाएगी।

33. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नये कोर्स आरम्भ किये गये हैं।

34. आई०टी० साक्षरता को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम ने फ्रेंचाईज बेसिज पर एक महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है। जिसके तहत ब्लॉक हैडक्वार्टर, कस्बों तथा बड़े गांवों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/हारट्रॉन वर्कस्टेशन/ई–एजूकेशन सैन्टर खोले जाएंगे।

35. आई०टी०साक्षरता के लिये चरणबद्ध योजना वर्ष 2003 तक क्रियान्वित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी के लिये विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में 2360 अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गई हैं।

36. आगामी तीन वर्ष में तकनीकी संस्थाओं में आई०टी० छात्रों की संख्या तिगुनी की जाएगी ताकि बाजार में बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आई०टी० उद्योग

37. सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आयातकों को हरियाणा स्थानीय विकास कर में छूट दी गई है।

38. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एस.टी.पी.आई. के साथ एम०ओ०यू० पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किये जाने हैं। एस.टी.पी.आई. गुड़गांव में दो अर्थ स्टेशन स्थापित करने जा रही है।

39. गुड़गांव में सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क ऑफ इण्डिया द्वारा निर्यात सम्बन्धी सिंगल विंडो सर्विस (एकल खिड़की सेवा) प्रदान की जा रही है।

40. औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई जोकि आई.टी. उद्योग में परिवर्तित होती है तो उसे भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि औद्योगिक इकाई औद्योगिक जोन में स्थापित की जा रही है तो भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति लेनी होगी एवं भूतल निर्मित क्षेत्र, एफ०ए०आर०, ऊंचाई एवं पार्किंग से सम्बन्धित व सभी शर्तें लागू होंगी जोकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर लागू हैं।

41. आई०टी० उद्योग के लिये 250 प्रतिशत एफ०ए०आर० तथा 30 मीटर ऊंचाई की अनुमति दी गई है।

42. आई०टी० यूनिटें तथा साईबर पार्कों अथवा आई०टी०पार्कों में पर्याप्त पार्किंग स्थल के लिये दो मंजिलें बेसमैंट की अनुमति दी जाएगी।

43. सरकार ने आई०टी० क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए आई०टी० यूनिट, आई०टी० पार्क एवं साईबर सिटी इत्यादि की स्थापना के लिए उदार मानदण्ड निर्धारित किए हैं।

44. गुड़गांव के नजदीक साइबर सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है।

45. पंचकूला में मनसा देवी कम्पलैक्स में एक आदर्श सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु 80 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। इस आई०टी० पार्क की स्थापना हेतु यह एक आदर्श स्थल है।

श्री जरनैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री शेर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किस तारीख तक माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर दे दिए जाएंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को ही नहीं पूरे सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्यों को पहले कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वे कम्प्यूटर हैंडल करने में ट्रेंड हो जाएंगे तो बाद में हर माननीय सदस्य को फ्री-औफ कौस्ट एक-एक कम्प्यूटर मिलेगा। यह मेरी आन दि फ्लौर औफ दि हाउस कही गई बात है जिसको

मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि सभी माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर मिलेंगे। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक विधायकगण कम्प्यूटर चलाना अच्छी तरह से सीख नहीं जाएंगे तब तक कम्प्यूटर लेकर क्या करेंगे। कम से कम मेरे और लछमण दास जी के बस का यह सब्जैक्ट नहीं है। यह हमारा फैसला है कि सभी माननीय सदस्यों को एक-एक कम्प्यूटर दिया जाएगा इसीलिए आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि विधायकों को कम्प्यूटर का ज्ञान है। यदि विधायकगण यह चाहते हैं कि कम्प्यूटर चलाने में अनट्रेंड विधायकों को भी कम्प्यूटर दिये जायें तो हम वह भी दे देंगे। हम 90 के 90 माननीय सदस्यों को एक-एक कम्प्यूटर देंगे। यदि विधायकगण यह कहते हैं कि कम्प्यूटर की ट्रेनिंग का समय और बढ़ा दिया जाए तो हम ट्रेनिंग का समय और बढ़ा देंगे ताकि विधायकगण और ट्रेनिंग ले लें।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, ऐसा लगता है चौधरी भजन लाल जी कम्प्यूटर के बारे में ट्रेंड हैं इसीलिए इन्होंने कम्प्यूटर की ट्रेनिंग के लिए दाखिला नहीं लिया। (हंसी)

श्री भजन लाल : मैं तो लोगों को पढ़ाता हूं। (हंसी)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, इधर मुख्य मंत्री जी के पास पूरा स्टाफ है जोकि उनको कम्प्यूटर के बारे में बता देगा और इधर विपक्ष के नेता भी कैबिनेट स्तर के हैं इसलिए इनको पी०ए० मिला हुआ है वह इनको कम्प्यूटर के बारे में बता देगा। लेकिन जो बाकी एम०एल०एज० हैं अगर इनको कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप सभी एम०एल०एज० को एक-एक पी०ए० दे दें वे कम्प्यूटर चला दिया करेंगे। जो सुविधा मुख्य मंत्री जी और विपक्ष के नेता को मिली हुई है वह सुविधा सभी एम०एल०एज० को भी दे दें।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को पहले इंगलिश सिखाने के लिए स्कूल खोला जाए जब ये इंगलिश सीख जाएं उसके बाद इनको कम्प्यूटर दिए जाएं। (हंसी)

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ई-गवर्नेंस में क्या-क्या करने जा रही है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, दुनिया की दौड़ में हरियाणा प्रदेश केवल शामिल ही न हो, बल्कि देश और दुनिया की अगुवाई करे, इस बात को लेकर इन्फर्मेशन टैक्नोलॉजी लागू की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने इस बारे में जो कदम उठाये हैं वे इस प्रकार से हैं—हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से स्मार्ट कार्ड तकनीक का प्रयोग ड्राईविंग लाईसैंस, वाहन पंजीकरण तथा राशन कार्ड आदि में कम्प्यूटराइजेशन करने का प्रस्ताव है ताकि ये सुविधायें सहजता, सरलता व बिना कठिनाई के प्राप्त की जा सकें।

ई-शासन केन्द्र

1. राज्यवासियों को दक्ष एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में 'इलैक्ट्रानिक्स शासन केन्द्र' (ई-शासन केन्द्र) स्थापित किया गया है।

2. इस केन्द्र में हरियाणा के माननीय विधायकों को कम्प्यूटर के प्राथमिक प्रशिक्षण के दो कोर्स आयोजित किए जा चुके हैं।

[श्री राम पाल माजरा]

3. हरियाणा में कर्मचारियों के लिए आई०टी० साक्षरता योजना लागू की जा रही है ताकि वर्ष 2002 तक शत-प्रतिशत आई०टी० साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस केन्द्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. इस केन्द्र के माध्यम से हिन्दी भाषा में आई०टी० की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है।

5. इस केन्द्र में प्रशिक्षण के अलावा आई०टी० से सम्बन्धित सुविधायें जैसे कि वैब स्टूडियो, एप्लीकेशन डेवलपमैंट केन्द्र, डाटा सैन्टर, विडियो कांफ्रेंसिंग स्टूडियो एवं डी.टी.पी. सैन्टर इत्यादि भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

6. इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार की आई०टी० एप्लीकेशन्स तथा वैब साईटस बनाई जा चुकी हैं तथा यह एप्लीकेशन्स विभिन्न विभागों, निगमों एवं बोर्डों में इस्तेमाल की जायेंगी।

7. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं निगमों को क्वालिटी सर्विसीज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र आई०एस०ओ० 9001 हासिल कर लिया है। हारट्रॉन इस प्रमाण-पत्र को हासिल करने वाला राज्य का पहला उपक्रम है तथा सॉफ्टवेयर एवं वैबसाईट के लिए समूचे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम है।

8. राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ भी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा सके। हरियाणा विधान सभा, हरियाणा सिविल सचिवालय, राजस्व विभाग, खजाना एवं लेखा विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वास्तुकला विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटरीकरण की योजनाओं की हाल ही में तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा निविदायें भी आमंत्रित की जा चुकी हैं।

9. सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय द्वारा खजाना एवं लेखा विभाग हेतु सॉफ्टवेयर का कार्य एन०आई०सी० एवं माईक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर पूर्ण कर लिया है। सॉफ्टवेयर की टैस्टिंग भी हो चुकी है। विभाग के कर्मचारियों का ट्रेनिंग का कार्य आरंभ है। हार्डवेयर की आपूर्ति की जा रही है। खजाना एवं लेखा विभाग के कम्प्यूटरीकरण की यह पूरे देश में बेमिसाल योजना है। इस योजना में बैंकों को भी भागीदार बनाया गया है ताकि ट्रेजरी से सम्बन्धित बैंक भी अपना कम्प्यूटरीकरण ट्रेजरी कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ कर लें। इससे राज्य सरकार को प्राप्ति एवं निकासी के आंकड़े ऑन-लाईन मिल सकेंगे।

10. अभिलेख पंजीकरण (डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन) हेतु राजस्व विभाग द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से "हैरिस" सॉफ्टवेयर तैयार कर राज्य के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी जारी है।

11. राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 कम्प्यूटरों की खरीद का निर्णय लिया गया है। पूरे उत्तरी भारत में इतनी बड़ी संख्या में कम्प्यूटरीकरण का यह सबसे बड़ा प्रयोग है। कम्प्यूटर आपूर्ति हेतु पूर्णतया पारदर्शी प्रणाली अपनाई जा रही है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप आई०एस०ओ० प्रमाणित 9001

एवं 9002 कम्प्यूटर निर्माता ही इसमें भाग ले सकेंगे ताकि आपूर्ति किये जाने वाले कम्प्यूटर गुणवत्ता के आधार पर श्रेष्ठ हों। हर लिया जाने वाला कम्प्यूटर टैस्ट करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा। आपूर्ति हेतु जो निर्माता पूर्व निर्धारित अहर्तायें पूर्ण करेंगे उन्हीं की निविदाएं विचारार्थ स्वीकार की जायेंगी।

12. राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग भारत सरकार से विशेष प्रयास करके विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई गई है इस राशि से शिक्षा विभाग, मद्यनिषेध, आबकारी एवं कराधान विभाग, खजाना एवं लेखा विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग एवं सचिवालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

13. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया है।

14. विश्व प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कम्पनी माईक्रोसॉफ्ट से एम०ओ०यू० किया गया है।

15. डिजिटल सिक्योरिटी में अग्रणी कम्पनी बाल्टीमोर यू०के० के साथ भी हारट्रॉन द्वारा एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. डिजीटल डाक्यूमेंटेशन में न्यूजैन कम्पनी के साथ काम किया जा रहा है।

17. भारत सरकार की संस्था सी-डैक के साथ हिन्दी में सॉफ्टवेयर में काम करने एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विषयों पर सहयोग हेतु एम०ओ०यू० करने के लिए विचारविमर्श जारी है।

18. सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विश्व प्रसिद्ध कम्पनी आई०बी०एम०, सनमाईक्रोसिस्टम, ओरेकल, सैनमीडिया, आटोडैस्क इत्यादि के साथ संभावनाएं तलाश रही है।

19. सरकारी गजट अधिसूचनाओं, नियमों विनियमों, परिपत्रों, नीतियों, तथा कार्यक्रम दस्तावेजों तथा लोकोपयोगी सूचनाओं को वर्ष 2001 के अंत तक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

10-00 बजे **श्री जय प्रकाश बरवाला :** अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जय प्रकाश जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (विघ्न)इनका कुछ भी बोला हुआ रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) मिस्टर जय प्रकाश, आप अपने बिहेव को कंट्रोल करें (विघ्न) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न)आप इस तरह की बात न करें। जय प्रकाश जी, यह विधान सभा है (विघ्न) आप विधान सभा में खड़े होकर बोल रहे हैं (विघ्न) पता नहीं आपका लोक सभा का क्या तजुर्बा है, पता नहीं आप वहां से क्या सीख कर आए हैं। आप गलत बिहेव कर रहे हैं। आपको बोलना नहीं आता है। आप बोलने की तमीज सीखिए। (विघ्न) आपको तमीज सीखने की जरूरत है (विघ्न) आप मेरे चैम्बर में आ जाएं मैं आपको तमीज सिखा दूंगा। (विघ्न) डा० सीता राम जी, आप अपना सवाल पूछें।

Sewerage System in Dabwali and Kalanwali

*295 **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[डॉ० सीता राम]

there is any proposal under consideration of Government to improve sewerage system in Dabwali and Kalanwali towns of Sirsa District; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

डबवाली शहर

जी हां, श्रीमान्! डबवाली शहर की सीवरेज प्रणाली के सुधार की योजना पर, कार्य प्रगति पर है जिसकी अनुमानित राशि 241.25 लाख रुपये है।

कालांवाली

जी नहीं, श्रीमान्! फिर भी कालांवाली शहर में सीवरेज की व्यवस्था के लिए 135.00 लाख रुपये का अनुमान अनुमोदित किया गया है जिसका कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो कार्य प्रगति पर हैं वे कब तक पूरे हो जाएंगे, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : स्पीकर सर, जिस प्रकार से माननीय डॉ० सीता राम जी ने यह माना है कि कार्य प्रगति पर है मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि जैसे-जैसे धन मिलता जाएगा काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से केवल एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में कई जगहों पर सीवरेज सिस्टम का काम चालू था और उन पर तकरीबन 90 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप कालांवाली या डबवाली के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें क्योंकि यह सवाल वहीं से सम्बन्धित है। (विघ्न) आप भूमिका न बनाएं केवल सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह : जैसे कि बवानी खेड़ा है, सिवानी है और भी कई इसी प्रकार से गांव हैं जहां पर काफी काम हो चुका था वह सारा पैसा बरबाद हो रहा है। बहुत थोड़े पैसे से वे प्रोजैक्ट कम्पलीट हो जाएंगे। अगर उनको चालू नहीं किया गया तो वे बन्द हो जाएंगे और फिर सरकार का सारा पैसा खराब जाएगा (विघ्न) इसी प्रकार से ऐसी जगहें भी हैं जहां पर 70-70 फीसदी काम हो चुका है लेकिन उसके बाद वहां पर काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : जो सब्जैक्ट मैटर है आप उस पर सवाल पूछें (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन साल से प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभी बिजली पानी का समय नहीं है आप कालांवाली पर सवाल पूछें (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो डबवाली और कालांवाली का है और ये भाई इस समय बिजली की बात कर रहे हैं। जहां पर भी इनकी कोई समस्या है ये लिख कर बताएं जहां 90-90 प्रतिशत काम हो चुका है, ज्यों-ज्यों धन की प्राप्ति होगी उनको पूरा करवा दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सीवरेज की चर्चा इस समय यहां पर चली हुई है और पलवल में यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवर का काम होना है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अगर कालांवाली के बारे में आपने कुछ पूछना है तो पूछिये (विघ्न) आपके कई प्रश्न विचाराधीन हैं जो कि सरकार को भेजे हुए हैं। आप उन पर पूछ लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वैश्चनज़ आपके ही हैं। नैक्सट क्वैश्चन, श्री अमर सिंह जी अपना सवाल पूछें।

Opening of a Sub Depot of Haryana Roadways

***457. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open a sub-depot of Haryana Roadways in Guhla, District Kaithal; and

(b) if so, the time by which the said sub-depot is likely to be opened ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) :

(क) नहीं, श्री मान जी,

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अमर सिंह ढांडे : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि गुहला एक बहुत पुराना सब-डिवीजन है जो कि पंजाब के साथ लगता है और वहां से पंजाब, चण्डीगढ़ और दिल्ली के लिये काफी बसें चलती हैं। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उसके ऊपर दोबारा गौर करें क्यों कि इससे लोगों को पूरा सुख और सुविधा मिल सकेगी। जिस प्रकार परिवहन पूरी स्टेट में तरक्की कर रहा है सभी लोगों को परिवहन का पूरा सुख और सुविधा मिले, क्या मंत्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुये मेरी रिक्वेस्ट पर पुनः गौर करने की कृपा करेंगे?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सब-डिपो और डिपो की बात पूछी है तथा जानना चाहा है कि इनको कैसे बनाते हैं? सर, हम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर डिपो और सब-डिपो बनाते हैं। हरियाणा प्रदेश में 20 डिपोज़ और 17 सब-डिपोज़ हैं। जहां तक विधायक जी ने गुहला-चीका की बात पूछी है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि वहां पर सब-डिपो बनाने के लिए 3 एकड़ 2 कनाल 2 मरले जमीन एक्वायर की गई है। वहां पर रात को आठ बसें ठहरती हैं। वहां पर जितनी बसों की जरूरत है वह ये हमें बता दें। हम वहां पर और बसें दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि सब-डिपो बनाने में ज्यादा खर्च होता है। इसलिए अभी वहां पर सब-डिपो बनाने का कोई विचार नहीं है। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सब-डिपो बनाने का क्या क्राईटेरिया है? सर, असंध सब-डिवीजन है क्या वहां पर सब-डिपो बनाने के लिए विचार किया जा सकता है? असंध चार डिपोज़ से जुड़ा हुआ है। असंध से जीन्द, असंध से करनाल, असंध से कैथल, असंध से पानीपत है, सब 40-45 किलोमीटर के फासले पर पड़ते हैं और

[श्री कृष्ण लाल पंवार]
ये सभी डिवीजन हैं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या असंध में सब-डिपो खोला जा सकता है?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, साथी विधायक ने डिपोज और सब-डिपोज बनाने के क्राईटेरिया के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इसके लिए कोई नार्मज नहीं होते हैं। यातायात की सुविधाओं को देखते हुए, जैसी-जैसी जरूरतें होती हैं उसके हिसाब से ही ये बनाए जाते हैं। असंध में हम सर्वे करवा लेंगे और सर्वे के हिसाब से जो भी पोसीबल होगा वह कर देंगे। (विघ्न) (इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

Vegetable Market in Indri

*397. Shri Bhim Sain Mehta : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Subji Mandi in Indri town; and if so ; the time by which it is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हां, श्री मान जी। स्थल चयन का मामला सरगर्मी से विचाराधीन है। मार्किट कमेटी, इन्द्री द्वारा भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् निर्माण कार्य करने के लिए लगभग दो वर्ष लगेंगे।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : * * * *

श्री जय प्रकाश : * * * * * *

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, जय प्रकाश जी आप अपनी-2 सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर) ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड नहीं किया जाए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप अखबारों में खबर बनने की कोशिश न करें।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब नये मैम्बर हैं और सांगवान साहब, कल जब अभिभाषण पर बोल रहे थे तब इनकी पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनी गई थी। सांगवान साहब, आप अपनी पार्टी के अकेले मैम्बर हैं और आपका जो समय बनता था उससे भी ज्यादा समय आपको बोलने का दिया गया था फिर भी आप अब बोल रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथियों को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आपने अगले प्रश्न का नम्बर बोल दिया है और मिनिस्टर साहब ने उस सवाल का जवाब भी पढ़ दिया है। ये फिर भी बोले जा रहे हैं इनको हाउस के समय का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेहता साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री भीम सेन मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की "हां" के लिए मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ का जिला हैडक्वार्टर है, क्या वहां पर सब्जी मण्डी बनवाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, नई मण्डियों के निर्माण के लिए और पुरानी मण्डियों के विस्तार के लिए इस वर्ष 42.30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आज के दिन गुड़ मण्डी, यमुनानगर, नई सब्जी मण्डी, तावड़ू के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अतिरिक्त अनाज मण्डी ढाण्ड, मडलौडा, नई अनाज मण्डी पुन्हाना, सफीदों, बगाना, बरवाला (पंचकूला), अनाज मण्डी नारायणगढ़, नई सब्जी मण्डी लाडवा, बराड़ा तथा यमुनानगर के विकास कार्य प्रगति पर हैं। जिस मण्डी का माननीय साथी ने जिक्र किया है उसके बारे में भी हम सर्वे करवा लेंगे और अगर जरूरत होगी तो उसको बना दिया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ की सब्जी मण्डी काफी अच्छी मण्डी मानी जाती है लेकिन उसकी चारदीवारी नहीं है इसके लिए पहले से ही एक प्रस्ताव भी सरकार के पास भिजवा रखा है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक इसकी चारदीवारी के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया जाएगा ? यह प्रस्ताव पिछले तीन चार सालों से पड़ा हुआ है। मंत्री जी बताएं कि क्या उस मण्डी के लिए उन्होंने पैसा दिया है या नहीं ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इसके लिए अलहदा से लिखकर दे दें ताकि हम इसके बारे में पता करवा लें। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली सरकारों के समय में हमेशा से विपक्ष के विधायक या आजाद विधायकों के हल्कों से पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता था वैसा अब नहीं होगा। मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 90 कांस्टीच्युएंसीज का दौरा किया था। अब वे जब फिर आपकी कांस्टीच्युएंसी में जाएंगे तो उस समय आप अपनी यह डिमांड रख देना। आपकी बात को जरूर पूरा कर दिया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, चौधरी देवीलाल जी के राज में बहादुरगढ़ में सब्जी मण्डी और चारा मण्डी सैंक्शन की गई थी अब सब्जी मण्डी का काम तो पूरा हो चुका है लेकिन चारा मण्डी अभी तक नहीं बनी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर चारा मण्डी कब तक बना दी जाएगी ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, जिस बात के लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हां भरी हो उसको पूरा न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो उसको जरूर पूरा किया जाएगा।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, दादरी में सब्जी मण्डी के लिए जमीन एक्वायर करके पहले ही दी जा चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दादरी में सब्जी मण्डी का काम कब तक शुरू करवाएंगे ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन को इस बात के लिए अलग से क्वैश्चन देना चाहिए था। कल भी इनके हल्के के विकास के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बातों के लिए 'हां' भरी है।

Construction of Bus Stand at Dhand

*494 **Shri Tejbir Singh :** Will The Minister for Transport be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Dhand ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : (क और ख) हां, श्रीमान जी। ढांड में "ए" टाईप बस क्यू शैल्टर बनाने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

श्री तेजबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ढांड में बस स्टैण्ड कब तक बना दिया जाएगा?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, जैसा मैंने रिप्लाई में बताया कि धन की उपलब्धता होने पर इसको शीघ्र ही बना दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में हमारे मित्र श्री कृष्णपाल गुर्जर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उस समय इन्होंने हमारे सारे जिले को छोड़कर केवल अपनी ही कान्टीच्यूएंसी में हर मोड़ पर या गांव में जहां पर जरूरत भी नहीं थी, क्यू शैल्टर या बस स्टाप बनवा दिए। इस तरह सरकार का पैसा बिना प्लान के बिना सैंक्शन किए हुए लगा दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तरह से मंत्रियों की जो टेंडैंसी रही है क्या वे इन चीजों की जांच करवाएंगे?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार का निर्णय है कि जहां भी लोगों की जरूरत होगी वहां बस क्यू शैल्टर बनाए जाएंगे। बिसला जी ने कहा है कि पिछली सरकार के समय में काफी अनियमितताएं हुई हैं। अगर वह अनियमितताएं बिसला जी के ध्यान में हैं तो वे इस बारे में लिख कर दें, उन अनियमितताओं की जांच करा दी जाएगी।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर नये बस स्टैंड बनाए गए हैं और पुराने बस स्टैंड इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक के पैसे का नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर भिवानी और जुलाना में एक नया बस स्टैंड बनाया गया है और नये अड्डे के बन जाने से पुराने बस अड्डे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। भिवानी वाले पुराने बस अड्डे में दफ्तर बनाया जा सकता है या उस जगह को बेचा जा सकता है जिससे सरकार को पैसा मिल सकता है। क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई प्रकार की अनियमितताएं की थी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके हल्के में इसराना बस स्टैंड है, जहां बस स्टैंड की जरूरत थी वहां बस स्टैंड बनाने की बजाए वहां से हट कर दूसरी जगह बस स्टैंड बना दिया गया जहां आज कोई भी बस नहीं जाती है। हमारी सरकार का निर्णय है कि जहां भी बस स्टैंड बनेंगे वह जरूरत के मुताबिक बनेंगे। जहां तक भिवानी बस स्टैंड का सही यूज हो सके ऐसी कार्यवाही हम जरूर करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने इस प्रश्न से सम्बन्धित अपने जवाब में "ए" टाईप बस क्यू शैल्टर की बात कही है, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सरकार के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी यहां पर यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बस स्टैंड बनवाने के लिए बस स्टैंड की लागत सहित कितनी कैटेगरीज हैं और बस क्यू शैल्टर की कितनी टाइप हैं ताकि हम जरूरत के मुताबिक यथायोग्य निर्णय करने में सक्षम हो सकें ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, बस क्यू शैल्टर ए, बी, सी तीन टाइप के बनते हैं 'ए टाइप' बस क्यू शैल्टर पर 3 लाख 30 हजार रुपये खर्च होते हैं, 'बी टाईप' बस क्यू शैल्टर पर 2 लाख 20 हजार रुपये खर्च होते हैं व 'सी टाइप' बस क्यू शैल्टर पर 55 हजार 800 रुपये खर्च होते हैं।

Constitution of Municipal Committees of Haily Mandi and Pataudi

*426 **Shri Rambir Singh :** Will the Minister of State for Local Govt. be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute the Municipal Committee of Haily Mandi and Pataudi town; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही है।

(ख) 'क' के दृष्टिगत , इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री राम बीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह किया था कि हेली मंडी और पटौदी को मिलाकर कोई नगरपालिका बनाने जा रहे हैं ये अलग-अलग की बात नहीं थी।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैंने इसका जवाब ये दिया है कि अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि जनगणना का कार्य चल रहा है और जनगणना कार्य पूर्ण होने के पश्चात् हम सारे हरियाणा प्रदेश में जहां-जहां नगरपालिका बन सकेंगी इसके बारे में वायब्लिटी देखकर विचार करेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर महोदय, कनीना की म्यूनिस्पिल कमेटी का केस हाई कोर्ट में दायर हुआ था और हाई कोर्ट ने उस म्यूनिस्पिल कमेटी को दोबारा बहाल करने के आदेश दिए थे। यह आदेश किए हुए 3-4 महीने हो गये हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या उस आदेश की पालना करते हुए कनीना की म्यूनिस्पिल कमेटी को पुनः बहाल करने का काम सरकार के विचाराधीन है और यदि 'हां' तो यह काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के आदेश की उल्लंघना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चूंकि जनगणना का कार्य प्रगति पर है और सरकारी अमला इसमें व्यस्त है। जनगणना कार्य इसी महीने पूरा हो जायेगा उसके बाद सरकार दूसरे मुद्दों पर विचार करेगी।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा विशेष चर्चा का है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहूँगा कि कुछ म्यूनिस्पिलिटीज तोड़ने का जो निर्णय लिया गया था वह निर्णय इस दृष्टिकोण के तहत लिया गया था कि जो कमेटीज 15 हजार की आबादी से कम की हैं उनको तोड़ दिया जाये। यह निर्णय इस कारण नहीं लिया गया था कि हेली मण्डी और कनीना की कमेटीज अपनी आमदनी से अपना खर्चा चलाने में सक्षम नहीं थी। कुछ गांव ऐसे भी थे जिनकी आबादी 15 हजार से ऊपर थी अगर इन कमेटीज को रखा जाता तो उन गांवों को इस बात का ऐतराज होता। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद इस पर बहुत सोच समझकर निर्णय लिया जायेगा और सारे सदन को विश्वास में लेकर यह निर्णय किया जायेगा। हाई कोर्ट के निर्णय की पालना अवश्य की जायेगी। संविधान और ज्यूडिशरी का सम्मान हरेक को करना पड़ता है और यह सरकार भी ऐसा ही करेगी। अन्यथा ज्यूडिशरी स्वयं ऐसा करवा लिया करती है।

Setting up of 33 KV Sub-station at Kakrod

***303. Shri Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 KV sub-station at Village Kakrod in Uchana Constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) जी नहीं उचाना निर्वाचन क्षेत्र में गांव काकरोद में एक नया 33 के०वी० उप केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री भाग सिंह : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उचाना हल्के के गांव काकरोद में 33 के०वी० का सब स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :—स्पीकर सर, गांव काकरोद को बिजली की सप्लाई दिनौदा और उचाना के 33 के० वी० सब स्टेशन से दी जाती है। दुर्जन पुर गांव के 11 के० वी० सब स्टेशन का विभाजन करके काकरोद गांव को पूरी वोल्टेज दी जायेगी।

श्री भाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जरूरत के मुताबिक 66 के०वी० के और 33 के०वी० के कितने सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, चूंकि माननीय सदस्य का प्रश्न स्पेस्फिक है। इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने 9 नये सब स्टेशन और 71 सब स्टेशनों की आगमैंटेशन की है। जहां-जहां वोल्टेज में कमी की शिकायतें मिलती हैं उनका सर्वे करवाकर नई प्रोपोजल्स मंजूर की जाती है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव महोदय

को बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूंसी के अन्दर एक बड़ा गांव है बलाह। वहां 11 के०वी० का सब-स्टेशन है। उस गांव के लोग 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में मुख्य मंत्री महोदय के सामने खुले दरबार में पेश हुए थे और मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी समस्या हल करने का आश्वासन दिया था। क्या संसदीय सचिव महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उस गांव में जो 4 एम० वी०ए० के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, क्या उनको 6 एम०वी०ए० तक एक्सटैंड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में जिन कामों का आश्वासन दिया होगा, उन कामों को फ्रंटीयर मेल की स्पीड से पूरा किया जाएगा। जिस तरह से एक्सप्रैस गाड़ी चलती है उतनी तेजी से उन कामों को पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कृष्ण लाल पंवार जी कोई स्पैसीफिक नोटिस देंगे तो वहां के काम की स्थिति के बारे में बता दिया जाएगा।

Opening of Dispensary at village Ranjitpur

*380 **Shri Balwant Singh :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is no Dispensary in village Ranjitpur in Sadhaura Constituency where a large rural area is adjacent to it; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Dispensary in the said area?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) जी हां

(ख) जी नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय नीति के अनुसार नार्म्ज पूर्ण नहीं करता।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि रणजीतपुरा गांव में एक प्वायंट है जो हिमाचल से जुड़ता है वहां 10-12 किलोमीटर के एरिया में कोई अस्पताल या डिस्पैंसरी नहीं है इसलिए नार्म्ज में रिलैक्सेशन देकर काम बन सकता है और इससे लोगों को लाभ मिल सकता है।

डा० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि रणजीतपुरा गांव में डिस्पैंसरी खोलने की कोई भी योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और 'ख' में इसलिए नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत नार्म्ज पूरे नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस गांव की आबादी 351 है और कुल 52 घर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत हमारा जो क्राइटेरिया है उसके तहत इस गांव को मुगलवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ जोड़ा हुआ है जो यहां से 10 किलो मीटर दूर है। वहां हमारे दो ए०एन०एम०, सोशल वर्कर आदि काम कर रहे हैं। इस गांव की देख रेख के लिए अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो उन दोनों की दो दिन के लिए ड्यूटी उस गांव में लगा सकते हैं ताकि

वहां के लोगों के स्वास्थ्य की देख रेख हो सके।

डा० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बलवन्त सिंह जी ने रणजीतपुरा गांव में डिस्पैंसरी खोलने का सवाल रखा है वह बहुत जरूरी है। वहां आस-पास कोई डिस्पैंसरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां यह डिस्पैंसरी जरूरी खुलवाई जाए।

(इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हमारे साल्हावास हल्के में कोसली गांव है वहां एक पी.एच.सी. है। उस गांव की आबादी 5000 के लगभग है। क्या उस पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

Mr. Speaker : This is not relevant question. Please sit down.

Dr. Jai Parkash Sharma : Hon'ble Speaker, Sir, through you I would like to inform the Hon'ble Health Minister that opening of dispensaries does not require any national policy. These are opened for the health of the people. Prof. Sampat Singh ji has already mentioned that "Health is Wealth". So, I would request that this portion should be deleted from the statement of the Health Minister that it requires national policy, whereas it is not required.

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Opening of a 50 Bed Hospital at Taraori

***277. Shri Dharam Pal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Hospital of fifty beds at Taraori in District Karnal; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said hospital is likely to be completed ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के कारण इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Repair of Road

***544. Shri Dina Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road from Lamba Kheri to Dhanauri; if so, the time by which the above said road is likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हां। मुरम्मत का कार्य अगले वित्त वर्ष के दौरान, मार्च, 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा।

To set up Sugar Mill

***302. Shri Pawan Kumar :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill in Jyotisar-Pehowa area; if so, the detail thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) : जी हां, श्रीमान। पेहवा क्षेत्र में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रस्ताव के गुण दोषों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद लिया जाएगा।

Education Standard in Harayna

***289. Ram Kishan Fauji :** Will the Minister of State for Education be pleased to state —

(a) whether the Govt. is aware of the fact that Educational standard in Haryana is going down day by day, if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the standard of Education; and

(b) the amount earmarked for Primary, Middle, High and College level education during the present year ?

Minister of State for Education (Ch. Bahadur Singh) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The Govt. is aware of the need to constantly improve quality of education. A number of steps have been taken to raise the standard of education in the State including formulation of an innovative Education policy-2000. Steps taken to raise the standard of education are :—

1. Teaching of English has been introduced from class-I during academic session 2000-2001.

2. In-service teachers programme has been strengthened.

3. Teaching-learning material in the school especially in the seven districts of District Primary Education Programme (DPEP) have been prepared and given to the teachers and students. Integrated education

[चौ० बहादुर सिंह]

for the disabled children have also been given in all the districts of DPEP.

4. Distance Education Programmes have been organised to update the knowledge of the teachers in the State.

5. SCERT and DIETs have been strengthened by providing library books, good staffing and other research material etc.

6. Other incentives like Mid-day-meal, Book Bank Scheme, Innovative Programmes, Attendance Prize, Free uniform, Free stationery, Free text-books, Special attendance allowance to Nomadic Tribe children, Pre-matric Scholarship, stipends to students belonging to De-notified Tribes etc. are made available to the school children.

7. Other infrastructure like construction of school buildings, class-rooms, boundary-wall, separate toilets for boys and girls, provision of drinking-water etc. are being provided.

8. To cope with the demand of Information Technology, Computer Education is being started in Government Schools from Class-VI.

9. As per decision in New Education Policy the control of Government Primary Schools is being transferred to Panchayati Raj Institutions for overall improvement.

10. 2119 posts of C & V teachers have been filled by Departmental Committee, 3153 posts of Masters and 842 posts of Lecturers are under process and would be filled soon as and when recommended by Haryana Staff Selection Commission.

11. The State Govt. has sanctioned a total number of 204 posts of teachers, 60 clerks and 289 Class-IV for 151 schools upgraded from Primary to Middle, 69 from Middle to High and 38 High to Senior Secondary level. The Financial sanction for these schools has been given by the State Government.

12. Supervision has been strengthened and DEOs have been asked to do supervision frequently.

13. Monthly tests and quarterly tests are being held in every school and the progress of each student is being conveyed to the parents and the results of quarterly examination are being reviewed in quarterly meetings of Parents—Teachers Associations.

14. Interaction between the parents and class teacher is organised on fixed days in every school to encourage involvement of parents and to create positive mutual relationship between community and the school.

15. Training of teachers is being organised at district level for four

subjects i.e. English, Maths, Science and Geography so that teachers remain well equipped with latest technology.

16. A uniform pattern of Annual examination in the 6th, 7th, 9th & 11th classes has been introduced on the pattern of board examination for 8th, 10th & 12th classes respectively.

17. To ensure comprehensive & continuous evaluation, system of adding the marks of quarterly examination to the total marks in the Annual examination in the 6th, 7th, 9th, & 11th classes has been introduced.

18. A system of awarding cash prizes to the students of Govt. Schools who obtain Ist ten positions in the Sr. Secondary, Matric & Middle Examinations in the Districts among Govt. schools have been started in 1994 and cash prizes are given on Children day.

19. Inter class competitions have been introduced in all schools with a view to give an opportunity to each student to participate in some activity or the other, students showing good performance in various fields are honoured and awarded at the school annual functions.

20. Science exhibition, Handwriting competitions, On-the-spot Painting competitions, Essay writing competitions are conducted at Division, District and State level every year.

21. "Cleanliness Competitions" for Govt. Middle School at Sub-Divisional level are organised and the Schools which stand Ist, IInd, and IIIrd are awarded Rs. 2000/-, Rs. 1500/- and Rs. 1000/- respectively.

22. System of annual day function in the schools has been started and this has evoked a tremendous response from the parents.

23. An annual Calendar of all academic and co-curricular activities has been drawn up for all Government Schools.

24. The State Award money which was given to State Awardee teachers has been doubled. It was Rs. 2500/- and now is made Rs. 5000/-.

25. Sixteen posts of Principals and 200 posts of Headmasters have been filled up by way of direct recruitment.

26. Computer Education is being introduced as an optional subject in Govt. Colleges of the State from the coming academic session.

27. Two new Govt. Colleges namely Govt. College for Women, Sampla and Govt. College, Badli have been opened during the year 2000-2001.

28. With a view to removing disparity of lecturers in rural and urban areas, about 180 lecturers have been posted in rural colleges as a part of rationalization.

[चौ० बहादुर सिंह]

29. Girls Education is being encouraged particularly in the rural areas. A girls college has been opened at Sampla.

30. Permission has been given to 40 aided Private Colleges for starting Job-Oriented Courses.

31. Women cells have been established in 164 Colleges in the State to enhance gender awareness.

32. Meritorious students of colleges of rural and urban areas have been honoured at State Level Function to encourage the pursuit of excellence.

33. In-service training course has been specially designed and run to impart managerial skills to the Principals.

34. 300 Govt. College lecturers are being required to provide adequate faculty in colleges.

(b) The following amount has been earmarked during the current financial year.

Primary Education	Rs. 33,895.73 lacs
Secondary Education	Rs. 73,395.91 lacs
Higher Education	Rs. 23,233.33 lacs

Lining of Malleka Minor

***360 Shri Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the lining of Malleka Minor; if so, the time by which the said work is likely to be started/completed ?

मुख्य मंत्री (ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान जी, यह कार्य मौके पर शुरू कर दिया गया है और 30.9.2001 तक पूरा होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Releasing of land

11. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state the districtwise total acreage of land, if any, released to its original owners in the State during the period from April, 1995 to 31st January, 2001, if so, the reasons thereof ?

Town & Country Planning Minister (Shri Dhir Pal Singh) : Yes Sir, Total land measuring 335.26 acres has been released to the original land owners during the period from April, 1995 to 31.01.2001, district-wise details of which are as follows :—

Sr. No.	District	Acres
1.	Panchkula	7.56 Acres
2.	Yamuna Nagar	0.19 Acre
3.	Karnal	3.33 Acres
4.	Panipat	2.84 Acres
5.	Faridabad	85.06 Acres
6.	Sonepat	1.22 Acres
7.	Rohtak	9.02 Acres
8.	Jhajjar	11.73 Acres
9.	Hissar	3.42 Acres
10.	Gurgaon	173.05 Acres
11.	Rewari	34.62 Acres
12.	Narnaul	3.22 Acres
	Total	335.26 Acres

The detail of released land togetherwith reasons is attached at Annexure -"A".

The year-wise detail of released land from 1995 onwards is as under :-

Year	Name of District		Land Released in Acres
1995	Panchkula		1.30
	Panipat		0.16
	Gurgaon		0.28
	Hisar		3.00
	Faridabad		14.02
		Total	18.76
1996	Panchkula		0.01
	Karnal		0.33
	Rewari		1.54
	Gurgaon		49.35
		Total	51.23
1997	Panchkula		2.03
	Panipat		1.32

[श्री धीर पाल सिंह]

	Gurgaon		1.34
	Narnaul		1.07
	Faridabad		19.97
	Jhajjar		11.73
	Sonipat		1.22
		Total	38.68
1998	Karnal		3.00
	Gurgaon		82.70
	Faridabad		39.04
		Total	124.74
1999	Panchkula		3.62
	Panipat		1.33
	Rewari		20.78
	Gurgaon		10.69
	Narnaul		0.25
	Faridabad		0.83
	Rohtak		9.02
		Total	46.52
2000	Panchkula		0.63
	Faridabad		11.20
	Yamuna Nagar		0.19
	Rewari		12.30
	Gurgaon		28.69
	Narnaul		1.90
	Hissar		0.42
		Total	55.33
2001			Nil
		G. Total	335.26

THE TOTAL LAND RELEASED FOR THE ORIGINAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL 1995 TO 31-1-2001 DISTRICT REWARI.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Areas released	No.& Date of release order	Ground of release
1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
1.	Pardeep S/o Sh. Tej Singh etc.	Sec.4A&6 Part Dharudhera	1K-1M	2075-77/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court order
2	Smt. Ratni Devi Wd/o Sh. Tej Singh etc.	-do-	0K-6M	2079-81/22-3-99	-do-
3.	Shamsher Singh, Jaipal, Inder Pal S/o Sh. Dalip Singh etc.	-do	1K-2M	2083-85/22-3-99	-do-
4.	Jitender Singh, Jai Singh, Ram Singh S/o Sh. Inder Pal etc.	-do-	1K-0M	2087-89/22-3-99	-do-
5.	Sheo Rattan S/o Sh. Bhoop Singh etc.	-do	8K-0M	2091-93/22-3-99	-do
6.	Smt. Vishal Devi W/o Sh. Vikram Singh etc.	-do	7K-7M	2095-97/22-3-99	-do-
7.	Jitender Singh, Jai Singh, Ram Singh S/o Sh. Inder Pal etc.	-do	0K-2M	2099-101/22-3-99	-do-
8.	Shivdeep-Davees SS/o Sheo Rattan Singh etc.	-do-	5K-1M	2103-05/22-3-99	-do-
9.	Ram Chand S/o Sh. Bhoudh Ram etc.	-do-	1K-1M	2051-53/22-3-99	-do-
10.	Shemsher Singh S/o Sh Dilip Singh	-do-	1K-2M	2315-18/22-3--99	-do-
11.	Sheo Rattan etc.	-do-	1K-9M	2319-21/22-3-99	-do-
12.	Rohtash, Omparkash, Dharambir Pish Ram, Ram Parshad S/o Nonda Ram etc.	-do-	28K-9M	2067-69/22-3-99	-do-
		Total	7.00 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
13.	Raja Ram, Boda, Banwari, Iswar SS/o Sh. Ganga Ram etc.	Sec.4A &6 Part Dharuhera	4K-8M	2323-25/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court Order
14.	Din Dyal S/o Ganshi Lal S/o Sh. Har Narain.	-do-	0K-12M	2327-29/22-3-99	-do-
15.	Gulab Singh, Partap Singh SS/o Sh. Phool Singh etc.	-do-	3K-16M	2331-33/22-3-99	-do-
16.	Smt. Gindori Devi Wd/o Budh Ram etc.	-do-	0K-7M	2335-37/22-3-99	-do-
17	Chela Ram S/o Gana Ram etc.	-do-	0K-7M	2339-41/22-3-99	-do-
18.	Sube Singh, Udey Ram, Mahinder Singh Vijinder Singh, Dharam Singh, Ramesh Singh SS/o Sh. Bhag Mal etc.	-do-	1K-2M	2343-45/22-3-99	-do-
19.	Jahria, Parbhu, Tara Chand, Rattan Singh, Pisran & Smt. Ginddori D/o Sh. Ramji Lal etc.	-do-	0K-6M	2347-49/22-3-99	-do-
20.	Smt. Ram Kaur Wd/o Sh. Man Singh etc.	-do-	0K-5M	2351-53/22-3-99	-do-
21.	Dharambir S/o Sh. Suresh Chand etc.	-do-	0K-2M	2355-57/22-3-99	-do-
22.	Smt. Manjula W/o Sh. Rishi Pal etc.	-do-	0K-7M	2055-57/22-3-99	-do-
23.	Smt. Santra Devi W/o Sh. Ram Avtar etc.	-do-	0K-15M	2359-61/22-3-99	-do-
24.	Smt. Kamlesh Kumari W/o Sh. Mohan Jatoai S/o Sh. Dina Nath	-do-	0K-6M	2363-65/22-3-99	-do-
25.	Smt. Ranbir Singh S/o Sh. Hoshiar Singh	-do-	0K-5M	2367-69/22-3-99	-do-
26.	Smt. Bhagwanti W/o Sh. Jagan Nath S/o Sh. Janki Dass.	-do-	0K-7M	2059-61/22-3-99	-do-
27.	Smt. Sumitra Devi W/o Sh. Surender Kumar etc.	-do-	0K-7M	2063-65/22-3-99	-do-
28.	Hukam Chand S/o Sh. Bihari etc.	-do-	1K-17M	2371-73/22-3-99	-do-
29.	Kalish Chand S/o Sh. Radhey Sham etc.	-do-	2k-0M	2375-77/22-3-99	-do-
		Total	2.04 Acres		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
30.	Om Parkash, Parbhu Dayal, Suresh Kumar SS/o Sh. Shiv Charan etc,	Sec. 4A & 6 Part Dharuhera	0K-17M	2379-81/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court order
31.	Sarpanch Gram Dharuhera	-do-	1K-12M	2383-85/22-3-99	-do-
32.	Sanjay S/o Sh. Shemsher Singh etc.	-do-	0K-4M	2387-89/22-3-99	-do-
33.	Shamsher S/o Sh. Dalip Singh etc.	-do-	2K-8M	2107-9/22-3-99	-do-
34.	Raju S/o Sh. Tej Singh etc.	-do-	2K-1M	2111-13/22-3-99	-do-
35.	Pardeep S/o Sh. Tej Singh etc.	-do-	0K-5M	2115-17/22-3-99	-do-
36.	Jitender Singh, Jai Singh, Ram Singh SS/o Sh. Inder Pal Singh etc.	-do-	0K-6M	2119-21/22-3-99	-do-
37.	Jitender Singh, Jai Singh, Ram Singh SS/o Sh. Inder Pal Singh etc.	-do-	0K-10M	2123-25/22-3-99	-do-
38.	Sheo Rattan Singh S/o Sh. Bhoop Singh	-do-	16K-16M	2129-31/22-3-99	-do-
39.	Pawan Kumar, Parveen Kumar SS/o Vikram	-do-	0K-17M	2132-34/22-3-99	-do-
40.	Shiv Deep Devees SS/o Sh. Shiv Rattan	-do-	1K-12M	2135-37/22-3-99	-do-
41.	Inder Pal Singh etc. C/o Virender Singh S/o Sh. Ram Chander etc.	-do-	0K-4M	2311-13/22-3-99	-do-
42.	Rani Hukam Kaur Wd/o Bhoop Singh S/o Ganpat etc.	-do-	1K-12M	2139-41/22-3-99	-do-
43.	Shiv Deep Singh, Devees Kumar SS/o Sh. Shiv Rattan Singh etc.	-do-	1K-6M	2143-45/22-3-99	-do-
44.	Smt. Ram Devi W/o Sh. Ram Chand etc.	-do-	0K-11M	2043-45/22-3-99	-do-
45.	Lalit Kumar, Prem Sagar, Vivek Kumar SS/o Sh. Ram Chander.	-do-	0K-9M	2047-49/22-3-99	-do-
46.	Shiv Deep Singh, Devees Kumar SS/o Sh. Shiv Rattan etc.	-do-	4K-2M	2147-49/22-3-99	-do-
		Total	4.20 Acres		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
47.	Smt. Vishal Devi Wd/o Sh. Vikram Singh S/o Sh. Bhoop Singh.	Sec. 4A & 6 Part Dharuhera	9K-16M	2154-56/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court order
48.	Shemsher Singh S/o Dalip Singh	-do-	1K-18M	2158-60/22-3-99	-do-
49.	Jitender Singh, Jai Singh, Ram Singh SS/o Inder Pal	-do-	4K-7M	2162-64/22-3-99	-do-
50.	Smt. Shanti Devi W/o Sh. Tara Chand S/o Sh. Ram Ji Lal etc.	-do-	12K-1M	2166-68/22-3-99	-do-
51.	Rakesh S/o Sh. Daya Chand etc.	-do-	0K-8M	2170-72/22-3-99	-do-
52.	Raj Kumar S/o Sh. Rangbir etc.	-do-	0K-13M	2174-76/22-3-99	-do-
53.	Smt. Santosh Kumari W/o Sh. Suresh Chand	-do-	0K-8M	2178-80/22-3-99	-do-
54.	Lakhi Chand Bhu Devdutt SS/o Sh. Khusi Ram	-do-	0K-7M	2181-84/22-3-99	-do-
55.	Rameshwar S/o Sheo Karan S/o Sh. Ami Lal	-do-	0K-3M	2186-88/22-3-99	-do-
56.	Ved Pal S/o Sh. Sultan Singh S/o Bhoji Ram	-do-	0K-11M	2190-92/22-3-99	-do-
57.	Ranglal S/o Sh. Sohan Lal etc.	-do-	0K-6M	2193-96/22-3-99	-do-
58.	Ram Kishor S/o Sh. Shimbu Dayal	-do-	0K-9M	2198-2200/22-3-99	-do-
59.	Madan Lal / Rameshwar Dayal, Banwari Lal SS/o Sh. Gansi Lal etc.	-do-	0K-11M	2202-04/22-3-99	-do-
60.	Smt. Rewati W/o Sh. Lakhmi Chand S/o Shiv Narain.	-do-	1K-0M	2206-08/22-3-99	-do-
61.	Smt. Veena W/o Sh. Lal Chand S/o Sh. Nand Kishor.	-do-	0K-10M	2210-12/22-3-99	-do-
62.	Smt. Sudha W/o Sh. Ajit Kumar etc.	-do-	0K-18M	2214-16/22-3-99	-do-
63.	Suresh Chand S/o Ami Chand	-do-	0K-11M	2218-20/22-3-99	-do-
64.	Ram Naresh s/o Sh. Banwari S/o Mahadev Parsad	-do-	0K-11M	2222-24/22-3-99	-do-
		Total	4.43 Acres		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
65.	Sheo Ram S/o Sh. Heera etc.	Sec. 4A &6 Part Dharuhera	0K-6M	2227-29/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court orders
66.	Laxmi Narain S/o Sh. Ram Kumar S/o Sh. Matadin.	-do-	0K-7M	2231-32/22-3-99	-do-
67.	Jagdish Chand S/o Sh. Kanshi Ram	-do-	1K-0M	2234-36/22-3-99	-do-
68.	Smt. Shene Lata W/o Sh. Kumat Parsad Smt. Krishna Devi	-do-	0K-5M	2239-40/22-3-99	-do-
69.	Smt. Bharpai W/o Sh. Tota Ram etc.	-do-	3K-3M	2242-44/22-3-99	-do-
70.	Smt. Shanti Devi W/o Sh. Tara Chand etc.	-do-	1K-3M	2246-48/22-3-99	-do-
71.	Smt Mune Devi W/o Sh. Ashok Kumar etc.	-do-	0K-11M	2250-52/22-3-99	-do-
72.	Sanjay S/o Sh. Lajpat Ram S/o Vidhya Rattan	-do-	0K-17M	2254-56/22-3-99	-do-
73.	Smt. Manju W/o Sh. Mahinder Kumar etc.	-do-	0K-5M	2258-60/22-3-99	-do-
74.	Smt. Maya W/o Sh. Jai Gopal etc.	-do-	0K-6M	2262-64/22-3-99	-do-
75.	Mangat Ram Chatrimal SS/o Sh. Chathermal	-do-	0K-4M	2267-69/22-3-99	-do-
76.	Smt. Imarti Devi W/o Sh. Rama Nand etc.	-do-	0K-12M	2270-72/22-3-99	-do-
77.	Sh. Ram Mehar-Udeyvir Singh, Rajbir SS/o Sh. Khusi Ram etc	-do-	1K-2M	2274-76/22-3-99	-do-
78.	Sh. Subash Chand S/o Sh. Lal Chand etc.	-do-	0K-6M	2278-80/22-3-99	-do-
79.	Om Parkadh S/o Sh. Rangbir Singh	-do-	0K-8M	2282-84/22-3-99	-do-
80.	Bhartu-Parbhu Pish Ran, Jeeva Ram S/o Sh. Sukh Lal etc.	-do-	0K-16M	2286-88/22-3-99	-do-
		Total	1.44 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
81.	Smt. Sarti, Banto D/o Sh. Sawant Ram, Badlu Ram etc.	Sec.4A & 6 Part Dharuhera	1K-0M	2289-92/22-3-99	Due to Hon'ble Supreme Court orders
82.	Sanpat, Mani SS/o Sh. Patram etc.	-do-	1K-0M	2294-96/22-3-99	-do-
83.	Gopi Chand S/o Lali D/o Bhagwani W/o Sh. Parbhati etc.	-do-	2K-0M	2298-2300/22-3-99	-do-
84.	Matta Din etc, Gori Shanker S/o Thandi & Kundan etc.	-do-	4K-0M	2302-04/22-3-99	-do-
85.	Shiv Rattan Singh S/o Sukantla Devi D/o Rani Hukam Kaur W/o Sh. Bhoop Singh.	-do-	4K-17M	2305-8/22-3-99	-do-
86.	Sarpanch Gram Dha, Dharuhera	-do-	0K-9M	2305-9/22-3-99	-do-
87.	Omkar Mal & Om Parkash	Sec.3 Part II, Rewari	2K-6M	210/9-1-96	Due to Court case.
88.	Smt. Krishna	-do-	10K	2864/24-4-96	Due to existing construction before U/S-4
89.	Smt. Sumitra Devi	Sec-4, Rewari	1K-1M	5423/7-8-2000	Due to Hon'ble High Court orders.
90.	Panna Lal S/o Sh. Lachman	-do- }		-do-	-do-
91.	Ram Chander S/o Sh. Lachman	-do- }	0K-9M	-do-	-do-
92.	Sunder Lal S/o Sh. Lachman	-do- }		-do-	-do-
93.	Muni Ram S/o Sh. Rati Ram	-do-	0K-2M	-do-	-do-
94.	Babu Ram S/o Sh. Duli Chand	-do-	0K-10M	-do-	-do-
95.	Ramji Lal S/o Sh. Mehar Singh	-do-	0K-16M	-do-	-do-
96.	Vijay Kumar S/o Sh. Amar Singh etc.	-do-	12.5 M	-do-	-do-
		Total	3.65 Acres		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri—				
97.	Ram Kala S/o Sh. Murli etc.	Sec. 4, Rewari	0K-8M	5423/7-8-2000	Due to Hon'ble High Court orders
98.	Dass Ram S/o Sh. Ishwar Dass	-do-	0K-6M	-do-	-do-
99.	Shish Ram S/o Sh. Girdhari etc.	-do-	1K-0M } 0K-18M }	-do-	-do-
100.	Smt. Agayawati W/o Sh. Dhar Pal etc	-do-	78K-13M	-do-	-do-
101.	Banwari Lal etc.	-do-	5K-8M	-do-	-do-
102.	Hakam Singh etc.	-do-	12K-8M	-do-	-do-
103.	Anni Lal S/o Sh. Badlu Ram etc.	-do-	1K-0M	-do-	-do-
104.	Ram Sarup S/o Sh. Chunna	-do-	0K-17M	-do-	-do-
105.	Sultan Singh S/o Sh. Chunna	-do-	0K-18M	-do-	-do-
106.	Gella Ram S/o Sh. Ramji Lal	-do-	1K-6M	-do-	-do-
		Total	11.86 Acres		
		B.F	22.76 Acres		
		G. Total :	34.62 Acres		

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGINAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001 URBAN ESTATE, NARNAUL.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Ground of release
1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
1.	Kalawati	Sec.-1,Narnaul	500 Sq.yd.	261/13-1-97	Due to existing construction before U/S-4 notified.
2.	Rai Gulab Singh	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
3.	Surender Singh S/o Suraj Bhan	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
4.	Krishna Devi W/o Bhoop Singh	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
5.	Ravinder Singh S/o Naresh Singh	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
6.	Om Parkash S/o Mukh Ram	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
7.	Ranbir Singh S/o Khushi Ram	-do-	210 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
8.	Babli Devi & Ram Chander	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
9.	Bhim Singh S/o Hardwari Lal	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
10.	Mewa Singh	-do-	150 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
11.	Mata Deen, Prithvi Singh	-do-	300 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
		Total :	0.69 Acre		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
12.	Rohtash	Sec.-1,Narnaul	240 Sq.yd.	1216/28-2-97	Due to existing const. before U/S-4 Notified
13.	R.K. Punia	-do-	400 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
14.	K.K Yadav	-do-	1200 Sq.yd.	1216/28-2-97	-do-
15.	Ram Kumar, Narnaul	-do-	391.11Sq.yd.	3502/6-5-99	-do-
16.	Vinod Kumar Gupta	-do-	800 Sq.yd.	3506/6-5-99	-do-
17.	Sham Sunder S/o Jai Ram	-do-	225 Sq.yd.	5516/42/10-8-2000	Due to Hon'ble High Court orders.
18.	Jai parkash S/o Bhur Singh	-do-	450 Sq.yd.	-do-	-do-
19.	Sheela Devi W/o Ram Avtar	-do-	450 Sq.yd.	-do-	-do-
20.	Sehdev	-do-	500 Sq.yd.	-do-	-do-
21.	Bhanmatti W/o Joginder	-do-	150 Sq.yd.	-do-	-do-
22.	Ram Pyari W/o Satbir etc.	-do-	375 Sq.yd.	-do-	-do-
23.	Bholi Devi W/o Mani Dev	-do-	300 Sq.yd.	-do-	-do-
24.	Jai Narain S/o Sanwal Ram	-do-	300 Sq.yd.	-do-	-do-
25.	Gian Chand S/o Sanwal Ram	-do-	200 Sq.yd.	-do-	-do-
26.	Santosh Devi W/o Devde	-do-	1200 Sq.yd.	-do-	-do-
		Total :	1.48 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
27.	Sher Singh S/o Ganga Ram	Sec.-1, Narnaul	300 Sq.yd.	5516/42/10-8-2000	Due to Hon'ble High Court orders.
28.	Jitender Kumar Adv.	-do-	432 Sq.yd.	-do-	-do-
29.	Naresh Kumar S/o Ramjilal	-do-	500 Sq.yd.	-do-	-do-
30.	Bimla Devi W/o Sultan Singh	-do-	450 Sq.yd.	-do-	-do-
31.	Virendar Kumari W/o Kanchan Lal	-do-	300 Sq.yd.	-do-	-do-
32.	Phool Chand Saini	-do-	160 Sq.yd.	-do-	-do-
33.	Suresh Chand S/o Parbhati Lal	-do-	313 Sq.yd.	-do-	-do-
34.	Anita W/o Raj Kumar	-do-	400 Sq.yd.	-do-	-do-
35.	Dariya Singh S/o Jai Narain	-do-	800 Sq.yd.	-do-	-do-
36.	Mahabir Parshad	-do-	300 Sq.yd.	-do-	-do-
37.	Ghisa Ram S/o Dev Karan	-do-	400 Sq.yd.	-do-	-do-
38.	Mahender Partap	-do-	800 Sq.yd.	-do-	-do-
		Total :	1.05 Acres		
		B.F.	2.17		
		G. Total:	3.22 Acres		

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001 URBAN ESTATE, GURGAON.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Ground of release
1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
1.	Bhim Singh, Ved Pal Singh	Sec.-9, 9A, Gurgaon	450 Sq.yd.	2423/24-5-95	Due to existing construction before U/S-4.
2.	Dharam Singh S/o Rampat	Sec.-38, Gurgaon	928 Sq.yd.	6654/7-12-95	Due to existing construction & falls near abadi & Laldora.
3.	M/s East India Hotels Ltd.	Sec.-30, Gurgaon	30 Sq.yd.	125/4-1-96	For setting up hospital.
4.	M/s Ansal Properties & Industries Pvt. Ltd.	Sec.-44-46, Gurgaon	22K-16Marla	1943/22-3-96	As per Govt. Policy & the land purchased by the colonizer before Section-4.
5.	M/s I.S.T., Gurgaon	Sec.-21, Gurgaon	16.50 Acres	3004/7-5-96	Industrial unit existing & compromise before U/S-4 notification.
6.	Gram Panchayat, Jharsa	Sec.-38, Gurgaon	436 Sq. yd.	2910/13-5-97	Due to existing Hanuman Mandir.
7.	M/s Palwal Export Pvt. Ltd.	Sec.-33- 34, Gurgaon	1.10 Acres	3013/20-5-97	Due to Hon'ble High Court orders.
		Total :	50.82 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
8.	M/s Ansal Properties & Indstt. Ltd.	Sec.-44-46, Gurgaon	1K-4 Marla	3436/30-5-97	Due to licenced area.
9.	M/s Gopal Dass & Com. Gurgaon	Sec.-51-52, Gurgaon	38 Acres	5079/19-8-98	For grant of licence for group housing as per Govt. policy.
10.	M/s God Gifts Prop., Gurgaon	Sec.-26, 27,28,42, Gurgaon	2.56 Acres	937/17-2-98	For grant of licence as per Govt. policy.
11.	M/s Homage Build. Pvt. Ltd.	Sec.-26,27,28,42, Gurgaon	2.1578 Acres	932/17-2-98	-do-
12.	19 Applicants, Gurgaon	Sec.-2,3, Gurgaon	23.1725 Acres	998/19-2-98	Due to Hon'ble High Court orders.
13.	Phoolwati & Ramrati, Gurgaon	Sec.-42, Gurgaon	3.1875 Acres	1712/25-3-98	For grant of licence as per Govt. policy.
14.	M/s Gulab Farm (P)	Sec.-42, Gurgaon	13.478 Acres	6300/29-10-98	-do-
15.	Ram Sarup & Balwant Singh	Sec.-23, Gurgaon	220 Sq. Mtrs	6488/6-11-98	Due to Hon'ble Supreme Court orders.
16.	Maman & Hari Singh, Gurgaon	Sec.-42, Gurgaon	3.9437 Acres.	1169/16-2-99	For grant of licence.
17.	Suraj Bhan & Dharampal	Sec.-52, Gurgaon	1210 Sq.yd	4522/22-6-99	Due to existing construction before U/S-4 notification.
18.	Anumod Sharma S/o Vishnu Datt Sharma	Sec.-15, Gurgaon	4.731 Acres	4987/18-7-99	For grant of licence as per Govt. policy.
19.	Sat Parkash, Gurgaon	Sec.-10-A, Gurgaon	1K-18 Marla	7393/16-11-99	Compromise basis & the development works of HUDA.
		Total :	92.01 Acres		

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
20.	M/s Ansal Props. Indstt. Ltd.	Sec.-1,2, Gurgaon	4K-5Marla	8155/20-2-99	For grant of licence as per Govt. policy.
21.	M/s DLF Universal Ltd., Gurgaon	Sec.-26,27,28,42,43, Gurgaon	1.7187 Acres	242/11-1-2000	For grant of licence as per Govt. policy
22.	M/s Industrano Ltd., Gurgaon	Sec.-34, Gurgaon	1Acre	8330/24-2-99	Compromise basis & for the development works of HUDA.
23.	Sukhbir Singh etc.	Sec.-42, Gurgaon	2.38 Acres	3204/15-5-2000	For grant of licence as per Govt. policy.
24.	M/s Queensdale Cultivation Pvt. Ltd.	-do-	2.31 Acres	3992/22-6-2000	For grant of licence as per Govt. policy.
25.	M/s DLF Universal Ltd., Gurgaon	Sec.-26,27,28,42,43, Gurgaon	1B-12B-0B 0B-2B-0B	5236/28-7-2000	Due to already licenced area as per Govt.policy
26.	M/s Madhu Cultivation Ltd., Gurgaon	-do-	0-16-0	-do-	-do-
27.	M/s Queensdale Pvt. Ltd.	-do-	0-5-0	-do-	-do-
28.	M/s Kum-Kum Cultivation Pvt. Ltd.	-do-	0-12-0	-do-	-do-
29.	M/s Oscar Farming Co. Ltd., Gurgaon	-do-	0-12-0	-do-	-do-
30.	M/s Suvida Agro Products. Ltd., Gurgaon	-do-	0-12-0	-do-	-do-
31.	M/s Manak Estate (P) Ltd.	-do-	0-12-0	-do-	-do-
		Total :	8.99 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

1	2	3	4	5	6
	Sarvshri/Smt.—				
32.	M/s DLF Exports Pvt. Ltd.	Sec.-26,27,28,42,43, Gurgaon	2B-1B-0B 0-8-0	5236/28-7-2000	Due to already licenced area as per Govt.policy
33.	M/s Instant Battries Ltd.	-do-	B-B-B 3-2-0 1-17-0	-do-	-do-
34.	M/s Aravali Cultivation Ltd., Gurgaon	-do-	0-7-16	-do-	-do-
35.	M/s Paragon Real Estates Apartment Ltd., Gurgaon	-do-	0-15-0 2-5-0	-do-	-do-
36.	M/s Delhi Towers & Estates Pvt. Ltd. (Associated Com) of M/s Ansal Group, Gurgaon	-do-	1K-5Marla 0K-18Marla	-do-	-do-
37.	M/s Satbir Estates Pvt. Ltd.	-do-	1B-2B-0B B-B-B	-do-	-do-
38.	M/s Hansalaya Builders & Developers Pvt. Ltd.	-do-	0-5-0 0-9-0	-do-	-do-
39.	Kanwal Sain Jain etc.	Sec.-39,Gurgaon	13.50 Acres	14684/18-12-2000	for grant of licence as per Govt. policy.
40.	Mahavir Singh.	Sec.-26-A, 27, 28,42, 43, Gurgaon	3.84 acres	14740/20-12-2000	-do-
		Total	20.23 Acres		
		B.F.	151.82 Acres		
		G. Total	172.05 Acres.		

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001, DISTRICT HISSAR

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Grounds of release
1	2	3	4	5	6
1.	Suresh Kumar, Pawan Kumar M/s Batra Cold Store.	Fatehabad, Sector-3	1.00 Acre	2722-25/13-6-95	Due to existing cold store before U/S-4.
2.	Nand Lal Saini etc. Tarsam Nagar, Hisar, (15-20 Houses.)	Hissar, Sector-1-4	2.00 Acres	2543-46/30-5-95	Due to constructed colony.
3.	Sh. Madan Lal, Inderjit Kaur Bimla Devi	Sector.-13, Hissar	2051 Sq.yd.	14155-59/ 20-11-2000	Due to existing construction before Section-4.
		G.Total :	3.42 Acres.		

[श्री धीर पाल सिंह]

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001, DISTRICT PANCHKULA.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Grounds of release
1	2	3	4	5	6
1.	Sh. Krishan Chand S/o Mangat Rao	Sec.-20,Panchkula	16K-6M	3526/3-6-97	Due to irregular shape and location and constants.
2.	Chaudhary Roshan Lal Memorial Deepmanav Sewa Ashram Charitable.	Sec.-3,Panchkula	11 Bigha	7317/12-11-99	Due to existing religious structures before under Section-4.
3.	Krishana Saw Mills	Sec.-3,Panchkula	1.02 Acre	7978/10-12-99	Due to saw mills before under section-4.
4.	Sh. Prem Singh, Vill.-Kundee.	Sec.-20,Panchkula	0.13 Acre	1876-78/ 21-3-2000	Due to existing structures before under Section-4.
5.	Sh. Seriya S/o Kishana	-do-	0.10 Acre	4708/6-7-99	-do-
6.	Sh. Jageet Singh, Vill. Ramgarh	Sec.-27-28,Panchkula	0K-2 Marla	187-91/8-1-96	Due to existing structures smadhi etc.
7.	M/s Kaisar Hospital	Sec.-21,Panchkula	10K-8 Marla	1971-75/27-4-95	Due to existing dispensary before under Section-4.
8.	Sh. R.N. Prashar, IAS	Sec.-4,Mansa Devi Complex, Panchkula	2035.10 Sq.Mtrs.	7001-05/1-9-2000	Compromise basis for the development work of HUDA and due to existing structures before under Section-4.
9.	Abha Rathore W/o S.P. Rathore Vill-Banna, Madanpur.	Sec.-25,Panchkula	192 Sq. yds.	8079-83/7-9-2000	Due to Court orders.
		Total :	7.56 Acres		

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001, DISTRICT KARNAL.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Grounds of release
1	2	3	4	5	6
1.	M/s Man Cold Storage, Karnal	Sec.-4-5, Karnal	3.00 Acres	2117/6-4-98	Due to existing structures before under Section-4.
8.	Sh. Kuldeep Rai	Sec.-3, Karnal	1B-12 Biswas	6047-50/20-9-96	-do-
		Total:-	3.33 Acres		

[श्री धीर पाल सिंह]

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001, DISTRICT PANIPAT.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Grounds of release
1	2	3	4	5	6
1.	Guru Amar Dass Gurudwara	Sec.-17, Panipat	703.45 Sq.Mtrs.	5539/27-10-95	Due to existing Gurudwara before under Section-4.
2.	Radha Swami Satsang Beas.	Sec.-17-18, Panipat	5992.00 Sq.Mtrs.	3510/3-6-97	Due to existing structure before under Section-4.
3.	Sh. Dhara Singh etc.	Sec.-13 &17, Panipat	8521.22 Sq.Mtrs.	8134/15-12-99	Compromise due to development by HUDA
4.	M/s Anand Product	Sec.-24, Panipat	203.50 Sq.Mtrs.	1948/19-3-99	Due to existing factory before under Section-4.
		Total :	1.99 Acres.		

THE TOTAL LAND RELEASED TO THE ORIGENAL LAND OWNERS DURING THE PERIOD FROM APRIL, 1995 TO 31-1-2001, DISTRICT JAGADHRI.

Sr.No.	Name of party	Name of Urban Estate/Sector	Area released	No.& Date of release orders	Grounds of release
1	2	3	4	5	6
*1.	Kuldhir Singh	Sec.-17-18, Jagadhri	30 Marla	7040/5-9-2000	Due to existing structure before under Section-4 and surrounding land
		Total :	0.19 Acre		

Construction of Old Age Home

12. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the district-wise names of villages wherein Old-Age Home constructed/are being constructed in the State during the year 2000-2001 and 2002 together with the funds earmarked for the purpose.

Minister of State For Social Welfare (Sh. Risal Singh) : The details of district-wise names of villages wherein Old Age Homes have been constructed/are being constructed in Haryana during 2000-2001 alongwith the funds earmarked/tentative cost is enclosed herewith. Being an on-going programme the villages where such homes will be constructed in future including year 2002 are yet to be selected in course of time.

List of Villages showing position of Vridh Vishramgreh and funds earmarked for the purpose

Sr.No.	Name of the District	Name of the Village where constuction work is completed	Name of the Village where constuction work in progress	Source of Funds	Funds alloted (Rs. in lac)	Tentative Expenditure
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ambala		1. Manglai	M.P. LAD	2.50	—
		—	2. Durga Nagar	-do-	2.50	—
		—	3. Bhudg Pur	-do-	2.50	—
		—	4. Nanpolla	-do-	2.50	—
		—	5. Naggal	-do-	2.50	—
		—	6. Taipla	-do-	2.50	—
		—	7. Pilkhani	-do-	2.50	—
		—	8. Jatwar	-do-	2.50	—
		—	9. Pathehri	-do-	2.50	—
		—	10. Badholi	-do-	2.50	—
		—	11. Ali Pur	-do-	2.50	—
		—	12. Hema Majra	-do-	2.50	—
		—	13. Tagali	-do-	2.50	—
		—	14. Bikampur	-do-	2.50	—
		—	15. Kakar Majra	-do-	2.50	—
		—	16. Halpari	-do-	2.50	—
		—	17. Galheri	-do-	2.50	—
		—	18. Nohani	-do-	2.50	—
		—	19. Kalpi	-do-	2.50	—
		—	20. Berkheri	-do-	2.50	—
2.	Panchkula	—	1. Ramgarh	-do-	2.50	—
		—	2. Batour	-do-	2.50	—
		—	3. Mouli	-do-	2.50	—
		—	4. Raipur Rani	-do-	2.50	—
		—	5. Nandpur Kedarpur	-do-	2.50	—
		—	6. Manakpur Devilal	-do-	2.50	—

1	2	3	4	5	6	7
		—	7. Rath Pur	-do-	2.50	—
3.	Yamuna Nagar	—	1. Bijoli	M.P. LAD	20.00	—
		—	2. Milk Khas			
		—	3. Katterwali			
		—	4. Peerwali			
		—	5. Majri Subarari			
4.	Kurukshetra	—	1. Lohara	M.P. LAD	2.50	—
		—	2. Jyotisar	-do-	2.50	—
		—	3. Kharindwa	-do-	2.50	—
		—	4. Nalvi	-do-	2.50	—
		—	5. Thol	-do-	2.50	—
5.	Kaithal	—	1. Sakra	Panchyati Fund	Cost varies village to village depending upon the design and type of material used	—
		—	2. Barsana	-do-		
		—	3. Patti Afgan	-do-		
		—	4. Keerak	-do-		
		—	5. Kalar Majra	-do-		—
		—	6. Balbehra	-do-		—
		—	7. Ferojpur	M.P. LAD	2.00	—
		—	8. Matour	-do-	2.00	—
		—	9. Kailram	-do-	2.00	—
		—	10. Kotra	-do-	2.00	—
6.	Fatehabad	1. Bhuna (Existing building converted)	—	—	—	—
		2. Gaurkhpur (Existing building converted)	—	—	—	—
			1. Gullarwala	Panchayati Fund	—	2.15
			2. Lali	-do-	—	2.15
			3. Bangon	PRI/P. Share	—	2.15
			4. Majra	-do-	—	2.15
			5. Bhattu	PRI	—	2.15

1	2	3	4	5	6	7
7.	Sirsa	1. Chomar Khera	—	ESA	1.55	—
		2. Tigri	—	-do-	2.00	—
		3. Daultpur Khera	—	Panchyati fund/ M.P. LAD	1.50	—
		4. Karamgarh	—	-do-	1.50	—
		5. Satwala	—	-do-	1.50	—
		6. Rori	—	-do-	1.50	—
		7. Phaggu	—	M.P. LAD	1.50	—
		8. Bacher	—	-do-	1.55	—
			1. Mathasinghana	P.Fund/M.P. LAD	1.75	—
			2. Kanwarpura	-do-	1.75	—
			3. Chaharwala	P.Fund/M.P. LAD/DP	2.15	—
8.	Hisar	—	1. Juglan	M.P. LAD	2.00	—
			2. Masudpur	-do-	2.00	—
			3. Sorkhi	-do-	2.00	—
			4. Kheri Lochab	-do-	2.00	—
			5. Migni Khera	-do-	2.00	—
			6. Kaimeri	-do-	2.00	—
9.	Jind	1. Rasida	—	Panchayati Fund	—	1.82
		2. Jiwanpur	—	EAS FUND	—	2.50
			1. Budda Khera Lather	-do-	—	1.82
			2. Khanda	Panchayati Fund	—	1.82
			3. Khera Khemawati	-do-	—	1.82
			4. Habbatpur	-do-	—	1.82
			5. Ujjana	-do-	—	1.82
			6. Dharodi	-do-	—	1.82
			7. Peopletha	-do-	—	1.82
			8. Data Singh Wala	-do-	—	1.82
			9. Dhamtan Shaib	-do-	—	1.82
			10. Kasuhan	EAS/P. FUND	—	1.82
			11. Uchana Kalan	EAS/P. FUND	—	1.82

1	2	3	4	5	6	7
10.	Bhiwani	1. Gauri Pur	—	M.P. LAD	14.00	—
			1. Dirod			
			2. Mundhal Khurd			
			3. Jatu Luhari			
			4. Charkhi			
			5. Mandola			
			6. Obra			
11.	Karnal		1. Nigdu	M.P. LAD	3.00	—
			2. Bhadson	Panchyati Fund	3.00	—
			3. Chochra	-do-	3.00	—
			4. Barota	—	3.00	—
		—	5. Kalron	M.P. LAD	3.00	—
12.	Panipat	1. Patti Kalyana	—	Panchyati Fund	—	Cost varies village to village depending upon the design and type of material used.
		2. Manana (both in existing building converted)	—	-do-	—	
			1. Bapoli	-do-	—	2.50
			2. Dahar	-do-	—	2.50
			3. Pathri	-do-	—	2.50
			4. Kurana	-do-	—	2.50
			5. Rair Kalan	-do-	—	2.50
			6. Dharangarh	-do-	—	2.50
			7. Ganjbar	-do-	—	2.50
			8. Baroli	-do-	—	2.50
			9. Azizulapur	-do-	—	2.50
			10. Sultana	-do-	—	2.50
			11. Bohali	-do-	—	2.50
			12. Sewah	-do-	—	2.50
13.	Sonepat	1. Kherkhoda	(Existing building converted)	-do-	—	2.00
		2. Hullaheri		-do-	—	1.25
		3. Mahara		-do-	—	2.00

1	2	3	4	5	6	7
		4. Matand		Panchyati Fund	—	2.00
		5. Dattoli		-do-	—	2.00
			1. Jatheri	-do-	—	2.00
			2. Orangabad	-do-	—	2.00
14.	Rohtak	—	1. Jasia	M.P. LAD	6.00	—
			2. Kheridi	-do-		
			3. Bhansi	-do-		
15.	Jhajjar	—	—	M.P. LAD	8.00	Funds allotted in 4 villages (Madana Kalan, Patoda, Salhawas & Badli) but work not started.
16.	Gurgaon	1. Sukharali	—	Panchyati Fund	—	2.00
		2. Sikanderpur	—	-do-	—	2.00
		3. Sarai Allawarde	—	-do-	—	2.00
		4. Gurgaon Vill.	—	-do-	—	4.50
		5. Basai	—	-do-	—	2.00
		6. Kanhai	—	-do-	—	2.00
			1. Jharsa	-do-	—	3.60
			2. Dharampur	-do-	—	2.00
			3. Manasar	-do-	—	6.00
17.	Faridabad	1. Sikari	—	-do-		Cost varies village to village depending upon the design and type of material used.
			1. Neemka	-do-	—	—
			2. Mohana	-do-	—	—
			3. Aherwan	-do-	2.25	—

1	2	3		4		5	6	7
				4.	Bhiduki	Panchyati Fund	—	—
				5.	Bahin	-do-	2.00	—
18.	Rewari	1.	Nandrampura Khas			-do-	0.10	—
		2.	Dharuhera			-do-	0.10	—
		3.	Gopalpur Gaji			-do-	0.10	—
		4.	Banipur		(Esisting building	-do-	0.10	—
		5.	Khori		converted)	-do-	0.10	—
		6.	Lula Ahir			-do-	0.10	—
		7.	Jatusana			-do-	0.10	—
		8.	Suma Khera			-do-	0.10	—
		9.	Murawada			-do-	0.10	—
		10.	Lilot			-do-	0.10	—
		11.	Khurisad Nagar			-do-	0.10	—
				1.	Kalaka	-do-	2.00	—
				2.	Goklegarh	-do-	2.00	—
				3.	Mundi	-do-	2.00	—
				4.	Karavara Mankapur	-do-	2.00	—
				5.	Parkhotampur	-do-	2.00	—
				6.	Badoli	-do-	2.00	—
				7.	Nahad	-do-	2.00	—
				8.	Kosli	-do-	2.00	—
				9.	Bhakli	-do-	2.00	—
				10.	Jalivas	-do-	2.00	—
19.	Narnaul	1.	Pattikara (Existing building converted)					
				1.	Khatoti Kalan	(Existing building converted)		
				2.	Ganiyar			
				3.	Pali			
				4.	Malra Sarai			

Collection of Passenger Tax

13. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the total amount of passenger tax collected in the State during the period from March, 2000 to till todate;

(b) the total amount out of the amount referred to in part (a) above has been collected by Haryana Roadways;

(c) the total amount of passenger tax/penalties collected by Regional Transport Authorities in the State during the period referred to in part (a) above ?

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार) :—

(क) राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2000 से जनवरी, 2001 तक 190.09 करोड़ रुपये यात्री कर के रूप में एकत्रित किये गये ;

(ख) उपरोक्त दी गई राशि में से 112.54 करोड़ रुपये हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा एकत्रित कर के जमा करवाये गये ;

(ग) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा यात्री कर एकत्रित नहीं किया जाता। फिर भी उन द्वारा ऊपर 'क' में निर्दिष्ट अवधि के दौरान चालानों से 8.20 करोड़ की राशि जुर्माने (कम्पोजीशन फीस) के रूप में एकत्रित की गई।

Agreement with Rajasthan Government

14. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether an agreement has been reached with the Rajasthan Government for giving water of Gurgaon Canal to the State of Rajasthan to irrigate the area of Bharatpur district, if so, the details there of ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नहीं श्रीमान जी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए मैं अपनी तरफ से, पूरे सदन की तरफ से सभी माताओं, बहनों और बालिकाओं को बधाई तथा शुभ कामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मकसद केवल एक ही है कि महिलाओं में जागृति पैदा की जाये, चेतना पैदा की जाये और उनको सम्मान प्रदान किया जाये। वैसे भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में नारी को बहुत सम्मान प्रदान किया गया है। भारत जैसे देश में तो एक कहावत प्रचलित है कि 'जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है।' हमारे देश में सीता, सावित्री, विद्यावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक महिलाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। खेल के मैदान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एक महिला ने सम्मान दिलाया। यह श्रेय भी हरियाणा प्रदेश को जाता है। हरियाणा

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

की एक महिला ने सिडनी ओलम्पिक खेलों में भारत को एकमात्र कांस्य पदक दिलवाया और पदक तालिका में भारत का नाम लिखवाया जबकि दूसरे सभी खिलाड़ी मुंह लटका कर बिना कोई पदक हासिल किए वापिस आ गये। इसके अतिरिक्त यह श्रेय भी हरियाणा को ही जाता है कि करनाल की एक महिला कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई है। हरियाणा प्रदेश में महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, खेल का मामला हो या अंतरिक्ष में जाने का मामला हो, महिलाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। हरियाणा के रिवाड़ी जिले की संतोष यादव ने माउंट ऐवरैस्ट पर चढ़कर हरियाणा का नाम रौशन किया है। हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए कई किस्म की योजनाएं बनाई हैं, विशेष रूप से गरीब वर्ग और हरिजन वर्ग की लड़कियों के लिए। हरिजन वर्ग की महिला को जब बच्चा होता है तो उसे 500/- या 1000/- रुपये उसके सम्मान में अनुदान राशि के रूप में दिए जाते हैं। गरीब हरिजन की लड़कियों की शादी के समय हरियाणा सरकार कन्यादान के रूप में 5100/- रुपये देती है। इस तरह से आज के दिन हरियाणा सरकार महिलाओं को पूरा सम्मान दे रही है। लेकिन इसके साथ-साथ पूरे सदन तथा पूरी स्टेट के लोगों के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि आज के दिन महिलाओं की संख्या दिन ब दिन पुरुषों के मुकाबले में कम होती जा रही है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश में 1000 लड़कों के पीछे लगभग 750 लड़कियां हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए और लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करनी चाहिए ताकि सबको प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ हो। एक बार फिर से मैं 'महिला दिवस' पर सबको बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर सबसे पहले किसी महिला को दिया जाये। बहन सरिता नारायण तो कल बोल चुकी हैं इसलिए आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहन वीना छिब्बर को बोलने का अवसर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो ये महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब प्लीज़ आप बैठें।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं आदि

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, गवर्नर एड्रैस पर डिबेट शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, लिख कर दें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, लिखकर तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन जीरो ऑवर में तो हरेक को बोलने का हक है इसलिये आप मुझे बोलने का समय दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : राव साहब, कल भी किसी ने लिख कर नहीं दिया और जिन्होंने लिख कर दिया वे सदन में बोलने के लिये आये ही नहीं। अगर आप चाहें तो उनकी पोजीशन पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अण्डर कंसीडरेशन हैं (शोर) उनमें से कुछ डिस-अलाउ हो चुके हैं। (शोर) कादियान साहब का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी अंडर कंसीडरेशन है (शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपकी सीट के सम्बन्ध में कुछ रूलिंग चाहता हूं। (शोर) आपकी हिफाजत के सम्बन्ध में, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप मेरी हिफाजत के सम्बन्ध में कैसी रूलिंग चाहते हैं? (शोर)। आप बैठिए। (शोर)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, जीरो ऑवर में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, कल भी मैंने इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाही थी। कल एक कैनेडियन डेलीगेशन यहां आया और उसके बाद एक माननीय सदस्य ने अपना भाषण पढ़कर दिया। यह कैनेडियन डेलीगेशन आपकी सीट के सहारे से सदन के अन्दर दाखिल हुआ और जब वह उठकर गया तो ऑफिसर्ज गैलरी की तरफ से बाहर गया। क्या किसी विदेशी का हमारे सदन के अन्दर प्रवेश करना और यहां एक माननीय सदस्य द्वारा भाषण पढ़कर देना सदन की परम्परा के अनुसार उचित था या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि पार्लियामैंट की कन्वैंशन रही है कि मैम्बर्ज रैफ्रेंसिस के लिए पढ़ सकता है। बाकी कैनेडियन डेलीगेशन के मेरे पास से आने की जो बात है उससे मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ हूं। (शोर) कल आपकी पार्टी के ही एक सदस्य श्री जय प्रकाश जी मेरे पास आकर मेरे पर्सनल सैक्रेट्री तक आये थे। हमने तब भी कुछ नहीं बोला था। (शोर) यह तो बड़े सम्मान की बात है कि हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये कैनेडियन डैलीगेशन आया। यह तो बड़े गौरव की बात है। हमारे लिये यह शोभा की बात है। हम तो चाहते हैं कि समय-समय पर इस तरह के और भी डेलीगेशन आयें और इस हाउस की कारगुजारी देखें, आपकी योग्यता देखें, आपकी भावनाओं को देखें। कहीं आप इस बात से तो चिंतित नहीं कि आपकी परफोर्मेन्स में कमी रही और आपको यह अखाड़ा लग रहा हो। (विघ्न)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्द्रजीत सिंह जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, राव इन्द्रजीत सिंह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। ये सीजंड और एक अच्छे पार्लियामैंटेरियन भी हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सदन के अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि वे किसी को कहीं पर बैठाएं, कहीं पर ले जाएं। ये अध्यक्ष महोदय के अधिकारों पर आपत्ति कर रहे हैं यह इनको शोभा नहीं देता। यहां एक विदेशी डेलीगेशन चल कर आया और वह अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आया। वह डेलीगेशन सदन की

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

कार्यवाही देख कर गया। ये लोग इस बात को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये लोग हर मामले में क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसिज़्म वहां करना चाहिए जहां किसी बात को क्रिटिसाइज़ करने का अवसर आता है। पिछले सैशन में अपोज़िशन की तरफ से सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडैंस मोशन आया लेकिन अपोज़िशन वाले उस पर चर्चा करने से पहले ही सदन से भाग गए। जब इनको बोलने के लिए खुल कर समय दिया जाता है तब यहां से भाग लेते हैं या बाथरूम में छिप जाते हैं या यहां से छिप कर चले जाते हैं। इन लोगों को चाहिए कि ये सदन की गरिमा का भी ध्यान रखा करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य इन्द्रजीत सिंह जी ने जो बात कही वह बिल्कुल ठीक कही थी, गलत नहीं कही थी। यह बात भी ठीक है कि यहां सदन में वह विदेशी डेलीगेशन आया। अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामैंट का दो बार मैम्बर रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ और राज्यसभा का भी मैम्बर रहा हूँ। हमने वहां पर देखा है कि जब इस तरह का कोई विदेशी डेलीगेशन आता है वह अपनी गैलरी में बैठने के लिए हाउस के अन्दर से हो कर इस तरह नहीं जाता जिस तरह से वह डेलीगेशन हमारे हाउस के अन्दर से हो कर गया है। पार्लियामैंट में इस तरह के डेलीगेशन का अलग से गेट है जैसे आपके आने का अलग गेट है। इस गेट से हाउस में आ सकते हैं। यह नहीं कि वे हाउस के अन्दर से हो कर गैलरी में जाएं। हम बाकायदा उनका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से मैंने उनका स्वागत किया था। माननीय सदस्य इन्द्रजीत सिंह जी का कहना अनुचित नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप भी थोड़ा-सा कूल रहें और मुख्य मंत्री जी भी थोड़ा-सा कूल रहें। यह मुनासिब बात नहीं है कि मुख्यमंत्री की मर्जी में जो बात आए वह बात कह दें।

श्री अध्यक्ष : यह हरियाणा विधान सभा की रूल्ज़ ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिज़नैस की बुक है इसका रूल 120 है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। यह रूल कहता है —

> Rule 120 —"All matters not specifically provided in these Rules and all questions relating to the detailed working of these Rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो यह इजाजत देता हो कि विदेशी डेलीगेशन सदन के अन्दर से हो कर गैलरी में जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने आपको रूल 120 पढ़ कर सुनाया है। (शोर)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नील गायों (रोझ) द्वारा फसलों की क्षति संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 3 regarding Damage of Crops by antelope (Roze) from Shri Karan Sing Dalal, M.L.A. I admit it. Shri Karan Singh Dalal may read his notice and the Minister concerned may make the statement thereafter.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में नील गायों (रोज़) की अधिक संख्या होने के कारण किसानों की फसलों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है क्योंकि नीलगायों (रोज़) के झुंड

उनकी फसलों को खा जाते हैं तथा लोगों को चोट भी पहुंचाते हैं। इसके कारण पूरे राज्य के किसान बहुत अधिक परेशान हैं तथा वित्तीय हानि उठा रहे हैं।

इसलिये, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्य संसदीय सचिव द्वारा—

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : नील गाय हिरण प्रजाति का तेज़ दौड़ने वाला एक वन्य प्राणी है जिसे रोज़ के नाम से जाना जाता है। यह सारे हरियाणा राज्य में पाया जाता है और जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी, रोहतक, सिरसा तथा जींद में अधिक हैं। इस वन्य पशु द्वारा किसानों की खेती को पहुंचाये जा रहे नुकसान से सरकार पूरी तरह अवगत है। लोगों में यह गलत धारणा है कि नीलगाय 'गाय' प्रजाति से सम्बन्ध रखती है। यही कारण है कि इसके नुकसान के होते हुये भी इस पशु को वे खत्म करने की कार्यवाही नहीं करना चाहते। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के लागू होने से नीलगाय को इसके अनुभाग-III में शामिल किया गया तथा इसे आंशिक सुरक्षा प्रदान की गई। 22-6-1973 से नीलगाय की संख्या को कम समझते हुये हिरण प्रजातियों के अन्य वन्य पशुओं के साथ इसके शिकार पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया। पिछले तीन दशकों में नीलगायों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस समय यह 30,000 के करीब आंकी जा सकती है। इस वन्य प्राणी द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने बारे किसानों से काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

राज्य सरकार के अनुरोध पर वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा हरियाणा में नीलगाय की समस्या पर अध्ययन किया गया। इस संस्थान ने निम्नलिखित सम्भावित हल सुझाए :—

1. बिजली की तार से बाड़ करना,
2. बढ़ती संख्या को रोकना अथवा छंटनी करना,
3. आम शिकार करने देना,
4. पकड़ना एवं बाहर भेजना, तथा
5. प्रजनन पर नियंत्रण।

साथ ही उन्होंने पहले तीन हल जैसा कि (1) बिजली के तार से बाड़, (2) छंटनी तथा (3) आम शिकार करने देने को ही नीलगाय की बढ़ती संख्या को कम करने के लिये उपयुक्त बताया क्योंकि इन्हें पकड़ना तथा इनका प्रजनन नियंत्रण इस समय सम्भव नहीं।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस वन्य प्राणी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुभाग III से अनुभाग V में बदलने के लिये लिखा था ताकि यह पीड़क जन्तुओं में आ जाये और इसका खुला शिकार हो सके। राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार का अनुरोध किया गया। भारत सरकार इस अनुरोध से सहमत नहीं हुई परन्तु राज्य सरकारों को निर्देश दिये कि वे उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं जिसके अनुसार यदि मुख्य वन्य प्राणी वार्डन सन्तुष्ट हो कि कोई वन्य प्राणी मानव जीवन अथवा सम्पति के लिये हानिकारक हो गया है तो वह इसके मारने का परमिट दे

[श्री राम पाल माजरा]

सकते हैं। राज्य सरकार ने 7-11-1996 के इस वन्य प्राणी को ग्राम पंचायतों के अनुरोध पर मारने के परमिट देने बारे हिदायतें जारी की हैं। पिछले पांच वर्षों में 19 परमिट जारी किये गये और मार्च, 2000 तक केवल 9 नील गायें मारी गईं।

वर्ष 1996 में पलवल क्षेत्र में नील गाय को पकड़ने तथा बाद में बाहर भेजने के लिये एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग पर 1.98 लाख रुपये खर्च करके भी इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। केवल चार नील गायें पकड़ी गईं वे भी मौके पर ही मर गईं।

इनके पकड़ने के लिये व्यवसायिकों की सेवायें लेना, जाल तथा लोहे की जाली की बाड़ लगाने के अन्य तरीकों से भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला।

नील गायों के आतंक का सामना केवल तब ही किया जा सकता है जब लोगों तथा उनके स्थानीय प्रतिनिधियों, विधायकों तथा पंचायती राज संस्थानों जैसे स्थानीय निकायों का कारगर सहयोग मिले।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय माजरा साहब ने जो तथ्य हाऊस के सामने रखे हैं वे बिल्कुल सही हैं लेकिन इसके लिए हमें कोई न कोई विचार तो करना ही होगा। यह ठीक है कि कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं इन नील गायों के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री महोदय से और इस सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको मारने के बारे में भारत सरकार से पुनः अनुरोध किया जाये। पहले जब मैं इस विभाग का मंत्री था तो उस वक्त भी हमने इन नील गायों को पकड़ने का प्रयास किया था और तकरीबन उस वक्त दो लाख रुपये खर्च किये गये थे भारत सरकार से भी इनको मारने की अनुमति मांगी थी लेकिन भारत सरकार ने यह अनुमति नहीं दी थी। ये रोज़ घोड़ों से भी तेज दौड़ते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हम किसानों को बेसहारा होते हुए भी नहीं देख सकते। ये रोज़ किसानों की फसलों को बहुत नुकसान करते हैं और कहीं पर यदि एक-दो आदमी हों तो इन पर भी हमला करने का भी प्रयास करती हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पंजाब में नीलगाय को मारने पर आपत्ति नहीं है उसी प्रकार से हरियाणा में भी इनको मारने की अनुमति दी जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री से अनुरोध है कि इनको मारे जाने का एक प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा से पास करके हरियाणा सरकार भारत सरकार को भेजें और उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाये।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, ये सप्लीमेंटरी पूछें। ये तो यहां पर अपना भाषण देने लग गए। आप इनसे कहें कि ये केवल सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय नीलगाय या इन रोज़ों को मारने के लिए कोई इन्तज़ाम सरकार की तरफ से करेंगे या सरकार प्रदेश के लोगों को यह सन्देश देने पर विचार करेगी कि जो भी लोग नीलगायों को मारेंगे उनके खिलाफ सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी? (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि कम से कम मारने का शब्द इस्तेमाल न करें और ऐसी सरकार की नीति रहनी चाहिए। ये खुद मन्त्री भी रहे हैं और इन्होंने इस बारे में स्वयं भी प्रयास किया होगा (विघ्न) इस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, हमारे माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न) हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि पानी और बिजली नहीं मिल रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, यह रैलेवैन्ट सवाल नहीं है। हमें उम्मीद थी कि आप कोई सही सवाल पूछेंगे। इस समय जो मामला विचाराधीन है उससे सम्बन्धित यह सवाल नहीं है इसलिए आप अभी बैठें। (विघ्न) मन्त्री जी, आप जवाब दें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में नीलगाय का आतंक है और किसान भी इससे परेशान हैं। जो दलाल साहब ने कहा है वह तभी सम्भव हो सकता है कि जो जन प्रतिनिधि और विधायक हैं, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों का कारगर सहयोग मिले और लोगों के मन में यह बात खुद बैठ जाए कि यह नीलगाय हिरण प्रजाति की है यह गाय प्रजाति की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा कि यह बहुत तेज दौड़ती है, इनके पीछे घोड़े भी लगा लिये फिर भी नहीं पकड़े जाते। इसलिए मैं इनसे ही यह पूछना चाहूंगा कि क्या अब इनकी स्पीड कम हो गई है या यह पहले तेज दौड़ती थी? दो लाख रुपये में चार नीलगाय पकड़ी गई हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए (विघ्न) यह चार नीलगाय दो लाख रुपये में पकड़ी गई हैं और वह भी मरी हुई। अध्यक्ष महोदय, पंजाब की तर्ज पर हम कोई सन्देश प्रदेश में नहीं दे सकते। हां विधान सभा में इस पर चर्चा हो सकती है। इस पर कार्यवाही करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा हो सकती है इसमें सरकार को कोई ऐतराज नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है कि दो लाख रुपये खर्च करके चार नीलगाय पकड़ी गई हैं। अगर इसमें कोई गलत बात लगती है तो सरकार इस बारे में जरूर इन्क्वायरी करवा ले। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी यह है कि इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि दिल्ली में जो एम्बैसीज हैं वहां पर काफी लोग ऐसे हैं जो कि इन जानवरों का शिकार करना चाहते हैं लेकिन उनको इसका परमिट नहीं मिलता है। हमने हरियाणा में जो प्रावधान किया था वह यह था कि अगर गांव की पंचायत चाहे तो डिप्टी कमिशनर से इन रोजों को मारने का लाइसैंस ले सकती है। डिप्टी कमिशनर उनको परमिट जारी करेगा और इसी प्रकार से एम्बैसीज के लोगों को रोजों को मारने की इजाजत दे कर लाइसैंस दे दें तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक सवाल यह है कि क्या सरकार इन रोजों के ऊपर दूर से जो इन्जैक्शन मारा जाता है, कोई ऐसा इन्जैक्शन इनको लगाएगी जिससे आगे इनके बच्चे न हों? यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप सवाल पूछें सुझाव तो मन्त्री जी देंगे। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर****

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा कि गन से फायर किया जाए। अगर इस प्रकार से जनता के बीच में कोई फायर किया जाए तो इससे जनता में बहुत रोष फैलता है क्योंकि उससे जनता को भी नुकसान हो सकता है। जनता में इससे नाराजगी फैलती है और वे ऐसा करने नहीं देते हैं। जनता के अन्दर नीलगाय पर फायर किया जाए यह संभव भी नहीं है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय कर्ण सिंह दलाल जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और यह समस्या भी है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सदन में यह कहना चाहूँगा कि किसी भी जीव की हत्या करना महा पाप है। यह जो नीलगाय है इसको कोई गाय कहता है कोई हिरण भी कह देता है। अगर आप मारने की इजाजत दे देंगे तो लोग हिरण और दूसरे जानवरों की भी हत्या करेंगे। यह भी सोचने की बात है। कोई यह सोचता है कि लड़की पैदा न हो और किसी के घर में 5-5 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। (विघ्न) जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश की जनसंख्या में बढ़ौतरी हुई है। नीलगाय भी बहुत बढ़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब किसान खेत की पोर में बीज डालता है तब किसान परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे भगवान यह जो मैं बीज बो रहा हूँ इसमें राही का, हल का, पाली का, जीव का, जन्तु का यानि कि जो भी जीवित है, उन सब का हिस्सा इसमें है। इसलिए हमें किसी को भी मारने की बात नहीं सोचनी चाहिए। यह जो माजरा साहब ने न मारने वाली बात कही है मैं इनकी बात की ताईद करता हूँ और इस सरकार का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि रोज़ किसानों की फसल को बहुत नुकसान करते हैं। इन्होंने जो कॉलिंग अटैंशन दी है उसमें तो इन्होंने नीलगाय बताई और अब रोज़ की बात कर रहे हैं। जब ये कृषि मंत्री थे तब इन्होंने चार रोज़ पकड़े थे और वे चारों भी मर गए थे। इससे हमारे हिन्दुत्व को भी ठेस पहुंचती है। जब ये मंत्री थे उस वक्त इन्होंने यह बात क्यों नहीं सोची। अब इनको यह बात याद आ गई है। अध्यक्ष महोदय, ये जो नसबन्दी की बात कर रहे हैं यह ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बंसी लाल जी की सरकार में रहे हैं। (हंसी) जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि फसलों को टिड्डा खा गया। अब ये उसको भूल गए। अब ये यहां पर नीलगाय की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's address will be resumed. Smt. Veena Chhibbar will speak.

श्रीमती वीना छिब्बर (अम्बाला शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में हो रही चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार की सराहना करूंगी कि उन्होंने गुजरात में जो भू-कम्प आया, वहां पर जो लोग करोड़पति थे वे कौड़ी के हो गए हैं, जो आसमान पर रहते थे वे जमीन पर आ गए हैं और जो अच्छे खाते पीते थे वे आज भूखे मर रहे हैं। उन सब की सहायता हमारी सरकार ने की है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए अपनी सरकार की सराहना करती हूँ।

11-00 बजे

स्पीकर साहब, अब मैं परिवहन के बारे में चर्चा करूंगी। परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिये सरकार ने जो पग उठाए हैं उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। इस सरकार ने खटारा बसों के स्थान पर जो 450 बसिज खरीदी हैं यह भी एक अच्छी बात है। खटारा बसिज में लोग बैठते हुए कतराते थे। इसी तरह से जो यातायात सहायता केन्द्र की स्थापना सरकार करने जा रही है उसके लिए भी मैं उसका धन्यवाद करती हूं क्योंकि आम जनता को इसका बड़ा लाभ होगा। मैं एक बात और परिवहन मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि चंडीगढ़ से जाते हुए अम्बाला शहर सबसे

पहले आता है यह बहुत बड़ा शहर है। जहां पर जो बलदेव नगर कैम्प है वहां पर लम्बी दूरी से आने वाली बसिज नहीं रुकती हैं और न ही इस तरह की बसिज में लोगों को वहां तक का टिकट दिया जाता है। बलदेव नगर में एक पुराना बस स्टॉप बना हुआ है उसको सरकार को फिर से चलवाना चाहिए और दिल्ली से अम्बाला शहर तक का टिकट भी हरियाणा रोडवेज की बसिज में दिया जाना चाहिए। सरकार ने स्थानीय शासन का नाम बदलकर नगर विकास विभाग करने का जो फैसला लिया है यह भी एक अच्छी बात है इससे शहरों का विकास होगा और शहरों की सुन्दरता बढ़ेगी। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो डेयरियों को शहर से बाहर ले जाने की बात कही है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूं। लेकिन मैं इस बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो डेयरी शहर से बाहर जाएं उनके लिए बाहर पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इसी तरह से पीने के पानी की बात है। कहते हैं कि अगर जल नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। हर एक को पीने का पानी मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनायी हैं वह बहुत अच्छी हैं। चालीस लीटर से सत्तर लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देने का जो फैसला किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है लेकिन इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि जहां-जहां पर पानी नहीं है वहां पर पीने का पानी पहुंचाया जाना चाहिए। अम्बाला शहर में रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ डूगी गोहर एरिया में पानी बिल्कुल नहीं है। वहां की बहनों को पानी लेने के लिए रेलवे स्टेशन के इस ओर आना पड़ता है जिससे कभी-कभी वहां पर ऐक्सीडैंट भी हो जाते हैं इसलिए मैं चाहती हूं कि अम्बाला शहर में मानव चौक, डूगी गोहर में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से शहरों के सौन्दर्यकरण की बात चल रही है उसी कड़ी में मैं अम्बाला शहर को जोड़ना चाहूंगी। अम्बाला शहर एक ऐतिहासिक शहर है इसका नाम अम्बा के नाम पर पड़ा है। यहां पर गुरु गोबिन्द सिंह जी ने भी अपना बचपन बिताया था। शहरों का सौन्दर्यकरण करने की जो स्कीम बनायी गयी है उसमें अम्बाला शहर को भी जोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह से महिला दिवस पर जो आज मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं को बधाई दी है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में तथा उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने के बारे में जो बात कही है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आज बड़े स्तर पर लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है उसके लिए पक्के तौर पर सरकार को सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। पहले तो बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थीं लेकिन अब पैदा होने से पहले ही पेट के अंदर उनको मार दिया जाता है। इससे महिलाएं कम होती जा रही हैं और पुरुष बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस बारे में सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और प्रकृति की बराबरी रखने के लिए विशेष पग उठाए जाने चाहिएं। इसी तरह से कानून व्यवस्था की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी के राज में रेणुका कांड, द्रोपदी कांड और भूत मांजरा जैसे कांडों की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। आज हर नागरिक को हर नगर को इसका इंतजार रहता है कि कब उनकी बारी आएगी। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसी तरह से पीले कार्ड धारकों की बात है। पीले कार्ड वाला हर आदमी गरीब ही होता है। इसी तरह से एस.सीज. की लड़कियों को 5100/- रुपये शगुन के रूप में देने का सरकार का फैसला भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से अम्बाला शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की भी है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगी कि जिसके पास पीला कार्ड हो उसकी बच्ची को शगुन की राशि जरूर मिले और विधवा को जो सहायता मिलती है वह सभी विधवाओं को मिले, इतनी बात कहते हुए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

श्री जय प्रकाश (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ बड़ी मिन्नत के बाद मुझे बोलने का समय दिया गया। पांच तारीख को राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था वह पूरे तरीके से इनैलो के नेताओं के भाषणों का पुलिंदा है इस में कोई नयी चीज सरकार की ओर से नहीं दर्शाई गई है। सरकार ने अब तक क्या-क्या किया है, अपना क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक बात मैं जरूर ठीक मानता हूँ कि गुजरात में जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें हरियाणा प्रदेश की सरकार ने वहां पर जाकर जो काम किया वह सराहनीय है लेकिन यह जो पैसा इकट्ठा किया गया था यह हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री राहत कोष में दिया गया था न कि इनैलो के अध्यक्ष को दिया गया था। इस पैसे का दुरुपयोग राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए व लोगों में शो करने के लिए किया गया है। यह पैसा इनैलो ने इकट्ठा किया। यह पैसा मुख्य मंत्री राहत कोष में आया था, इसका दुरुपयोग करना एक गलत बात है। एस.वाई.एल. के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि यह मामला सुप्रीमकोर्ट में पड़ा है (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० संपत सिंह) अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी पहले मिसयूज के बारे में बताएं कि कैसे मिसयूज हुआ है?

श्री जय प्रकाश : पार्टी का नाम आया है।

प्रो० संपत सिंह : मुख्य मंत्री राहत कोष में जो पैसा आता है वह पार्टी फंड में जमा नहीं किया जा सकता है।

श्री जय प्रकाश : सरकार की तरफ से आपकी अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल गया उसमें जो कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्ष है उसको लेकर नहीं गए, हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार थे।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के सदस्यों से विनती करना चाहता हूँ कि ये इस बात की जानकारी दें कि हरियाणा विधान सभा के किसी भी मैंबर ने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से या स्पीकर साहब आप से विनती की हो कि कोई राजनैतिक पार्टी का दल जा रहा है। हमारी सरकार ने चार डिविजनों से अलग-अलग अधिकारी आई०ए०एस० या एच०सी०एस० से कम रैंक के नहीं भेजे उससे निम्न स्तर का कोई अधिकारी नहीं गया किसी मैंबर ने लिखकर ये रिक्वैस्ट की हो तो बताएं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कमेटी गठित होती है चाहे वह विधान सभा की हो चाहे गवर्नमैंट की हो उसमें रिक्वैस्ट नहीं करनी होती है।

श्री धीर पाल सिंह : कमेटी गठित नहीं हुई आपको रिक्वैस्ट करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : अब भी चले जाएं, अब भी कोई बात नहीं है आप जा सकते हैं।

श्री जय प्रकाश : एस०वाई०एल० का जहां तक मामला है यह हमारी लाइफलाइन है 1987 के चुनाव से पहले जब विधान सभा का चुनाव हुआ था तो आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने नारा दिया था उस नारे को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आज प्रदेश में जो सरकार है क्या उसने कभी यह महसूस किया है कि प्रदेश को एस०वाई०एल० नहर की जरूरत है? आज पूरे प्रदेश के लोग यह चाहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एस०वाई०एल० नहर का काम पूरा हो। पिछले डेढ़ वर्ष से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार इस प्रदेश में कायम है। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यह बताएंगे कि पिछले डेढ़ वर्ष में एस०वाई०एल० नहर बनाने के काम के लिए उन्होंने क्या काम किया है? मैं

यह मानता हूं कि मामला सब ज्यूडिस है। लेकिन क्या ऐसी बात नहीं हो सकती है कि जिस तरह केन्द्र सरकार ने इंटरवीन करके कावेरी नदी के मामले को सुलझाने का काम किया है उसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर इस मामले का समाधान करें जिस तरह वे दूसरे सियासी मामलों में इकट्ठे बैठकर बात करते हैं उसी तरह इस मामले में भी काम कर सकते हैं। यह मामला प्रदेश के लोगों के लिए पानी का सवाल है और प्रदेश की रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है। मामला चाहे अदालत में पैंडिंग हो परन्तु अगर इसका हल करने के लिए प्रयत्न किए जायें तो यह काम अवश्य हो सकता है। जब हमारे रिश्ते पंजाब से मधुर हैं तो सामाजिक तौर पर इस समस्या का निदान करके यह मामला सुलझा लेना चाहिए था। परन्तु यह कहकर कि मामला अदालत में विचाराधीन है एस०वाई०एल० नहर के मामले की हम मुस्तैदी से पैरवी कर रहे हैं इससे मसला हल नहीं होगा। इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया। अगर हरियाणा सरकार चाहे तो भाईचारे के नाते मिल बैठकर इस मामले को सुलझा सकती है। 1987 में और 1989 में जो सरकार बनी थी जिसमें मैं भी शामिल था, उस समय यह कहकर जनता से वोट लिये गये थे कि हम एस०वाई०एल० नहर का निर्माण करवायेंगे परन्तु उस वक्त इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई लेकिन इस बारे कोई बात नहीं हो सकी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से इस प्रदेश में विराजमान है परन्तु इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है जोकि एक चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं। आने वाले समय में अगर यह सरकार लोगों को यह कहेगी कि क्योंकि मामला सब-ज्यूडिस था इसलिए हम कुछ नहीं कर सके तो लोग इस बात को नहीं मानेंगे। इस मामले का समाधान इस सरकार को जल्दी से जल्दी निकाल लेना चाहिए।

जहां तक 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की बात है, अध्यक्ष महोदय, कई साथियों ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने के लिए इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जो पैसा डी०आर०डी०ए०, एच०आर०डी०एफ० और जवाहर रोजगार योजना में ए०डी०सी० लेवल के अधिकारी खर्च किया करते थे और ज्यादा से ज्यादा वे उस हल्के के एम०एल०ए० या एम०पी० से पूछ लिया करते थे कि इस पैसे को किस ढंग से खर्च किया जाये। परन्तु अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सस्ती सत्ता तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए 1999-2000 के वर्ष में 500 करोड़ रुपया सड़कों को बनवाने के लिए और रिटेनिंग वाल बनवाने के लिए खर्च करने को दिया है और यहां तक कि डी०सी० लेवल का पैसा भी मुख्यमंत्री जी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। (विघ्न) सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में टी०ए०/डी०ए० पर ज्यादा खर्च हो रहा है और जो विकास है वह कम हो रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार यह कहा कि हम कृषक को मरने नहीं देंगे। पिछले धान के सीज़न में हमारे कृषि मंत्री महोदय ने कहा कि हमने किसानों का 60 प्रतिशत धान खरीदा है। लेकिन इसके लिए मैं यह ऐतराज करता हूं। किसानों का 30 प्रतिशत धान घाटे के भाव से खरीदकर किसानों को लूटा गया, सरकार यह देखे कि उसके लिए कौन जिम्मेवार है। किसानों से 400/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जबकि नरवाना से खनौरी मण्डी सात किलोमीटर है, वहां जाकर किसानों ने 540/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा है। इसके लिए कौन दोषी है। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार इसको माने या न माने, यह मेरे बस की बात नहीं है। अखबारों में चर्चा आई कि हरियाणा सरकार ने उस वक्त राईस मिलर्ज़ के साथ समझौते किये। क्या समझौते किए यह तो भगवान जाने। राईस मिलर्ज़ के दबाव में आ कर जो किसानों के हितों

[श्री जय प्रकाश]

के साथ सौदेबाजी हुई और उनकी फसल को लूटा गया, यह एक निंदनीय बात है। उसके बावजूद भी कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सारा धान खरीद लिया। कृषि मंत्री जी आपके इलाके में पटियाला की तरफ से धान गई है और धान कौड़ियों के भाव लूटा गया है।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी स्टेट का अनाज दूसरी स्टेट न जा सके। हमारी सरकार ने जब महसूस किया कि पंजाब स्टेट या दूसरे राज्यों से व्यापारी सस्ती जीरी खरीद कर हमारी स्टेट में ला रहे हैं तो हमने इसका इंतजाम करवाया। जीरी लाने वाले ट्रकों को रोका, सिर्फ ट्रालियों से लाने वाले किसानों को नहीं रोका क्योंकि उनको पहले भी नहीं रोका जाता था। यह बात निराधार है कि हमने 30 प्रतिशत जीरी सस्ती खरीदी, हमने सारी जीरी ठीक रेट पर बिकवाई है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के किसान का गन्ना शूगर मिल्ज़ खरीद रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कैथल में लगातार 7 दिन से किसानों ने धरना दिया और 60 क्विंटल के पीछे 3 क्विंटल की कटौती की गई। परसों करनाल में इस बारे में हड़ताल हुई। यह सरकार किसानों की हमदर्द बनती है। इनकी एक वर्ष की सरकार के राज में किसानों की माली हालत इतनी कमजोर हो गई है कि क्या बताऊं। जब ये लोग लोगों के बीच जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि यह सरकार कितनी लोकप्रिय है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है, सिंचाई के मामले को लेकर सरकार ने कई दिनों तक ब्यान दिए। मैं एक बात मानता हूं कि डैम में पानी की कमी हो सकती है, यह किसी के बस की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा के सिंचाई मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज से 15 दिन पहले बरवाला के भादौड़ माइनर का इलाका जहां के एम०एल०ए० कल यहां बैठे थे लेकिन आज यहां नहीं हैं, वहां उस माइनर में पानी नहीं है, वहां 15 दिन पानी आता था और 15 दिन बन्द रहता था लेकिन आज यह किसान की सरकार ऐसी बनी कि वहां 40 दिन से पानी नहीं आया। लोगों में हा–हा कार मचा हुआ है इसी कारण भिवानी की रैली में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। हमारे नारनौंद, उचाना, नरवाना, बरवाला के इलाकों में पानी नहीं है इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है या फिर हो सकता है बरवाला से जय प्रकाश एम०एल०ए० बनकर आया। इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन पानी का बंटवारा एक समान होना चाहिए। 40 दिन तक पानी नहीं आया, बिजली नहीं आई और सरकार 24 घण्टे बिजली देने की बात करती है। इस सरकार ने राजस्थान को पानी दे दिया। यह ठीक है कि मानवता के नाते सरकारें एक दूसरे से लेती देती रहती हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसान की गेहूं की फसल पूरी तरह से सूख रही है अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी खेती किया करते थे लेकिन आज आप खेत में नहीं जाते होंगे, यह बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर किसान की गेहूं की फसल को पानी नहीं मिलेगा तो 10 मन किल्ले के हिसाब से यील्ड कम हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार कैसे भी प्रबन्ध करे, सरकार के सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। मुझे इस बात का पता नहीं लेकिन लोगों में चर्चा है कि मजीठा के चुनाव को लेकर पंजाब को ज्यादा पानी दे दिया गया लेकिन हमारे हिस्से में पानी कम आया। मुझे तो इस बात का पता नहीं लेकिन जनता कह रही है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी आपको जिस बात का पता हो उसी के बारे में बात करें। जिस बात की आपको जानकारी न हो उस बारे में बात न करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, लोग यह बात कह रहे हैं कि हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब को दे दिया।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरे माननीय साथी धर्मवीर जी का हल्का, जय प्रकाश जी का हल्का, रोहतक, सोनीपत, जींद, पानीपत और रिवाड़ी आदि जिलों का एरिया यमुना के पानी पर आश्रित है। मेरे विपक्ष के भाई राजनीति कर रहे हैं, ये करें, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं। लेकिन ये लोग जानबूझकर बकरी के तीन थन वाली बात कर रहे हैं। इस समय वैस्टर्न यमुना कैनाल में 1200 क्युसिक फुट पानी रह गया है और भाखड़ा कैनाल का भी जल स्तर नीचे गिर गया है। बिजली तो पाकिस्तान से, आसाम से या कर्नाटक से कहीं से भी लाई जा सकती है लेकिन पानी लाने के तो मेन दो ही चैनल हैं और इनमें पानी की कमी है, यह हमारी सरकार की मजबूरी है।

चौधरी जय प्रकाश : सर, यह सब सरकार की अक्षमता के कारण हो रहा है। जब हमारी सरकार आयेगी उस समय हम पूरा पानी देंगे। 1995 में जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय मौजूदा सरकार ने कहा था कि यमुना जल समझौता गलत हुआ है और कहा था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो वे इस समझौते को दोबारा से करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि अपनी सरकार बनने के बाद क्या इस बारे में उन्होंने कोई कदम उठाया है, कभी इस बारे में सोचा है? साथ लगते राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से इस बारे में कभी कोई बात की है? जहां तक मैं समझता हूँ इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एम०आई०टी०सी० के टूटे हुए नालों की तरफ दिलाना चाहूँगा। चुनाव के वक्त मौजूदा सरकार ने घोषणा की थी कि एम०आई०टी०सी० के सभी नालों को रिपेयर किया जायेगा और पैसे सरकार देगी। लेकिन बरवाला के 10 गांवों के नाले टूटे हुए हैं, उनको सरकार ने रिपेयर नहीं करवाया। अधिकारी भी इस बारे में कोई बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं पानी की कमी है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इस तरह के नाले पूरे प्रदेश में जल्दी ही ठीक करवा दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी आप 5 मिनट में समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी चर्चा समाप्त कर दूँगा। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी सरकार के समय में मैक्सी कैब्ज को परमिट दिये थे ताकि जो हजारों बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले और ऐसा हुआ भी। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो यह कहकर सत्ता में आई थी कि हजारों हाथों को रोजगार दिया जायेगा लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। मौजूदा हरियाणा सरकार अब इन मैक्सीकैब्ज के परमिट को 31 मार्च से समाप्त कर रही है और हजारों युवकों को बेरोजगारी में धकेल रही है। (शोर एवं व्यवधान) दूसरी तरफ जो नई परिवहन स्कीम बनाई है उसमें 10 हजार रुपये फीस रखी है जो बहुत ज्यादा है। एक शिक्षित बेरोजगार युवक इतने पैसे कहां से लायेगा? पुलिस भर्ती के फार्म की फीस 500 रुपये रखी गई है जो बहुत ज्यादा है। यह सरकार एक अक्षम सरकार है (शोर एवं व्यवधान) जिसने हरियाणा प्रदेश के शिक्षित नौजवानों से भी पैसा लूटने की कोशिश की है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह ********

श्री अध्यक्ष : बलबीर सिंह जी, आप अपना प्वाईंट ऑफ आर्डर कहिये (शोर)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल तक तो मेरा साथी हमारे नेता जी के पांव पकड़ा करता था और आज उनको गाली दे रहा है। (शोर) इसकी आंखों में थोड़ी-बहुत तो समझ होनी चाहिए। (शोर) बाकी जो प्वाईंट आफ आर्डर की बात है तो मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूँगा कि सम्मानित साथी चौधरी बंसी लाल की सरकार को बढ़िया बताया करता था। अगर उस सरकार की कारगुजारियां बढ़िया थीं तो उन्हें अब मान लें। ये कहीं तो डटे। (शोर) कल से सम्मानित साथी अपनी छाती के बटन तोड़ रहा है और यह बात कह रहा है कि जब हम जनता के बीच जाएंगे तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने नेता जी से एक बात कहने की इजाजत लेना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि वे इस बात की इजाजत दे भी देंगे। कांग्रेस के भाई बार-बार यह कह रहे हैं कि जनता हमें अपने हल्कों में घुसने नहीं देगी। मैं आपके माध्यम से इनको चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस के इस समय 21 सदस्य है और इनमें से जिसका जी चाहे वह मेरे हलके से आकर चुनाव लड़ ले। मेरे नेता मुझे इस बात की इजाजत भी दे देंगे। मैं यह भी नहीं चाहता कि इनका कोई सदस्य रिजाइन देकर चुनाव लड़े। अगर इनकी नाड़ी में दम हो तो जो जी चाहे वह मेरे हलके महम से मेरे मुकाबले में चुनाव लड़े।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरी नाड़ियों में बहुत दम है। अब आप कहेंगे कि मैं अपनी लाइन से बाहर जाकर बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ********से पाला पड़ जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह अनपार्लियामैंटरी शब्द है इसे रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी जय प्रकाश : मेरी नसों में तो 1996 में बहुत मजबूती थी जब नरवाना की सड़कों पर हमने इनकी नसें बजाई थीं। (शोर) यह रिकार्ड की बात है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें। (शोर)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, 1998 के चुनाव में इनैलो ने बसपा का लत्ता ओढ़ा और बाजपेयी साहब को कहते थे कि यह कुंवारा आदमी है जो अपना घर नहीं बसा सका तो देश को कैसे चलाएगा। (शोर) फिर बाद में इनैलो ने उनका समर्थन कर दिया। (शोर) कांशी राम वाली बसपा का लत्ता ओढ़ा था और बाद में भाजपा का समर्थन किया है। यह इनकी बात है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपके दो मिनट बाकी हैं।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जितना समय इन्होंने मेरा बेकार किया है वह समय तो आप मुझे देंगे ही। (शोर) अध्यक्ष महोदय, जब डीजल का भाव एक रुपया प्रति लीटर बढ़ा था तो इनैलो ने केन्द्र की वाजपेयी सरकार से समर्थन वापिस ले लिया था और आज डीजल का भाव 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया तो कहते हैं कि सरकार की मजबूरी है। स्पीकर साहब, इस तरह की दोगली बातें जय प्रकाश नहीं करता। हम जहां रहते हैं वहां ठाठ से रहते हैं नहीं तो छोड़ कर चले जाते हैं। (शोर) इनकी तरह हमारे ऊपर कम्बल नहीं डाले जाते।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप बैठिये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बैठिए। आपके पास बोलने के लिये अब कुछ है ही नहीं।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बोलने के लिए बहुत मैटीरियल है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अब बैठ जाइए और कोई बोल लेगा। (शोर) ठीक है, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे को पूरा टाइम दें। अध्यक्ष महोदय, अब बेरोजगारों की बात आती है। सरकार कन्फैड में रिट्रैंचमैंट कर रही है। 350 कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप को बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं। आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सरकार कन्फेड को बन्द कर रही है, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम और कुछ दूसरी कारपोरेशंज को बन्द कर रही है फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्पीकर साहब, जिन सिपाहियों की नियुक्ति रद्द की गई है मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा। जैसे पंजाब में डाक्टरों की नियुक्ति रद्द हुई थी और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने फ्राखदिली दिखा कर उन डाक्टरों को दोबारा से नियुक्ति दी थी। उसी तरह से हरियाणा के मुख्य मंत्री फ्राखदिली दिखा कर उन 1600 सिपाहियों को दोबारा नियुक्ति दें। मैं कहता हूँ जो सिपाही भर्ती किए गए थे उनका क्या कसूर है। यदि उनकी भर्ती में अफसरों की गलती है तो उनको सजा दें। उन सिपाहियों का क्या कसूर है, उनको दोबारा नियुक्ति दी जानी चाहिए। अगर आप उनको दोबारा नियुक्ति नहीं देंगे तो हरियाणा के बेरोजगार नौजवान आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है, अब आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने के लिए आप 10 मिनट का समय और दे दें ताकि ये अपनी बात कह सकें। रूलिंग पार्टी के महानुभावों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने से 10 मिनट तो वैसे ही इनके खराब हो गए। (शोर)

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, यह राज्यपाल महोदय का पुलिन्दा है। मैं इसका विरोध करने के लिए बोलना चाहता हूँ इसलिए आप मुझे बोलने का समय दें। अभी थोड़ी देर पहले बलबीर सिंह जी ने हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को चेलेंज किया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी मैम्बर मेरे मुकाबले में मेरे हल्के से चुनाव लड़ ले तो स्पीकर साहब, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाली साहब अपना अस्तिफा दे दें (शोर)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे मुख्य मंत्री जी मुझे इजाजत देंगे तो मैं भी इनके मुकाबले में मेरे हल्के से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। (शोर)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, केवल मात्र अल्फाजबाजी से बात नहीं बनती है। प्रजातंत्र में नियम हैं, रूलज़ हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है। चुनावों की प्रणाली भी है। स्टेट असैम्बलीज के, पार्लियामैंट और पंचायतों के हरेक के चुनाव होते हैं और उनके अपनी-अपनी टर्म्ज के मुताबिक चुनाव होते हैं। स्पीकर साहब, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत रखो आपको

[प्रो० सम्पत सिंह]

तो विपक्ष में एक साल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप हिम्मत रखो। आप बार-बार चुनाव-चुनाव कह रहे हैं। पिछली बार जब जुलाई के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार सम्भाली तो सितम्बर में पार्लियामेंट के चुनाव आए उनमें हरियाणा की 10 की 10 सीट इंडियन नैशनल लोकदल और बी०जे०पी० को मिलीं। कांग्रेस पार्टी को एक कातर भी नहीं मिली। उसके बाद फरवरी में स्टेट असैम्बली के चुनाव हुए उनमें इनको किनारे बिठा दिया और पूर्ण बहुमत ले कर इंडियन नैशनल लोकदल और बी०जे०पी० इसी तरह यहां आई। (शोर) मैं आपको चुनावों के मौके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर चुनाव आया रोड़ी हल्के का क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फरवरी में दो हल्कों नरवाना और रोड़ी से चुनाव जीता था तो इनको एक जगह खाली करनी थी वह इन्होंने रोड़ी की सीट खाली कर दी। उस सीट को खाली करने के बाद फिर वहां का चुनाव लड़ने का , वहां जनमत लेने का मौका आया। जब सरकार वहां पर जनमत ले रही थी तो उस समय विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश की गई कि पिछली बार तो इन्होंने वहां से जनमत ले लिया इस बार इस जनमत को खत्म किया जाए। इन्होंने रोड़ी हल्के के चुनावों में पूरी कोशिश की लेकिन रोड़ी हल्के के चुनाव में हमने इनको बहुत बुरी तरह से धूल चटाई। स्पीकर साहब, रोड़ी हल्के के चुनाव में इनको जो धूल चटाई वह अपने आप में एक मिसाल बन गई वह अपने आप में एक इतिहास बन गया। फिर भी ये चुनाव की बात करते हैं। जब भी चुनाव का कोई वक्त आता है हर बार इनको धूल चटाई जाती है। अल्फाजबाजी और चेलेंजबाजी करने से बात नहीं बनती। स्पीकर साहब, जब भी प्रदेश में चुनाव के मौके आते हैं उनमें हर बार इनको मार पड़ती है। अब ये वह बात कर रहे हैं जैसे कोई पहलवान हारने के बाद कहता है कि फिर आ जा। यह कोई बात नहीं है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * *(शोर)

श्री अध्यक्ष : माननीय जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। जय प्रकाश जी अब आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न)।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री भगवान सहाय रावत जी ने जो समर्थन का प्रस्ताव सदन में रखा था मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, 5 तारीख से यहां पर सैशन चल रहा है। सभी पार्टियों के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां पर रखे। मुझे भी महामहिम के इस अभिभाषण पर आपने बोलने का जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले भी यहां पर बैठे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे थे और अपने-अपने हल्कों की बात कही थी। सभी साथी अपने हल्के की समस्याओं के साथ हरियाणा प्रदेश की जो समस्याएं थीं उन के बारे में भी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जो बात सदन के अन्दर अपने सम्मानित सदस्य रख रहे थे उसमें जो कुछ सुझाव आये थे वे काफी हद तक ठीक आये थे लेकिन कुछ साथियों द्वारा जो सही बातें थीं उनको भी गलत बताने की कोशिश की जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बार फरीदाबाद से विधायक बन कर इस विधान सभा में पहुंचा हूँ यानि वहां के लोगों ने मुझे चुन करके यहां पर भेजा है। मैंने भी अपने क्षेत्र के अन्दर अपने लोगों की समस्याओं की आवाज उठायी थी और इस विधान सभा में भी मैं समय-समय पर अपने इलाके की आवाज उठाता रहा रहा हूँ और अपने विचार आपके सामने रखता रहा हूँ ताकि मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। अध्यक्ष महोदय, कई बार मन

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

को बड़ी तकलीफ होती थी, दुख होता था जब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी हविपा की सरकार थी, उन सरकारों के समय में हमारे इलाके की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने अपने समय में जो काम किये थे उनको जनता भी जानती है और ये लोग भी जानते हैं। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है। इस सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं विपक्ष को उनको सराहना चाहिए न कि उन अच्छे कामों की भी ये लोग बुराई करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गुजरात के अन्दर बहुत अच्छा काम किया है। गुजरात में भूकंप के अन्दर जो लोग मरे और जो लोग घर से बेघर हो गए थे, उन परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने तरीके से व लोगों से अपील करके पैसा इकट्ठा किया। सरकार की अपील पर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी काफी पैसा आया। हमारी सरकार ने वहां पर जितना अच्छा काम किया उसकी हर जगह पर प्रशंसा हुई है लेकिन कुछ लोगों ने इस काम को भी राजनैतिक रंग देने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी सराहना करने में विपक्ष को भी आगे आना चाहिए और मेरा अनुरोध है कि इन अच्छे कामों को राजनैतिक रूप देने की कोशिश न की जाये। इसके लिए अपनी पार्टी के नाम को और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कोई बात कहे यह ठीक नहीं है। यह तो इन्सानियत का फर्ज बनता था। चाहे वह कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी संस्था है किसी को भी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप वहां पर चल कर मदद करें। लोग खुद ही वहां पहुंच कर सेवा में लग गए थे। जिससे जितना बन पड़ा वहां पर उसने उतना काम किया और अपना सहयोग भी दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार को कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां पर चलें। सरकार को यह लगा कि वहां के लोगों पर दैवीय विपत्ति आई है, परमात्मा की ओर से उन पर प्रकोप पड़ा है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक दुखी था। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार को भी और यहां की जनता को भी उससे दुख हुआ और वहां के लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। वहां पर चाहे हरियाणा सरकार की मशीनरी का सहयोग रहा, चाहे लोगों का सहयोग रहा लेकिन लोगों के हित के लिए उनकी सेवा के लिए काम हुआ। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम तभी होने सम्भव होते हैं जब उनका नेतृत्व करने वाला कोई आदमी होता है। मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में यह काम हुआ है। उन्होंने लोगों से आवाहन किया और अधिक से अधिक लोग वहां पर सहायता के लिए पहुंचे जिसके कारण आज पूरे देश के अन्दर हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है और देश का हर नागरिक यह कहता है कि हरियाणा ने जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य यह बात कहते हैं कि यह काम सही तरीके से नहीं हुआ है मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि वे इस बारे में अपने सुझाव दें कि काम को किस प्रकार से और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वह बहुत ही विकट है और लाखों लोग बेघर-बार हो गए हैं। उनके पुनर्वास के लिए उन्हें कोई ठोस सुझाव देने चाहिए कि सरकार इस प्रकार से कुछ और काम कर ले जिससे कि वहां के लोगों को कुछ और राहत मिल सके। इससे लोगों को फायदा मिलेगा। जो लोग वहां पर जा कर लोगों की कुछ मदद नहीं कर सके उन्हें चाहिए कि वे सरकार के अच्छे कामों में कम से कम रुकावट न डाले। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझ से पूर्व जो सम्मानित सदस्य बोले सत्तापक्ष के लोगों ने सरकार के काम की सराहना की है और माननीय विपक्ष के लोग भी बोलें। मैं यह कहता हूँ कि अपनी बात को कहना चाहिए और अगर सरकार ने कहीं कोई गलत काम किया है तो उसे कहना चाहिए। मुझे याद है हमारे मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर बार

[श्री चन्द्र भाटिया]

एक बात कहा करते हैं कि हमें विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। अगर हम कोई गलत बात करते हैं तो विपक्ष हमें बताए ताकि हम अपनी उस गलती को सुधार सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे काम होते हैं उनमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हमारे सभी साथी अपनी बात मुख्य मंत्री जी के सामने कहते हैं और उन्होंने कह रखा है कि वे हर बात पर गौर करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे इससे हरियाणा की जनता का हित होगा। इस सरकार को बने हुए डेढ़ साल का समय हो गया है और इससे पहले हविपा की सरकार थी। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी यहां पर बैठे हुए हैं, इनका समय भी रहा है और आज ये हमारे सम्मानित सदस्य हैं। जिस समय इनके पास ताकत थी इनके हाथ में पावर थी अगर ये चाहते तो उस समय स्टेट के लोगों का खूब भला कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा का सैशन चल रहा है और जनता ने हमें सैशन के दिन यहां पर आ कर उनकी समस्याओं और उनकी बात सरकार के सामने कहने के लिए चुन कर भेजा है। हमें यह मालूम हुआ है कि जिस दिन सैशन चल रहा था उस दिन आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी कुछ हल्कों में अपनी जनसभाएं कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि ये जनसभाएं तो चलती रहती हैं लेकिन जब सैशन चल रहा होता है उस समय हमारा स्थान सैशन में है ताकि जनता की बात और लोगों की समस्याओं की तरफ हम सरकार का ध्यान दिला सकें लेकिन चौधरी बंसी लाल जी अपनी समस्याओं को ले कर जनसभाओं में जा रहे हैं जब कि इनको अपनी बात को यहां पर कहना चाहिए। आज इनको जनता के बीच में जाने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है। जब कलम इनके अपने हाथ में थी उस समय अपनी कलम चला लेते। अगर उस वक्त इन्होंने जनता के हित में अपनी कलम चलाई होती तो आज इनको जनता के बीच में जाने की जरूरत क्यों पड़ती।

मैं यह कहना चाहूँगा कि तीन-साढ़े तीन साल जब इनके पास राज था तो इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ क्या किया यह तो हरियाणा की जनता भी जानती है और अधिकारी भी जानते हैं। (विघ्न) बंसी लाल जी ने जो कहा है कि इन्होंने तो हमें अपनी कार से बाहर निकाल दिया था और हरियाणा की जनता ने तो इनको सत्ता से निकाल कर विपक्ष में बिठा दिया। लेकिन आज भी इनका अहंकार नहीं गया है जो इस तरह की बात यहाँ पर बैठे-बैठे कह रहे हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था फिर ये तो चीज ही क्या हैं। (विघ्न) हमें लोगों ने नहीं पीटा, पीटने वाले तो सत्ता से विपक्ष बैठे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन जो असल बात है वह तो हमें कहनी चाहिए उसको कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब इनका राज था तब तो इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया और अब ये जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इनको इसकी क्या जरूरत है ? जब इनके राज में ये टैक्स लगाते थे तो हम भी इनको कहते थे कि इतने टैक्स न लगाएं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और श्री भजन लाल जी ने भी कहा था कि इतने टैक्स न लगाएं तो ये कहते थे कि टैक्स लगेंगे तो ही सरकार चलेगी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है वह देखें। चौधरी बंसी लाल जी अखबारों में स्टेटमैंट देते हैं कि मेरी सरकार आ गई तो मैं हाऊस टैक्स माफ कर दूंगा। लेकिन जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने हरियाणा की जनता के ऊपर खूब टैक्स लगाए थे और आज टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जी आज यहां पर बैठे हुए हैं इन्होंने हमें दबाने की पूरी कोशिश की, दुनिया भर के मुकद्दमें हमारे ऊपर चलाए गए। इनकी तो पूरी कोशिश थी कि चन्द्र भाटिया अगली दफा हाउस में न पहुँचे। तब हम सोचते थे कि चौधरी बंसी लाल जो सत्ता में है अगली दफा यहां अपोजिशन में बैठें और आज ये यहां पर बैठे हुए हैं। अब ये सपना लेना छोड़ दें कि हरियाणा की जनता इनको दोबारा से सत्ता में बिठाएगी। अब

वह समय नहीं आने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे मन की पीड़ा है जो मैं यहां पर बता रहा हूँ। अगर ये उस वक्त ध्यान से चलते तो इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज भी ये फख्र से कहते हैं कि चन्द्र भाटिया को कार से उतार दिया था। मैं इनसे यह पूछना चाहूँगा कि वह कार किसने दी हुई थी ? इन्हें भी सभी विधायक साथियों ने ही बनाया था और कार भी हरियाणा सरकार की ही थी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यही रही कि जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को बी०जे०पी० समर्थन दे रही थी। उस समय कांग्रेस के हमारे साथी बड़े जोर शोर से कहते थे कि इन्होंने लोगों पर अत्याचार कर रखा है इसलिए आप इनका साथ छोड़ो। लेकिन जब बी०जे०पी० ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो कांग्रेस ने तुरन्त उस सरकार को अपना समर्थन दे दिया। इस तरह से इन्होंने हरियाणा की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन हरियाणा की जनता गुमराह नहीं हुई। बाद में हरियाणा की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्य मंत्री बनाया। (विघ्न) ये बातें बताना जरूरी है ताकि लोगों को भी पता लगे इसीलिए मैं बार-बार इन बातों को कह रहा हूँ। यहां हाउस से बाहर जाने के बाद भी हम हरियाणा की जनता को ये सारी बातें बताएंगे जो आपके सामने रखी हैं। ये बातें इनको भी माननी पड़ेंगी। इन्होंने लोगों को गुमराह करने का तरीका अपना रखा है। मुख्य मंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। इसके लिए चाहे पैसा सैंटर की सरकार से आया हो या हरियाणा की सरकार ने दिया हो लेकिन बात यह है कि पैसा तो हरियाणा सरकार ने ही खर्च किया है। जब मुख्य मंत्री जी लोगों के बीच में जा कर बैठते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपनी परेशानियां बताओ तथा जब वे अपनी परेशानियां बताते हैं तो वे उनका वहीं पर समाधान करते हैं। इसके लिए उनकी सराहना तो करनी ही चाहिए। कल हमारे एक साथी डॉ० जय प्रकाश जी बोलते हुए कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी से हमने अपनी समस्याओं के बारे में टेलीफोन पर बात की लेकिन मैं उन को बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा भी था जब मुख्य मंत्री जी से टेलीफोन पर बात करना तो दूर उनके नजदीक भी आप नहीं जा सकते थे। आदरणीय बंसी लाल जी के समय में उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। हम जब उनसे अपनी बात कहने के लिए मिलने के लिए उनके पी०ए० से बात करते थे तो पहले तो बहुत मुश्किल से उनसे मुलाकात का समय मिलता था और मिलता भी था तो वे अपने निवास पर बहुत अन्दर वाले कमरे में मिलते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, हरियाणा की जनता से मिलने की उसकी बात तो आप छोड़ ही दें। इनके पास उस समय पहुँचा ही नहीं जा सकता था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी ताकतवर होता है तो उस को जनता का भी ख्याल रखना चाहिए जिसने उसको कुर्सी दे रखी है। जनता ने उनको कुर्सी इसलिए दी थी ताकि वे उसके हितों का ध्यान रखें।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। क्या ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं ?

श्री चन्द्र भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सम्मानित सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा अगर उनको मेरी बात से तकलीफ हो रही है तो उस के लिए मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा। लेकिन सही बात को कहने का हमारा अधिकार है। एक समय था जब हमें यहां बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। आज मैं आप का धन्यवाद करता हूँ कि आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। आप इस में ब्रेक न लगायें ताकि हमारी पिछली कसर निकल सके। मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहना चाहूँगा कि हरियाणा की भोली-भाली जनता को दोबारा से गुमराह करने की कोशिश न करें। अगर ये इस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो हम हरियाणा की जनता के सामने

[श्री चन्द्र भाटिया]

जाएंगे और असलियत जनता को बताएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में लोगों का कोई काम नहीं हुआ था लेकिन इस समय मेरे क्षेत्र में काफी काम हो रहे हैं। इस के साथ ही साथ मैं यह अनुरोध करूँगा कि काम की गति में तेजी लाई जाये। अब मैं विधायकों की ग्रांट के बारे में कहना चाहूँगा। वैसे तो 'सरकार आप के द्वार' कार्यक्रम जब चलता है तो मुख्य मंत्री जी काफी पैसे की तुरंत घोषणा कर देते हैं। सरकार इस बात पर विचार करे कि 50 लाख रुपये की जो विधायकों की ग्रांट होती थी उसे बहाल किया जाए। किसी समय किसी विधायक को अपने क्षेत्र में कोई जरूरी कार्य करवाने पड़ जाते हैं और कोई व्यक्ति आकर काम की कहता है तो वह करा सकते हैं। अब मैं विधायकों को दिये जाने वाले कार लोन के बारे में कहना चाहूँगा। कार लोन चार लाख रुपये दिया जाता है और मकान के लिए भी चार लाख लोन दिया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस लोन की राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से भी यह अनुरोध है......

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बजाए वित्त मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध करें।

श्री चन्द्र भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी से ही अनुरोध कर रहा हूँ कि चार लाख की जो लोन की राशि है उसे बढ़ा कर आठ लाख रुपये किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी इस बाबत एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि जो रिकवरी 2 परसैंट की जा रही है उसको पहले की तरह से एक परसैंट किया जाए। आप चन्द्र भाटिया की बात पर भी गौर करें। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं फरीदाबाद में जो बी.के. होस्पीटल बना है, उस के बारे में कहना चाहूँगा। (विघ्न)

डा० बिशनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों के दूसरे भत्ते भी बढ़ाये जाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, आप अभी बैठिये।

श्री चन्द्र भाटिया : सर, उस होस्पिटल की एक बिल्डिंग तो बन गई है और दो बिल्डिंगज़ और बननी हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से अनुरोध है कि उन दो बिल्डिंगज को भी बनाया जाये जिससे फरीदाबाद के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो दवाइयों की कमी है उसको भी पूरा किया जाये। फरीदाबाद में रिन्यूअल योजना शुरू की गई है जिस के ऊपर 44 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उसका काम चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसका काम तेजी से किया जाये ताकि फरीदाबाद के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। पानी के नये ट्यूबवैल्ज कई जगह लगाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भाटिया जी अब आप वाईंडअप कीजिए।

श्री चन्द्र भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे हल्के में सड़कों का काम चल रहा है परन्तु कई जगह सड़कों की हालत काफी खराब है, उन सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जाये। मेरे हल्के में 28 गांव पड़ते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन सारे गांवों की सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य वे जल्दी पूरा करवायें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। परन्तु उससे पहले मैं आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको अगर मेरे

द्वारा कही बात का बुरा लगा है उसके लिए मैं उनसे यह कहूंगा कि कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कहनी चाहिये जिससे दूसरे सदस्यों को ठीक नहीं लगे। अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी बंसी लाल एम०एल०ए० द्वारा

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे ये *********** हैं और जो ***********में पत्थर मारेगा उसको खुद को ही छींटे लगेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था और इस माननीय सदस्य के हल्के में जाता था तो यह मेरे आगे पीछे घूमता था। उनकी पार्टी के नेता भी बैठे हुये हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और मेरे बारे में बड़ी तारीफ करता था।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी आप बैठिये। बंसी लाल जी ने जो अनपार्लियामैन्ट्री शब्द इस्तेमाल किये हैं रिकॉर्ड न किये जायें।

श्री चन्द्र भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सरकार का पहला सैशन था और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी यहां बैठे हुये थे तो उस समय चौधरी बंसीलाल जी ने यह कहा था कि यह सरकार 6 महीने भी नहीं चल पायेगी लेकिन आज इस सरकार को 6 महीने से ऊपर हो गये हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे पीछे घूमता था तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी बात मनवाने के लिये तीन महीने तक संघर्ष किया था और आखिर में इन्हें समझौता करना पड़ा था।

श्री उपाध्यक्ष : भाटिया जी आप बैठिये। चौधरी धर्मबीर सिंह जी आप बोलिये।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मबीर सिंह (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 30 मिनट बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी धर्मबीर जी, आप बोलने का समय अपने आप फिक्स न करें।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो किताब बाबू परमानंद जी ने पढ़ी थी उनमें से कुछ बातों का मैं समर्थन करूंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक वरिष्ठ विधायक हैं। कम से कम राज्यपाल महोदय के नाम से पहले महामहिम शब्द तो लगा लें।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण की मैं ज्यादातर बातों का विरोध करते हुए सबसे पहले तो सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। इस हरियाणा प्रदेश को बने हुए 34-35 साल हो गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, कोई पार्टी कहती है कि रावी ब्यास के सरप्लस पानी को हम इस प्रदेश को लाकर देंगे। एक आध पार्टी गंगा के पानी को लाने की बात करती है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इन दिनों इस प्रदेश के आधे हिस्से में पीने तक का पानी नहीं है, खेतों के लिए तो पानी की बात ही अलग है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार हमारी सरकारें और सभी पार्टियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी धीरपाल जी कह रहे थे कि यमुना में 1200 क्यूसिक पानी है, ये गलत आंकड़े पेश करते हैं। आज के दिन यमुना में 1800 क्यूसिक पानी है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि पीछे के दिनों सबसे कम यमुना का पानी 1200 क्यूसिक रहा है लेकिन अब आज के दिन यह पानी बढ़ गया है।

श्री धर्मबीर सिंह : ठीक है जी। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में 9100-9200 क्यूसिक पानी चल रहा है। हमारे प्रदेश का टोटल इलाका एक करोड़ 15 लाख एकड़ है। सिर्फ 95 लाख एकड़ एरिये में कम या ज्यादा पानी है। यह कितनी बुरी बात है कि 32 लाख एकड़ जमीन में 6700 क्यूसिक पानी है और 63 लाख एकड़ जमीन पर 3400 क्यूसिक पानी है। यह भेदभाव क्यों है। क्या किसी का फर्ज नहीं बनता कि हम इस पानी का बराबर बंटवारा करें। दड़बा कलां में मुख्य मंत्री महोदय गए थे तो लोगों की एक ही बात थी कि पानी ज्यादा होने की वजह से वहां सेम आ गया है। और सरकार ने पानी निकालने के लिए 12 करोड़ रुपये वहां के लिए मंजूर कर दिए। दूसरी तरफ 60 दिन पानी है अगर लोग एजीटेशन करते हैं तो उनको जेलों में ठोक दिया जाता है। रावी नदी के ऊपर रणजीत सागर डैम पूरा हो गया है और अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। पंजाब के पास आज कोई बहाना नहीं है कि रावी ब्यास के सरप्लस पानी को हम नहीं देंगे। क्योंकि जब तक रणजीत सागर डैम पूरा नहीं हुआ था तब तो हम मानते थे कि हरियाणा में वह पानी नहीं दिया जाएगा लेकिन आज जब वह डैम पूरा हो गया है तो उनके पास कोई बहाना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली को वे भाखड़ा नहर से पानी देते हैं। आज की सरकारें, पिछली सरकारें भी मानती हैं कि नरवाना मेन ब्रांच जिसकी कैपेसटी 4500 क्यूसिक पानी की है लेकिन उसमें केवल 3400 क्यूसिक पानी आता है क्योंकि उसकी लाईडनिंग नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई फिर भी दिल्ली शहर को इसी मेन लाईन द्वारा भाखड़ा का 1200 क्यूसिक पानी दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम दिल्ली सरकार से यह नहीं कह सकते कि हमारी नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी इतनी नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके यह हाऊस दिल्ली सरकार को कहे कि आप पीने का पानी हमारी अधूरी एस०वाई०एल० के मार्फत लेकर जाएं क्योंकि यह सबका प्रश्न है। आप दक्षिणी हरियाणा में, नरवाना गांव में, कवारी, बालावास, धमाना गांवों में जाकर देखें कि वहां के लोग 6-6, 7-7 दिनों से पानी मोल ला रहे हैं। बड़वा, सीवानी और बहल के बीच का इलाका ऐसा है जहां आप जाकर देखें आम आदमी को शर्म आती है कि वहां लोग कैसे जीते हैं, वहां के लोग अपनी झांडी काट-काट कर बेचें तो भी यह सरकार झांडी काटने वाले को पकड़ती है। कैसे वे लोग गुजारा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि सबसे पहले मौजूदा पानी का बराबर बंटवारा किया जाए ताकि हम जीने के लायक हो सकें। एक तरफ पानी के ठाठ हैं तो दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है। मेरे हल्के में केरू माइनर है अगर डेढ़ साल की सरकार के दौरान एक भी दिन वहां एक भी बूंद पानी गया हो तो आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि टेल पर पानी जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार नहरी पानी भी नहीं देती, वह पार्टी की सरकार जो किसानों की सरकार है, नहरी माल माफ करने की बात करती थी। आज किसान ढाई गुणा नहरी माल दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सीवानी लिफ्ट कैनाल, जुई लिफ्ट कैनाल, जैलन लिफ्ट कैनाल कहीं भी जाकर देखें, 40 प्रतिशत से ज्यादा पानी उठाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। बार-बार आश्वासन मिलते हैं कि मोटरें ठीक करवाई जाएंगी ताकि वे पानी उठा सकें। मेहरबानी करके उनकी मशीनें ठीक करवाई जायें। बार-बार आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार बिजली के क्षेत्र में किस तरह से किसानों के साथ नाईंसाफी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले एन.टी.पी.सी. का चेयरमैन पलवल में आया था। उस समय पूछने पर उसने बताया कि थर्मल से हरियाणा को जो बिजली मिलती है वह प्रति यूनिट 1.45 रुपये

के हिसाब से मिलती है और हाईडल से बिजली प्रति यूनिट 18 पैसे के हिसाब से मिलती है। इस तरह से हमारे पास 600 मेगावाट बिजली आती है लेकिन सरकार किसान से 4 या 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लेती है। ऐसा भेदभाव किसान के साथ नहीं करना चाहिए। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही एक लाख नये ट्यूबवैल के कनैक्शन तो जरूर दिए लेकिन बिजली का लोड नहीं बढ़ाया। मुख्य मंत्री जी चाहें तो लोहारू हल्के में जाकर देखें वहां बिजली बहुत जल्दी ट्रिप कर जाती है। इसी तरह से यह समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समय सरकार ने बिजली के बकाया बिलों की रिकवरी भी काफी की है और नये ट्यूबवैल कनैक्शन दिए हैं इसलिए बिजली का लोड बढ़ाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने अभी एक दो दिन पहले ही प्रधान मंत्री जी के साथ बैठक की थी और अखबारों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक दिसम्बर के बाद ट्यूबवैल्ज के फ्लैट रेट बिल बंद कर दिए जायेंगे और हर ट्यूबवैल पर मीटर लगा दिया जायेगा। प्रति होर्स पावर पर 45 रुपये का खर्चा आयेगा, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जहां पर 10 होर्स पावर की मोटर लगी होगी वहां पर किसान पांच हजार रुपये महीने के बिजली के बिल कैसे भरेगा। आजकल तकरीबन सभी जगहों पर दक्षिणी हरियाणा में पानी का स्तर नीचे जाने के कारण 10 हार्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं। जबकि प्रति होर्स पावर खर्चा 3.50 रुपये ही आता है यह बहुत शर्म की बात है। अगर सरकार ने प्रधान मंत्री जी से इस तरह का समझौता किया है तो हम इसका विरोध करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़े-बड़े ब्यान दिए कि जो फसल ज्यादा पानी लेती है उसकी बिजाई न करें जैसे गेहूं है, कपास है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम मानते हैं कि पानी की कमी के कारण ये फसलें किसान बोना बंद कर देगा। लेकिन इसके अतिरिक्त दक्षिणी हरियाणा में जैसे सरसों, गवार आदि की फसलें बोता है तो आजकल इन फसलों का भाव बहुत कम है। पहले गवार तीन या साढ़े तीन हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता था और अब यह मुश्किल से 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। इसी तरह से सरसों पहले 1700 या 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती थी लेकिन अब यह भी 1000 या 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही बिक रही है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वाजपेयी जी से बात करें और इन फसलों के रेट बढ़ाए जायें। मौजूदा मुख्य मंत्री जी केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं और केंद्र सरकार ने यहां पर मुख्य मंत्री जी को समर्थन दे रखा है। जन स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए हैं। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पीने का पानी पूरे हरियाणा में मिलेगा। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे यहां 70 ग्राम पीने का पानी भी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दे दें तो हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। लोग 20-30 कि०मी० दूर से पीने का पानी लेकर आते हैं। इस बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अब मार्च (जिसे देशी भाषा में फाल्गुन कहा जाता है) के महीने में पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है तो जेठ और आषाढ़ में क्या हालत होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जहां कहीं मीठा पानी है वहां पर ट्यूबवैल लगाये जायें और आने वाले समय में जो समस्या आये उससे निपटा जाये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पीने के पानी की बहुत दिक्कत आ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं भवन एवं सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज के दिन सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी महेन्द्रगढ़ गये थे। वहां पर जनता में से एक आदमी ने मुख्य मंत्री जी को कहा कि एक छोटी सी सड़क उनके गांव तक बनवानी है। इस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कोई मिस्त्री हूं जो तुम्हारी सड़क बनाऊं। इसी तरह से किसी ने पीने के पानी की समस्या के बारे में कहा तो मुख्य मंत्री जी ने उसे भी कह दिया कि कुण्ड से पानी पी लो। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को यदि कोई बिजली के बारे

[श्री धर्मबीर सिंह]

में कहता है कि बिजली नहीं आती तो ये कहते हैं कि लालटेन या मोमबत्ती जला लो। हरियाणा की जनता ने बड़े विश्वास के साथ चौटाला साहब को सत्ता सौंपी थी। लोगों को बहुत आशाएं थी कि मुख्य मंत्री जी उनकी भलाई के कार्य करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार ने कम्पयूटर शिक्षा पर बहुत जोर दिया है लेकिन ये ईमानदारी से बताएं कि कम्पयूटर शिक्षा कहां पर प्रयोग करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पढ़े-लिखे बच्चे जानते हैं कि गर्मियों में एयर कंडीशन कमरों के बगैर कम्पयूटर कामयाब नहीं हो सकते। गांवों में अगर आप जाकर देखें तो स्कूलों में बिजली का होना तो दूर, स्कूलों के दरवाजे भी टूटे पड़े हैं तो फिर सरकार कैसे उन कमरों को एयर कंडीशन बना पाएगी। दूसरी ओर गांवों में सुबह और शाम को बिजली दे नहीं सकते, दिन में कम्पयूटरों के लिए बिजली का इंतजाम कैसे करेंगे। इसलिये यह भी एक गंभीर सवाल है इस बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तो कम्पयूटर खरीद लिए जाएं और बाद में उन्हें बेच दिया जाएगा। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के बारे में मेरे से पहले डाक्टर साहब ने भी काफी कुछ बताया है। मैं तो केवल भिवानी जिले के बारे में बताना चाहूँगा। वहां पर ऐसे-ऐसे दलाल छोड़ दिये गये हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। जो डाक्टर कमीशन वाली नकली दवाई नहीं लिखते उनको फिरोजपुर झिरका भेज दिया जाता है। कम से कम बीमार आदमियों के बारे में तो सरकार कुछ सोचे। प्राइवेट अस्पतालों में तो बड़े-बड़े लोग आ सकते हैं किन्तु सरकारी अस्पतालों में तो गरीब लोग ही जाते हैं। अगर वहां पर भी उन डाक्टरों को रखना चाहते हैं जो कमीशन की दवाई लिखे तो यह बहुत गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अब कोई नई बात है या पहले भी ऐसा होता था।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह अब की बात है पहले का हमें नहीं मालूम। जहां तक गांवों में विकास कार्यों की बात है तो मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूँगा कि रोड़ी हल्के का विधायक अपने हलके में जाता है तो बड़े घमण्ड से कहता है कि मेरे हलके में 118 गांव हैं और वहां हर गांव में दो करोड़ से पांच करोड़ तक विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है जबकि हम अपने हलके के गांवों में बार बार जाते हैं तो वहां पर विकास कार्यों के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलता। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में विकास के कार्यों पर हर हलके में बराबर-बराबर पैसा लगना चाहिए। विकास का पैसा किसी एक हलके में लगाने के लिये सरकार नहीं होती। यह सारे प्रदेश का पैसा है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ कि एच०आर०डी० का पैसा जो कभी केवल शहरों में लगता था वह इस बार गांवों में भी लगा। इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी को शाबाशी भी देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गलियों के काम या दूसरे छोटे-मोटे विकास के कार्य जो केवल बी०डी० एण्ड पी०ओ० लेवल के होते हैं ये काम मुख्यमंत्री के नहीं होने चाहिएं। सारी पावर सेन्ट्रलाईज करने की जो कोशिश है वह ठीक नहीं है इसलिए किसी छोटे-मोटे काम के लिये मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं जाना चाहिए और लाखों रुपया जो उनके जाने पर खर्चा होता है, तेल इतना बेकार फूंका जाता है वह सब नहीं होना चाहिए। बी०डी०ओ० लेवल के काम को केवल बी०डी०ओ० ही करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खेलों के सम्बन्ध में यहां बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं ओलंपिक संघ के प्रधान भी हमारे एक विधायक श्री अभय सिंह चौटाला हैं और वे कहते हैं कि हमने खेलों के लिए ये किया, वो किया। यह अच्छी बात है। लेकिन इसमें जाति-पाति नहीं चलनी चाहिए. यहां पर मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। जैसे गुड़गांवां, दादरी में खेल हुए उसी तरह पंचकूला में भी खेल हुए और पाकिस्तान से टीम आई थी जिसमें हरियाणा

की टीम शाबाशी से जीती। इस टीम के अन्दर ऐसे-ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पूरे-पूरे नम्बर लिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी यह खेल शायद देखा था। उसमें एक काला सा लड़का था जो बड़सेरा गांव का था जिसका नाम सुरेन्द्र था लेकिन वह बदकिस्मती से जाति से पंडित था। जब यह हरियाणा पुलिस की भर्ती में खड़ा हुआ तो उसने फिजिकल टैस्ट में 20 में से 20 नम्बर लिये लेकिन उसका नाम इसलिये चयन सूची से निकाल दिया क्योंकि वह जाति से पंडित है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : बलबीर जी, आप बोलिये क्योंकि खिलाड़ी की भावना को खिलाड़ी ही जान सकता है।

श्री बलबीर सिंह : सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में ये पूरे पांच साल मंत्री भी रहे हैं तथा इन्हें भी पता होगा कि पिछली सरकारों में ब्लॉक स्तर पर भी खेल बंद कर दिये गये थे इसलिये मैं भाई अभय सिंह चौटाला जो कि हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रधान हैं, को बधाई देता हूँ जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देकर नया रिकार्ड कायम किया है। पिछली किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि ये खड़े होकर फर्जी बात करें। ये अपनी आत्मा से बताएं कि मौजूदा सरकार ने खेलों को कितना बढ़ावा दिया है।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम कहते है कि जाति-पाति नहीं चलनी चाहिए।

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जाति-पाति की कोई बात नहीं है। यह 36 कौमों की सरकार है, जाति-पाति की सरकार नहीं है। इनकी सरकार की तरह नहीं है कि 1600 पुलिस कर्मियों में से 900 पुलिस कर्मी केवल बिश्नोई ही भर्ती कर दिये जाएं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूँ। सीवानी में सेठ हनुमान के पास टैलीफोन आया था कि 20 लाख रुपये भेज दो। तोशाम में कल ईश्वर जैन के घर टैलीफोन आया। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य पहले जिस पार्टी के विधायक बन कर आये उस पार्टी की सरकार ने किस भावना से फाईल पर लिख कर अपने चैहतों की परमोशन कर दी और यदि सरकार के किसी चहेते की कहीं पर ट्रांसफर होनी होती थी तो उस पर 'जे' लिख देते थे। हर बात में 'जे' लिख देते थे। उस समय इनको पीड़ा क्यों नहीं होती थी कि प्रदेश के साथ क्या हो रहा है और किसी जाति विशेष के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के पांच साल के शासन काल में हरियाणा की पर्टीकुलर एक कास्ट के साथ बहुत ज्यादती की गई। माननीय सदस्य के दिल में उस समय यह भावना आती तो मैं मानता कि वाकई ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से ऊपर उठ कर बात कर रहे हैं।

श्री धर्मबीर सिंह : मैं उस समय सरकार में मंत्री नहीं था। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : वह सरकार तो आपकी ही पार्टी की थी। (शोर)

श्री धर्मबीर सिंह : मैं उस पुरानी सरकार में शामिल नहीं था। स्पीकर साहब, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा था। सीवानी में सेठ हनुमान के पास हर रोज टैलीफोन आते हैं कि आज हनुमान सेठ 20 लाख रुपये भेज दो। डा० कुन्दन 30 लाख रुपये भेज दो वरना तेरा मर्डर होगा। कल तोशाम में ईश्वर जैन के पास टैलीफोन आ गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत

[श्री धर्मबीर सिंह]
है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल मेरे पास एक चिट्ठी आई वह चिट्ठी क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर साहब यह इनका होम डिपार्टमैंट है। हिसार का एस०पी० मेरे पास चिट्ठी भेजता है कि आप 8 तारीख को सैशन में जाने की बजाय हमारे दफ्तर हाजिर हों, आपके खिलाफ फलां-फलां केस दर्ज है। आप लोग कुछ तो शर्म करो। मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें कम से कम विधान सभा में तो अपनी बात कहने का मौका दो बाद में देख लेना। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए आपका धान्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री जसबीर सिंह मलौर : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी धर्मबीर जी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जहां तक टैलीफोन पर धमकी दे कर पैसे लेने की बात है इस बारे में सबसे बड़ा दोषी इनका भाई है जो क्रिमिनल है। उसके ऊपर सैंकड़ों मुकद्मे दर्ज हुए हैं। जब लोक सभा का इलैक्शन हुआ उस समय मुझे वहां पर जाने का मौका मिला था। उस समय वहां पर जो गुण्डागर्दी इनके भाई ने फैलाई थी उससे वहां पर एक आतंक का माहौल पैदा किया हुआ था। यह इनकी बात का उत्तर है।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। वैसे तो राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है उसकी भाषा बड़ी लच्छेदार होती है क्योंकि यह कैबिनेट का तैयार किया हुआ होता है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ग्राम विकास समितियां बनाने के बारे में जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्राम समितियां बनाई गई हैं मैं इनका कोई औचित्य नहीं समझता। ये अनकांस्टीच्यूशनल हैं और इनका कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि जिस विधान के तहत हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट, हरियाणा प्रदेश की असैम्बली या दूसरी स्टेट्स असैम्बलीज़ बनी हैं उसी विधान के तहत ग्राम पंचायतें भी बनी हैं. हर गांव में पंचायत है फिर ये अलग से ग्राम विकास समितियां कहां से आ गईं। ग्राम विकास समितियां बनाने से गांवों में पार्टीबाजी और झगड़े होंगे। अगर आप यह दलील देते हैं कि गांव ब्रोडबेस्ड हो तो आप ग्राम सभा बना दें। ग्राम विकास समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रदेश के गांवों को ब्रोडबेस्ड करना है तो आप ग्राम सभा बनाएं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल, ने अपने भाषण में कहा कि मेरी सरकार एस०वाई०एल० कैनाल बनाने के लिए कमिटिड है। मैं मानता हूँ , कमिटिड है। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुख्य मंत्री आता है हर मुख्य मंत्री यह चाहता है कि एस०वाई०एल० कैनाल बन जाए लेकिन यह बनी तो नहीं। मैं कहता हूँ कि यह बननी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री कुरुक्षेत्र आए। वह हमारे मुख्य मंत्री से कह गए कि आप दूसरे मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुला लें। नतीजा क्या होगा, वही ढाक के तीन पात। पंजाब कभी इस बात को नहीं मानेगा कि हरियाणा को पानी मिले। इसका सबसे ठीक तरीका यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो रिट पैंडिग है उसकी अरली हियरिंग के लिए हमारी सरकार एप्लिकेशन दे। हमारी यह रिट कई साल से सुप्रीम कोर्ट में पैंडिग पड़ी है। यदि इसका फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। यह फैसला आपसी लैवल पर नहीं होगा। एक दफा मैंने भारत सरकार से उस वक्त फैसला करवाया था जब मैं भारत सरकार में मंत्री था। उस वक्त पंजाब सरकार ने 15.18 मिलियन एकड़ फीट पानी माना है। हमने कहा कि 19 मिलियन एकड़ फीट पानी है। पंजाब ने इन्कार किया। मैंने भी कहा कि मेरे आंकड़े सही हैं। प्रधान मंत्री ने यह कहा कि 15.18 मिलयन एकड़ फीट पानी जो है इसको तो आज आपस में बांट लो। इसके बाद कोई पानी फ़ालतु है तो वह हरियाणा ले ले। मैंने कहा कि इसको प्रोसिडिंग्ज में लिखवा दें। मेरे कहने पर प्राईमिनिस्टर ने इस ढंग से प्रोसिडिंग्ज में लिखवा दिया –

"Punjab will get not more than 3.5 million Acre Feet and Haryana will get 3.5 Million Acre Feet."

यानि हमारे ऊपर कोई सीलिंग नहीं लगाई गई। वहां पंजाब की तरफ से ढिल्लों साहब केन्द्र में मंत्री थे। उन्होंने पंजाब वालों को इस फैसले के बारे में बताया। थोड़े दिन बाद उन्होंने बताया कि पानी तो ज्यादा है। उस वक्त प्रदेश में चौधरी भजनलाल मुख्य मंत्री थे। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने एक समझौता किया था। हमारे मुख्य मंत्री द्वारा उस समझौते में पंजाब को तो बढ़ा हुआ पानी मान लिया गया और हमारा पानी वही 3.5 मिलियन एकड़ फीट माना गया। सुप्रीम कोर्ट के जज इराडी के नाम से एक इराडी ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और उस ट्रिब्यूनल के सामने यह केस गया। उस वक्त चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे। उस ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग के चलते-चलते मैं दोबारा से मुख्य मंत्री आ गया। हमने यह केस डिफेण्ड किया। हमने कहा कि भारत सरकार का तो फैसला यह है। इस पर उन्होंने कहा—"Mr. Bansi Lal, I cannot go beyond the agreement of your predecessor. I am a sitting judge of the Supreme Court and the principal of resjudicata applies to you.

उस के बाद क्या हुआ कि इराडी ट्रिब्यूनल का जब फाईनल फैसला आया तो उसमें पंजाब का पानी तो बन गया 5 मिलियन एकड़ फीट पानी और हमारा रह गया 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी। उसके बाद भी पंजाब कहता रहा कि इस नहर को हम नहीं बनने देंगे और न वह बनने देगा। अगर पंजाब आज भी यह कहे कि हम इस नहर को बनाने देंगे तो मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मेरा ख्याल है सरदार प्रकाश सिंह बादल इनके अंकल लगते हैं। ये अपने अंकल से बैठकर फैसला कर लें। उनके घर जा कर ये फैसला कर लें या उनको अपने घर बुलवा कर फैसला कर लें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह फैसला घर बैठकर नहीं हो सकता, यदि इसका फैसला कभी हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। घर में बैठकर यह फैसला नहीं हो सकता क्योंकि वह अपनी बात नहीं छोड़ेंगे और न हमारा मुख्यमंत्री अपनी बात छोड़े और छोड़ भी नहीं सकता।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। बाकी बातें तो भजन लाल जी खुद जानें कि पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। मैं चौधरी बंसी लाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इराडी ट्रिब्यूनल जो बैठा था वह एज ऐ रिजल्ट आफ राजीव लौंगोवाल का जो समझौता हुआ था उसके तहत बैठा था। उसकी जो टर्म्ज एण्ड कंडीशंज थी उसका हमने उस वक्त भी विरोध किया था कि जो कंडीशंज लगाई गई हैं वे ठीक नहीं हैं। आपकी यह बात ठीक है कि पंजाब पर 3.5 मिलियन एकड़ फीट की सीलिंग लगा दी गई थी। लेकिन जो सीलिंग खोली गई थी वह राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत खुली थी। उसका हमने विरोध किया था। उसके बाद आप यहां पर आ गए और उस वक्त भजन लाल को यहां से हटा कर सैंटर में भेज दिया गया था। इनके वहां पर चले जाने पर आप मुख्य मंत्री बन कर आये थे। उस वक्त भी आपने उसको स्पोर्ट किया था क्योंकि आप मुख्य मन्त्री थे तथा हमारे विरोध को दबाने के लिए आपने लाठियां और गोलियां भी चलवाई थीं। अब आप जवाब दें, आपने उस वक्त उस समझौते को क्यों माना? आप भी दोषी हैं ये तो दोषी हैं ही आप भी कम दोषी नहीं हैं। आपने भी उस समझौते का पूरा समर्थन किया था। और अब आपको याद आ रहा है 3.5 की जो सीलिंग थी यह बाद में खत्म कर दी वरना यह बात खत्म नहीं होती यह उस वक्त खत्म हुई है।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी ने जो कहा वह सही बात नहीं है और सम्पत सिंह जी ने जो कहा है वह भी सही नहीं है। यह इसलिए सही नहीं है कि 3.5 का फैसला

[चौधरी भजन लाल]

पहले हुआ था। यह फैसला करवाने में भजन लाल भी शामिल था। (विघ्न) टोटल सात एम०ए०एफ० में आधा करवाने में ये भी शामिल थे। फिर क्या हुआ कि फैसला करवाया और एग्रीमैंट हो गया। उसके बाद कमीशन बैठा और उस कमीशन में यह तय हुआ कि पीछे पानी बढ़ गया है और हमने कहा था कि इस बढ़े हुए पानी में हमें भी शेयर मिलना चाहिए। पंजाब ने कहा कि हमें मिलना चाहिए (विघ्न) यह सारा लिखित में है और मेरे पास इसकी कॉपी है। यह रिकार्ड की बात है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है 3.5 एम०ए०एफ० से फालतू बढ़ा नहीं सकते थे। क्योंकि सीलिंग थी (विघ्न) यह जो बात कही है यह बात तो ठीक है कि सीलिंग तो थी।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनिये। आपने अपनी बात तो कह दी है, 3.5 की बजाए 3.85 तो हरियाणा का हो गया और .6 राजस्थान का पानी का हिस्सा बढ़ गया और कुछ पानी का हिस्सा पंजाब का बढ़ गया। बढ़े हुए पानी में हमारा शेयर बढ़ गया यह रिकार्ड पर था। (विघ्न) कमीशन ने यह बढ़ाया था। आप पढ़े लिखे आदमी हैं आप इस को पढ़ सकते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या राजीव–लौंगोवाल समझौते की टर्म्ज एण्ड कण्डीशन्ज के हिसाब से पानी का शेयर बढ़ाया था? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : पानी बढ़ गया इसलिए थोड़ा–थोड़ा पानी सब का बढ़ गया इसलिए ही हमारा बढ़ा है। (विघ्न) इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वह भजन लाल का है। इसमें न तो चौधरी बंसी लाल की सरकार का योगदान है और न ही इस सरकार का है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय क्यों खाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपको पूरा टाईम मिलेगा। ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं यह बिल्कुल सही कहता हूँ। इनके पास एग्रीमैंट की कॉपी का तो मुझे पता नहीं लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोपहर बाद के सैशन में वह एग्रीमैंट सदन के सामने पढ़ दूंगा। क्योंकि पानी हमारा कटा सिर्फ चौधरी भजन लाल के पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्री के एग्रीमैंट की वजह से, वरना हमारा पानी घटने का कोई चान्स ही नहीं था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो होना था वह हो गया लेकिन आज जो पानी एलॉट हुआ है वह तो लेने की कोशिश की जाए। मैं यह कहता हूँ कि इसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है।

चौधरी भजन लाल : सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को हम ही ले कर गए थे और इन्होंने आकर इसको वापिस ले लिया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी साफ कर देता हूँ। यह बात ठीक है कि चौधरी भजन लाल जी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जब पहली पेशी लगी वह मेरे वक्त में लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दफा 81 का नोटिस पंजाब सरकार को नहीं दिया गया इसलिए हम इसको डिस्मिस करेंगे। हमने कोर्ट में कहा कि उसको हमें वापिस दे दें हम इस फोरमैलिटी को पूरा कर देंगे। वह फोरमैलिटी पूर्ण करके हमने फौरन केस कोर्ट में फिर दाखिल कर दिया। अगर इनके भरोसे रहते तो हमारा केस तो फाईल हो गया था। (विघ्न) यह तो रिकार्ड की बात है, यह सुप्रीम कोर्ट का

रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक चर्चा है कि पंजाब से पूरा पानी लेने के लिए पैसे दिये गये। भाखड़ा और नरवाना ब्रांच दोनों में ही पानी कम आता है। मेरे वक्त में करीब 11 करोड़ रुपये हमने पंजाब को दिये थे। एग्जैक्ट एमाउंट तो मुझे याद नहीं, ग्यारह से कुछ कम या कुछ ज्यादा दिये थे। गालिबन 11 करोड़ 30 लाख या समथिंग दिये थे। इस वक्त उसका क्या हुआ, कितना पानी दिया है कितनी कैपेसिटी बढ़ी इस बारे में जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो उस वक्त बता दें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि विलेज लिंक रोडज् की रिपेयर तेजी से जारी है। ये रिपेयर कहां-कहां हो रही है। स्टेट में मैं भी जाता हूँ लेकिन मरम्मत कहीं पर भी नजर नहीं आती है।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह): ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के आने से पहले का जो साढे आठ और नौ साल का अर्सा था उस समय में रिपेयर पर 1066 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और हमारी सरकार के आने के डेढ़ साल के पीरियड में 9788 करोड़ रुपए रिपेयर पर खर्च किए गए हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बिजली का भी अभिभाषण में जिक्र किया गया है। छठे प्लांट का भी इसमें जिक्र किया गया है। रूलिंग पार्टी की तरफ से किसी भाई ने कहा था कि साढे आठ साल तक छठे प्लांट की मशीनरी नहीं खोली गई थी। मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि साढे पांच साल पहले वह मशीनरी आई थी। मेरी सरकार ने उसको खोला था और उसको लगाने की कोशिश करी थी। मेरी सरकार ने उस मशीनरी की पेमैन्ट अदा की थी, न इनकी सरकार ने अदा की थी और न ही चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने अदा की।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि यह बात मैंने ही प्वायंट ऑफ आर्डर पर कही थी। 1989 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने पानीपत थर्मल प्लांट 210 एम०डब्लू० के 6 यूनिट मशीनरी का 157.6 करोड़ का वर्क आर्डर किया था जिसमें से 100 करोड़ का सामान आ गया जो कि पांच साल तक पानीपत रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे और इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था जबकि 100 प्रतिशत उस प्लांट की फाउंडेशन का काम हो गया था। भजन लाल जी की सरकार के बाद बंसी लाल जी आपकी सरकार आई थी। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के वक्त बी०एच०ई०एल० ने दो करोड़ रुपया मशीनरी के रख रखाव के लिए मांगा था। परन्तु उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद साढे तीन साल तक बंसी लाल जी की सरकार रही और आपने भी वहां पर एक नट भी लगाया हो तो बता दें। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने ही उसका काम किया है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मशीनरी मैंने खोली थी और मैंने लगवाई थी। सिर्फ वहां पर कूलिंग टावर रह गया था। बाकी सब चीजें मेरी सरकार के वक्त में कम्पलीट हो गई थीं। अभिभाषण में जहां तक बिजली का जिक्र किया गया है, तो उस बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि आज बिजली की बहुत चोरी हो रही है। हर सरकार के वक्त बिजली की चोरी हुई है लेकिन जब से यह मौजूदा सरकार आई तब से बिजली की चोरी की परसैन्टेज बढ़ गई है। यह इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज जो मुख्य मंत्री हैं जब वे विरोधी पक्ष में थे तब इन्होंने कहा था कि आप बिजली के बिल न दें मैं जब आऊंगा तब बिजली के बिल माफ कर दूंगा। जो लोग बिजली के बिल देते भी थे उन्होंने भी बिल देने बंद कर दिए और बिजली की चोरी भी बढ़ गई। बिजली की चोरी के मामले में इनको कुछ करना चाहिए अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो बिजली की कोई भी कम्पनी चल नहीं पाएगी। आज बिजली के

[चौधरी बंसी लाल]

अधिकारी मीटर चैक करने के लिए जाते हैं, मीटर बदलते हैं, ठीक है। अगर मीटर की कैलिब्रेशन ठीक नहीं है तो बदलें। लेकिन ये क्या करते हैं मीटर तो बदल दिया ये प्वायंट चैक करते हैं, प्वायंट से इनको क्या मतलब है। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई आदमी मीटर लगाता है और अगर उसको दो प्वायंट की जरूरत होती है तो वह चार प्वायंट जरूर करवाएगा क्योंकि आज नहीं तो भविष्य में उसकी जरूरत बढ़ेगी ही। जो बिजली के प्वायंट लगाने वाला होता है वह प्वायंट ज्यादा लगा जाएगा क्योंकि उसको तो प्वायंट लगाने के पैसे मिलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मीटर तो आपने लगा रखा है और मीटर में जो बिजली खर्च हो रही है उसके हिसाब से आप अपना बिल ले लें। फालतू में लोगों को तंग क्यों करते हैं। पूरी स्टेट में इसके प्रति त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस स्थिति को सरकार को ठीक करना चाहिए। इसी तरह से नहरों के पानी की बात है। मैं यह बात नहीं कहता कि पानी पूरा है और सरकार उसको आगे नहीं दे रही है इमप्रैक्टिकल बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। अगर पानी बहुत कम है तो उसका बंटवारा तो ठीक से करना चाहिए और कम से कम सैंट्रल हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा को पीने का पानी तो दे दो। वहां पर चालीस-चालीस दिन तक नहर नहीं आती इसलिए वहां पीने का पानी नहीं मिल पाता। अगर गर्मी में पानी की यही हालत रही तो शहरों में या नलकूपों पर पानी के लिए रायट्स हो जाएंगे। इसलिए सरकार को पीने के पानी का प्रबंध करना चाहिए। इसी तरह से हिसार-घग्घर ड्रेन का जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। पिछले साल भी राज्यपाल महोदय ने इस ड्रेन का जिक्र अपने अभिभाषण में किया था और यह लिखा था कि डी.सीज. को यह हिदायत दी गयी है कि हिसार-घग्घर ड्रेन बननी है इसलिए सारे इक्विपमैंटस चैक करें। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हिसार-घग्घर ड्रेन पर कितना काम हो गया है, कितना काम चल रहा है। यह बात ठीक है कि हाँसी, हिसार, जींद, सफीदों और पूरा जींद जिला, हिसार जिला और कैथल जिले के कुछ इलाकों का पानी घग्घर में चला जाएगा क्योंकि पानी का बहाव उधर को है। इस बारे में क्या किया गया, इसके बारे में भी मुख्य मंत्री जवाब देते समय रोशनी डाल दें। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, महम और लाखन माजरा ड्रेन एवं खानपुर माईनर का जिक्र किया गया था और इस बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनका जिक्र किया गया है। मगर इसमें सरकार का क्या लेना देना है क्योंकि ये दोनों ड्रेनें तो मैंने बनायी थीं। लाखन माजरा और महम की ड्रेन में एक गाँव बहुअकबरपुर ने रोड़ा अटका रखा था। इसलिए इसमें केवल उतनी ही जगह बचती थी। बाकी इनका काम तो मैंने ही करवाया था। इस सरकार ने इसमें क्या किया? क्यों दोनों साल कागज खराब किए? अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के महकमे का कोई काम सैटिसफैक्ट्री नहीं है। सरकार को कम से कम नहरों की छंटाई एवं नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। इसी तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी चर्चा है कि मुख्य मंत्री जी बाहर गए और वह वहां से होण्डा, सुजूकी तथा वाई.के.के. कम्पनी लाए। मुख्य मंत्री जी बाहर गए इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर ये अच्छा ऐटमोसफियर बनाने के लिए जाएं उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अभिभाषण में जिन तीन कम्पनीज़ को इन्होंने बाहर से लाने का जिक्र किया है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इनको यहां पर लाने में इस सरकार का कोई योगदान नहीं है। योगदान इसलिए नहीं है क्योंकि होंडा कम्पनी जिसका ये बार-बार जिक्र कर रहे हैं मेरे वक्त में ही उसकी एप्लीकेशन आयी और मेरे समय में ही उसको प्लॉट ईयर मार्क किया गया एवं मेरे समय में ही उसकी सब टर्म्ज एंड कंडीशंज तय हो गयी थीं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम यह जापान को रैफर कर रहे हैं क्योंकि उसकी मंजूरी वहां से ही आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने ओथ 24 तारीख को ली थी और उसकी मंजूरी 30 तारीख को आयी थी इसलिए एक हफ्ते में इस सरकार की इस बारे

में क्या उपलब्धि रही। इसके अलावा सुजूकी और वाई.के.के. कम्पनी तो पहले से ही हरियाणा में मौजूद हैं इसलिए इनके लाने के बारे में इनका क्या योगदान है। (विघ्न) इसी तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हुडको के 321 करोड़ रुपये के लोन की चर्चा की गयी है। स्टेट हाईवेज की मरम्मत और वाईडनिंग करना अच्छी बात है सरकार इसको करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं उनमें से एक आध को छोड़कर सबकी खस्ता हालत है। यह काम सरकार को वार फुटिंग पर करना चाहिए। इसके बगैर करोड़ों का नुकसान है क्योंकि हाईवेज पर रोडवेज की बसें चलती हैं वे डीजल भी ज्यादा खायेंगी, उनके टायर भी फटेंगे और दूसरी चीजें होंगी। भारत सरकार ने डीजल पर टैक्स लगाया। विलेज लिंक रोड्ज के लिए पिछले साल 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ उसमें से हरियाणा प्रदेश का हिस्सा मिल गया होगा। यदि नहीं मिला हो तो अब ले आएं और काम करें। अब मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहूँगा। ट्रोमा सैंटर करनाल और सिरसा में बनाने की बात है, ठीक बात है, करनाल और सिरसा में ट्रोमा सैंटर बनाने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद, सिरसा और रोहतक में भी ट्रोमा सैंटर सबसे जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत रोहतक में है और रोहतक में बिल्डिंग भी बन कर तैयार हो गयी थी। प्रदेश में एक ही मैडीकल कॉलेज है इसलिए ट्रोमा सैंटर पहले उसमें बनाना चाहिए उसके बाद दूसरी जगहों पर बनाना चाहिए क्योंकि स्टेट हाइवेज हमारे हदूद में से निकलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नेशनल हाइवे नंबर एक पर सोनीपत, पानीपत,करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में भी ट्रोमा सैंटर बनने चाहिए क्योंकि हाइवेज पर ऐक्सीडैंट बहुत ज्यादा होते हैं। रोहतक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि यह हरियाणा के लिए सैंट्रल प्लेस है। इस बार शुगर मिल्स महीने सवा महीने देर से चलीं जिससे किसान को नुकसान हुआ तो मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगले साल इसे रिपीट न होने दें इस साल जो हो गया सो हो गया।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। चौधरी साहब, बहुत सीनियर पोलीटीशियन हैं लेकिन जो जानकारी में उनको दे रहा हूँ वह यह है कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के एक साल के कार्यकाल में चाहे भूना शुगर मिल हो, चाहे महम शुगर मिल हो, उनसे मैक्सिमम रिकवरी की है और चालू सीजन में पिछले सालों की तुलना में कम गन्ना पेरने के बावजूद भी सवा लाख चीनी की बोरियां ज्यादा तैयार की हैं। आने वाले समय में किसान का एक भी गन्ना बकाया नहीं रहेगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है।

चौधरी बंसी लाल : जितना लेट शुरू करोगे उतनी ज्यादा रिकवरी होगी।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, इनके समय में तो मिलें फरवरी माह में ही बंद हो गई थीं।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, अब मैं कर्मचारियों की बात कहना चाहूँगा। कान्फेड के तीन सौ या सवा तीन सौ आदमी सरकार ने हटा दिये या हटाने वाली है। कान्फेड में छह सौ सवा छह सौ आदमी अब भी काम करते हैं जिन लोगों की 20-20 साल की सर्विस है उनको निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए और जहां कहीं भी वैकेन्सी हो उन्हें वहां एकोमोडेट करना चाहिए ताकि गरीब आदमी ऐडजस्ट हो जाएं।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। बंसी लाल जी कान्फेड के बारे में कह रहे हैं, मेरे हल्के में सुरथल ब्रुअरी को इन्होंने बंद किया था जिससे 600-700 आदमी बेरोजगार हो गए थे और वे ठोकरें खाते घूम रहे थे। उनके बारे में भी ये बताएं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो पुलिस की भर्ती के लिए सरकार ने 500/- रुपये की ऐप्लीकेशन फीस रखी है यह नाजायज है। गरीब आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में फरीदाबाद में कर्मचारी निकाले थे लेकिन जब दबाव दिया तब इन्होंने उनको नौकरी पर रखा। आज इन्हें गरीब भी याद आ रहे हैं।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सफाई मजदूरों और नर्सों के साथ क्या बर्ताव किया था ?

चौधरी बंसी लाल : मैंने उनके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था न ही करूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन से मैं पैसा ले आया था तीन वाटर वर्क्स के लिए अम्बाला, कैथल और भिवानी, उसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि गुड़गांव में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज जो 20-25 मंजिल की हैं, उनमें दरार आ गई है। उस इलाके के कुछ लोग मुझे आकर मिले थे और वे इस बात से बड़े भयभीत थे। इसलिए इन बिल्डिंग्ज का कोई न कोई समाधान होना चाहिये, उनकी मरम्मत भी हो सकती है या उनको गिराना पड़ेगा। यह फैसला तो सरकार करे। इसी तरह से रैस्ट हाउसिज को बेचने वाली बात ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में चण्डीगढ़ की मांग की है। सभी पार्टियों के लोगों ने यह तय किया था कि हरियाणा के लिए शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिये। मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के ऊपर जोर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, वाइंड अप कीजिये।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से किसानों को बिजली देने के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। किसानों को बिजली देने का जो सवाल है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले तो सरसों की फसल की पकाई आयेगी उसके बाद गेहूँ की फसल की पकाई आयेगी इसलिए इस समय किसानों को पूरी बिजली मिलनी चाहिये ताकि फसल अच्छी तरह से पक सके और किसानों को उसका पूरा फायदा मिल सके। इससे स्टेट का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। आज सुबह माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं रैफर किया कि स्टेट में लड़कियों की संख्या कम है? यह ठीक है कि लड़कियों की संख्या कम है इसके आगे और बुरे परिणाम होंगे क्योंकि जो लड़के कुंवारे रह जायेंगे वे क्राइम करेंगे। इसके लिए सरकार से मेरा सुझाव यह है कि जो अलट्रा साउंड की मशीनें हैं उन पर सख्त कंट्रोल किया जाये ताकि अबोरशन वगैरह न किये जा सकें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य करण सिंह दलाल किस बात पर बोल रहे थे। इन्होंने रोंझ को परिवार नियोजन के इंजैक्शन देने की बात कही थी और उनकी बात पर काफी शोर मचा था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर परिवार नियोजन की बात सिरे चढ़ जाती तो आज इस मुल्क में कोई प्राबल्म नहीं होती। लोगों ने उस पर कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसकी मुखालफत की। यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ती गई और उसी के कारण आज प्राबल्म हो गई है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक चर्चा यह भी की गई कि प्राइमरी स्कूलों को पंचायतों के अधीन देने की बात इस सरकार ने कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अगर आप पंचायतों को प्राइमरी स्कूलों का कंट्रोल देंगे तो उन पर कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि अगर किसी टीचर का ट्रांसफर करना पड़ा तो क्या टर्म एण्ड कंडीशन्ज होंगी? जो पहले से ही सर्विस में हैं उन पर टर्म एण्ड कंडीशन्ज क्या होंगी? मुझे तो यह काम इमप्रैक्टीकल सा लगता है अगर यह प्रैक्टीकल है तो मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में बता दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी

बात समाप्त करता हूँ।

श्री लछमन दास अरोड़ा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है उसके विषय पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि एक प्रथा सी बन गई है कि ट्रेजरी बैंचिज उस अभिभाषण को स्पोर्ट करते हैं और ओपोजिशन बैंचिज उसका विरोध करती हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे बजट हो, चाहे गवर्नर एड्रैस पर चर्चा हो परन्तु ऐसी प्रथा नहीं रहनी चाहिये क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए इससे पहले ही बाढ़ नियन्त्रण का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। क्योंकि सिरसा जिले में 22-23 गांव ऐसे हैं कि जब घग्घर नदी में फ्लड आता है तो ये पूरी तरह प्रभावित होते हैं और तबाह हो जाते हैं। 1994-95 से घग्गर डैम बनना शुरू हुआ है इस बांध पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन काम बीच में ही अधूरा पड़ा हुआ है। 3-4 सालों से बारिश नहीं आई है लेकिन कल को अगर फ्लड आता है और इस बांध के काम को नहीं सम्भाला गया तो इन 22-23 गांवों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी और इन गांवों में पानी चला जाएगा। फिर उस पानी को निकाला नहीं जा सकेगा क्योंकि यह बांध कुछ-कुछ बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बांध का काम कम्पलीट करवाया जाए। जहां तक सड़कों की बात है, सिरसा शहर के सौन्दर्यकरण की बात कही गई है। मुख्य मंत्री महोदय का 15-20 दिन में सिरसा शहर का चक्कर लगता रहता है वहां के अधिकारी मुख्य मंत्री महोदय को ऐसे रास्ते से लेकर जाते हैं जहां इनके सामने शहर की सड़कों की असलियत नजर नहीं आती है। इसके अलावा जहां मुख्य मंत्री महोदय जी की कोठी है उसका तो सौन्दर्यकरण किया गया है लेकिन ये अधिकारी मुख्य मंत्री महोदय का शहर के इंटीरियर एरिया में जाने का प्रोग्राम नहीं बनाते इसलिए मुख्य मंत्री महोदय को इंटीरियर इलाके में, शहर में जो हो रहा है उसका पता नहीं चलता है। अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस टैक्स की बात आई है, हाउस टैक्स के बारे में लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, फीते लेकर कोठियों और मकानों को मापा जा रहा है। लोगों में दहशत फैलाई जा रही है कि इस तरह, उस तरह से हाउस टैक्स लगाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वाटर टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा। जहां तक पीने के पानी की बात है, तो 10-10, 12-12 हजार रुपये पानी के बिल उन लोगों को आ गए जो रेहड़ी लगाते हैं। पूछने पर बताया गया कि इन्होंने 10 सालों से बिल नहीं भरे थे। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि 10 साल तक उनको पानी के बिल क्यों नहीं दिए गए? आज गरीब आदमी इतने बिल की पेमैंट कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, बरनाला रोड के साथ सिरसा में एक माइनर पड़ती है। उसके आगे 2 किलोमीटर तक का एरिया जहां रेलवे क्रासिंग पड़ती है उसको चतुर्गढ़ पट्टी बोलते हैं। अगर वह 2 किलोमीटर सड़क नहर के साथ बन जाती है तो आधा ट्रैफिक मंडी का, आउटर कालोनी का उस तरफ हो जाएगा। और यह कोई लम्बी-चौड़ी बात भी नहीं है, इससे शहर बड़ा सुखी हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह नैशनल हाइवे का बाई पास जो पास हुआ है उसकी डिमार्केशन भी हो चुकी है। इसके लिए कई अड़चनें आई हैं। यह 15 सालों से बनने जा रहा है लेकिन बीच में ही अधूरा पड़ा हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय से मेरा खासतौर से अनुरोध है कि इसकी तरफ ध्यान दें क्योंकि इसके कारण शहर में इतनी भीड़ हो जाती है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण पिछले दिनों सदन में दिया, इस अभिभाषण को पढ़कर यह लगता है कि हरियाणा की जो

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

समस्याएं हैं, लोगों की इस सरकार से जो उम्मीदें हैं, हरियाणा की जो खास जरूरतें हैं, उनके ऊपर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इससे यह आभास होता है कि आने वाले दिन हरियाणा प्रदेश के लिए कोई अच्छे दिन नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब हरियाणा के मुख्य मंत्री बने, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन दिनों में हम श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे। वे ऐसे हालात थे, जिनसे बचा नहीं जा सकता। लोक सभा के चुनाव उन दिनों में होने जा रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला जी तमाम हरियाणा के अन्दर जितनी सभाओं को सम्बोधित करते थे उन जनसभाओं में हरियाणा के लोगों को काफी आश्वासन देते थे, लोगों को बड़े सुनहरे सपने दिखाते थे। मुख्य मंत्री जी उस समय यह भी कहते थे कि ये हरियाणा के किसानों को बिजली पानी मुफ्त देंगे, 90 हजार नये रोजगार दिये जायेंगे, एस०वाई०एल० के पानी को हरियाणा के अन्दर लाया जायेगा, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, जिन कर्मचारियों की छंटनी हो गई उन्हें एडजैस्ट किया जायेगा और साथ में यह भी कहते थे कि ये तो इनकी फिल्म का ट्रैलर है। फिल्म तो ये उस समय दिखायेंगे जिस समय ये दोबारा से मुख्य मंत्री बनेंगे। लेकिन इन्होंने पहले वाले वायदे भी पूरे नहीं किये। अब जब इन्होंने भयानक फिल्म हरियाणा की जनता को दिखानी शुरू की है उससे चारों ओर त्राही-त्राही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चौटाला साहब की सरकार बनी है। सदन से बाहर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी यही कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी की यह भयानक फिल्म किसी तरह बंद हो। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री जी का पद कोई स्थाई नहीं होता, यह जनता की मेहरबानी पर निर्भर करता है। हरियाणा के अंदर कई मुख्य मंत्री बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चौटाला साहब ने रवैया अपना रखा है वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें। राजनीतिक बातें न करें। आप तो इस तरह भाषण दे रहे हैं जैसे किसी आम सभा में दिया जाता है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। मैं मेरे माननीय साथी दलाल साहब को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हाउस का समय बहुत कीमती होता है, ये तीन बार विधायक रह चुके हैं इसलिए इस बात का इन्हें पता है। इसलिए ये हाउस का समय नष्ट न करें और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही आ रहा था, आपने मेरी बात को वैसे ही अन्यथा मान लिया। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने असत्य का रवैया अपना रखा है और हरियाणा की जनता को गलत तस्वीरें दिखा कर गुमराह कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले थीन डैम की 50 प्रतिशत बिजली हरियाणा में लाने की बात कही थी और अखबार में इस बारे में इन्होंने स्टेटमैंट भी दी थी। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छी बात है कि ये थीम डैम की 50 प्रतिशत बिजली हरियाणा में लाना चाहते हैं। इसके लिए यह पूरा सदन और हरियाणा की जनता पूरी तरह से इनके साथ है। थीन डैम पर रावी-ब्यास के पानी से बिजली बनेगी इसलिए उस पर हमारा हक भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ ब्यान देना सीखा है, लोगों को गुमराह करना सीखा है। अगर ये वाकई में थीन डैम से बिजली लाना चाहते हैं तो यहां हाउस में बतायें कि वे किस तरह से बिजली लायेंगे। क्या मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से बात की है? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मुख्य मंत्री जी कहते थे कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलेगा लेकिन पीछे धान की फसल की खरीददारी

ठीक तरह से नहीं हुई। स्पीकर सर, यह फसल आपके इलाके में भी बोई जाती है। जिस समय इस फसल की खरीददारी हो रही थी उस समय मुख्य मंत्री जी विदेश दौरे पर गये हुए थे और किसी भी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मण्डियों में जाते और किसानों को आश्वासन देते कि उनकी फसल सही तरीके से खरीदी जायेगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं मेरे माननीय साथी दलाल साहब को बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश के हित के लिए विदेशी दौरे पर गये थे और उस समय अरोड़ा साहब, गोयल साहब और स्वयं मैं मण्डियों की हर मिनट की धान की खरीद के बारे में जानकारी ले रहे थे। अध्यक्ष महोदय, धान की खरीद के बारे में जो अनियमतिताएं मिली हैं उन अनियमितताओं के सम्बन्ध में समय-समय पर हम इनसे निर्देश लेते रहे। (शोर) और मैं हाउस में बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी तो उस वक्त एक साल में जितना धान खरीदा गया उससे ज्यादा धान वर्तमान सरकार ने एक दिन में खरीदा। जितना धान मण्डी के अन्दर आया उसका 82 प्रतिशत धान सरकार ने खरीदा है। दूसरी बात जो कर्ण सिंह दलाल कह रहे थे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की ओर से हाईवे पर जाम लगवाया गया। वहां से होडल की मंडी में धान आ रहा था। हम उस धान को इस लिये नहीं खरीदते थे क्योंकि हम चाहते थे कि पहले हमारे हरियाणा के किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे कि हम भी यहां पर अपना धान बेचेंगे। इस सम्बन्ध में मैंने और मेरे मंत्री साथियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्र में श्री शांता कुमार जी से विनती की थी कि हरियाणा के साथ यह ज्यादती हो रही है। उसके बाद शांता कुमार जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात की और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री जी से बात की तो उत्तर प्रदेश का धान खरीदने की बात भी हरियाणा ने स्वीकार की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री कर्ण सिंह दलाल को यहां तक कहता हूँ कि हरियाणा सरकार अब की बार यह कदम न उठाती तो किसानों को धान की फसल में वाकई नुक्सान होने की संभावना होती। हमने तो अपने किसानों को इस नुक्सान से बचाया है। माननीय सदस्य को तो इस बात का समर्थन करना चाहिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों का धान दो साल से लगातार *********

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप चेयर की अनुमति से ही खड़ा हुआ करें। भजन लाल जी ने जो कहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये मुख्य मंत्री होते थे तो पूरे साल में 43000 टन जीरी खरीदी गई जबकि हमने एक-एक दिन में 60-60 हजार टन जीरी खरीदी है (शोर) सरकार की तरफ से 540/- रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का मूल्य निर्धारित किया गया और उसी हिसाब से हमने धान खरीदा। इसके बाद भी हमने प्रदेश के किसानों को कहा कि अगर फिर भी कहीं कोई बेकायदगी हुई होगी तो उसका भी हम कोई ईलाज करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भजन लाल के राज के वक्त इतना धान खरीदा गया जबकि हमने इतना धान खरीदा। मुख्य मंत्री जी को यह भी समझ होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। ये जरा दिमाग लड़ाएं कि इसके क्या कारण हैं ? हमने किसानों के

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]
धान का भाव मार्किट में कम नहीं होने दिया बल्कि व्यापारियों ने ज्यादा भाव में उनसे धान खरीदा। इसी वजह से सरकार ने कम धान लिया ताकि किसानों को धान की कीमत स्पोर्ट प्राइस से भी ऊंची मिल सके। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये बताएं तो सही कि किस भाव में धान खरीदा?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट प्राइस से भी ऊंचे भाव में लिया गया। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात धीरपाल जी ने कही है यह बात वे पहले भी कह चुके हैं लेकिन स्पीकर सर, एक बात आप भी जानते हैं और मैं भी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के किसानों के लिये धान के लिये एक पैकेज की घोषणा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूं और आप भी चाहें तो सदन की एक कमेटी बना दें तो पता चलेगा कि हरियाणा के किसी भी किसान को उस पैकेज का एक भी पैसा नहीं मिला। आप स्वयं भी किसान हैं, चाहें तो किसी भी मण्डी से पता करा के देख लीजिए, किसानों से पता करा लीजिए। अगर केन्द्र के पैकेज का एक भी पैसा हरियाणा के किसानों को मिला हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से इन्होंने लोगों को गुमराह किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन का एक सम्मानित सदस्य बिना ज्ञान के आधारहीन और अनर्गल बात सदन में कह रहा है जबकि किसी किसान का एक दाना भी 540/- रुपये प्रति क्विंटल से कम रेट में नहीं खरीदा गया और यह क्रैडिट हरियाणा सरकार को जाता है कि हमने किसानों को पूरा पैसा दिया है। इस सम्बन्ध में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। जब सदन के नेता हाउस में खड़े हों तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यू०पी० की जीरी आई है और अब भी आ रही है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप दो मिनट में कन्कलूड करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके हिस्से में दस मिनट आते हैं। इससे ज्यादा समय आपका नहीं बनता। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी बातें आपकी सेहत के लिये अच्छी हैं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, टाइम का बंटवारा हिसाब से होना चाहिए। किसी पार्टी का अकेला आदमी है और अकेले विधायक को इतना समय दे दिया फिर भी यह चाहता है कि और समय दिया जाए। इससे अच्छे तो चौधरी बंसी लाल थे जो अपनी पार्टी के हिसाब से बोल कर बैठ गए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर चौधरी बंसी लाल को इतना समय दे सकते हैं तो मुझे और समय देने में क्या तकलीफ है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी की हैसियत इनसे दुगुनी है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसानों को 540/- रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव दिया गया। मैं फिर आपके माध्यम से इनसे अनुरोध करता हूं कि गांवों में जाएं और मुख्य मंत्री जी की हैसियत से न जाकर एक साधारण किसान की हैसियत से जाकर किसानों से पूछें कि क्या उनको धान की इतनी कीमत मिली है। स्पीकर सर, किसानों को धान की इतनी कीमत नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण में नहरी पानी की चर्चा की गई लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि फरीदाबाद जिले के अन्दर मेवात के इलाके से मैं अकेला विधायक हूं जो कि सरकार में शामिल नहीं है, बाकी के सभी विधायक सरकार का समर्थन करते हैं। स्पीकर सर, आगरा नहर जो कि मेवात के तमाम इलाकों के खेतों को पानी देती है, महामहिम गवर्नर महोदय के अभिभाषण में कहीं पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में पहले यह नहर पूरी क्षमता के साथ चला करती थी। मेरे दूसरे साथियों को भी पता है लेकिन अब उन इलाकों में कई महीनों से खेतों के अन्दर पानी नजर नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई कर्ण सिंह दलाल से यह निवेदन करूंगा कि तथ्यों से बाहर विधानसभा में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि छायंसा डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज सब पक्की हो रही हैं। जो नहरें पक्की हो रही हों तो उन में पानी तो रोकना पड़ता है। दलाल साहब को यह बात पता होनी चाहिए। मेरे माननीय साथी जिले में तो जाते नहीं, पता नहीं कहां घूमते रहते हैं। आदरणीय चौटाला साहब की सरकार में डेढ़ साल के कार्यकाल के अन्दर फरीदाबाद जिले के अन्दर ही बिजली और पानी के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात एरिया और फरीदाबाद के किसानों को आगरा कैनाल का नहरी पानी नहीं मिल रहा है। किसानों के प्रति इससे बड़ी और ज्यादती क्या हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और आदरणीय साथी कर्ण सिंह दलाल को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के काल में उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में टेल तक कभी पानी नहीं पहुंचाया गया। चौधरी बंसी लाल जी भी यहां पर बैठे हुए हैं अगर दलाल साहब में हिम्मत हो तो वे इस बात को स्वीकार करें। अब की बार वहां टेल तक पानी पहुंचाया गया है (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि जब कर्ण सिंह दलाल चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में मंत्री थे तो गलत मोडलिंग करके वहां पर सड़क बनाई गई जिस पर दो करोड़ रुपये खर्च किए गए। वह सड़क आज भी ज्यों की त्यों है। इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए। इसके अलावा इनकी सरकार के समय में गंगा का पानी हरियाणा में लाने की बात कही जाती थी और आज भी वहां के लोग गंगा के पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फिर गंगा का पानी कहां गया?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस तरह से कोई बात नहीं कहता जबकि ये बोलते हैं तो काटने को आते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पुलिस की भर्ती की बात कही गई है। स्पीकर सर, पुलिस की भर्ती हो या दूसरी किस्म की भर्तियां हों उनकी एक मर्यादा होती है। पुलिस की भर्ती उसी इलाके से होनी चाहिए थी जहां की पोस्ट भरी जाती है। मैं तमाम् हरियाणा की सलैक्शन लिस्ट आपको दे सकता हूं। मैं अपने जिले फरीदाबाद के लोगों के नाम भी बता सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और सिरसा जिले के लड़के फरीदाबाद में भर्ती कर दिये गये। इतना ही नहीं, उन लड़कों की भर्ती हुई जिनके कद पांच फुट और पेट तीन फुट आगे की ओर निकले हुए हैं। (शोर)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पड़ौसी हैं और मैं सब जानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इनके पूरे शासनकाल में फरीदाबाद में जितनी नौकरियां लगी हैं उससे जायादा आज की सरकार ने फरीदाबाद जिले के लोगों को नौकरियां दी हैं। अगर मेरे साथी में हिम्मत हो तो त्याग पत्र देने के लिए तैयार हो जाएं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कोई भी जिला हो, फरीदाबाद हो, गुड़गावां हो या और कोई भी जिला हो। पहले शुरू में जब हमारी सरकार ने यह नियत किया था कि हम जिले वाइज पुलिस की भर्ती करायें तो लोगों ने कोर्ट में जाने व षड्यन्त्र रचने की कोशिश की। भर्ती के नियम ऐसे हैं कि हरियाणा का कोई भी आदमी भर्ती के लिए कहीं भी अपीयर हो सकता है। नियमों की अवहेलना तो नहीं की जा सकती है। जहां कहीं भी लड़के अपीयर हुए उसी हिसाब से सिलैक्शन हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि जो आदेश मैं एक बार कर देता हूँ उसको वापस नहीं लेता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण पाल जी के एरिया में एक मंदिर पहले तो सरकार ने तुड़वा दिया। बाद में जब उसका व्यापक विरोध हुआ तो इन्होंने कह दिया कि हम इसको दुबारा बनवा देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप मुख्य मंत्री के बारे में सुनना नहीं चाहते तो मैं दूसरी बात कह लेता हूँ। लेकिन आप मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी अब आप बैठिये। अब श्री दान सिंह जी बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने दान सिंह जी को बोलने के लिए कह दिया है? अब दान सिंह जी बोलेंगे।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर महोदय के एड्रैस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ? गुजरात त्रासदी एक बहुत ही दर्दनाक घटनाओं में से एक ऐसी घटना है जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। (शोर एवं विघ्न)

वाक-आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे केवल दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये आपका समय खत्म हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे तो मैं वाक आऊट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के सदस्य, श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आऊट करके चले गए।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है या विदेशी आक्रमण हमारे देश पर होते है तो उस वक्त सारा राष्ट्र एकजुट होकर उस समस्या का सामना करता है। गुजरात की त्रासदी के अन्दर भी ऐसा ही हुआ है कि वहां पर उनकी मदद के लिए सारा राष्ट्र एकजुट होकर आगे आया। उनके पुनर्वास के लिए पूरे राष्ट्र ने एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनकी सहायता करने का प्रयास किया चाहे वह स्वयंसेवी संस्था थीं, या राजनैतिक पार्टियां थीं, सभी ने एक साथ मिलकर उनका साथ दिया। हमारी सरकार ने भी उनकी मदद की जो कि एक सराहनीय कदम है। मैं इस कदम के लिए सरकार को बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित है। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि ''देयर इज नो कल्चर एक्सैप्ट एग्रीकल्चर''। लेकिन आज हमारे किसानों को न तो बिजली पूरी मिल रही है और न पानी मिल पा रहा है। किसान अपने उत्पदान को सस्ते में बेच रहा है जबकि उसकी लागत कहीं अधिक आती है। किसान इस बात से बहुत दुःखी है कि उसकी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का किसान आज खून के आंसू बहा रहा है। हरियाणा, जिसे हम सम्पन्न स्टेट कहते हैं वहां पर 25 प्रतिशत के आस-पास लोग बिलो पावरटी लाईन रहते हैं जो भूखे पेट सोते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा की सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। मैं खास तौर पर दक्षिणी हरियाणा की बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहां पर जलस्तर दिन-प्रति-दिन नीचे जाता जा रहा है। बरसात की कमी है और रिचार्जिंग के स्रोत नहीं हैं। जिसके कारण पानी का स्तर 400-450 फुट नीचे चला गया है। इस प्रदेश की राजनीति में एस.वाई.एल. कैनाल का सुनहरा ख्वाब सुनहरा स्वप्न हर पार्टी दिखाती रही है और वर्तमान सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने भी इस अभिभाषण में इसका जिक्र किया है कि हम एस.वाई.एल. का पानी लाने के लिए तत्पर हैं। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या एक राजनीतिक पहलू में उलझ कर रह गई है। आज तक इस बारे में कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि न ही ऐसी कोई नीति है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पानी अवश्य आएगा लेकिन हमारे खेतों में नहीं बल्कि हमारी आंखों में आएगा। जब किसान बर्बाद हो जाएगा उसके बाद उस पानी का क्या लाभ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि केन्द्र में भी उनकी पार पटती है और पड़ौस के राज्य में भी उनकी जो दोस्ती है वह सब को पता है। कावेरी जल-विवाद की तरह इस समस्या का कोई हल निकालने का प्रयास करें ताकि यहां का किसान जीवित रह सके। रहा सवाल बिजली का, बिजली के बारे में वर्तमान सरकार ने चुनावों से पहले लोगों से वायदा किया था कि हम चौबीसों घण्टे और सस्ती बिजली आपको देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें सस्ती बिजली तो नहीं मिली लेकिन हम पर बिजली पड़ अवश्य गई है। किसान का जो बिजली का 300/- रुपये का बिल आता था आज उसका रेट 550-600 रुपये कर दिया गया है। पहले प्रति यूनिट रेट 3 रुपये 06 पैसे था लेकिन आज 4.60 रुपये प्रति यूनिट

[राव दान सिंह]

बिजली का रेट कर दिया गया है। तो यह हालत आज हमारी बिजली की है। रहा सवाल मेरे अपने क्षेत्र के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र और खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा बिजली पर निर्भर है क्योंकि वहां पर नहरी पानी नहीं है। वहां पर हजारों की संख्या में ट्यूबवैल्ज हैं। वहां का सब-स्टेशन 32 के.वी.ए. का है उसको 220 के.वी.ए. तक बढ़ाने के लिए सरकार के पास प्रस्तावित परपोजल है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका दर्जा बढ़ाएं इससे किसान के लिए कुछ सहूलियत होंगी। इसी तरह से दो और छोटे-छोटे सब-स्टेशन्ज हैं। एक बवानी के अन्दर 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन है और दूसरा मण्दौला के अन्दर है जहां से किसानों का ऐजिटेशन मण्डियाली गांव में शुरू हुआ था। उस जगह के किसानों की राहत के लिए परपोजल बना हुआ है मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दे कर इनको भी जल्दी से जल्दी लगाने का कार्यक्रम बनाए। रहा सवाल स्वास्थ्य के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर उसका नागरिक होता है। अगर नागरिकों की सेहत ठीक है तो राष्ट्र समर्थ है और अगर नागरिकों की सेहत ठीक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वह राष्ट्र भी समर्थ नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि "सबसे पहला सुख निरोगी काया" यदि आपके शरीर में पीड़ा हो और आपको चारों तरफ से सुखों में गाड़ भी दिया जाए तो भी आपके मुंह से यही निकलेगा कि मुझे धन सम्पत्ति नहीं चाहिए मुझे तो शरीर का सुख और चैन चाहिए। इसके लिए हमारे सरकारी अस्पताल हैं हमें चाहिए कि उनका रख-रखाव इस प्रकार से किया जाए ताकि वहां पर जाने वाले किसी भी रोगी को पूर्ण उपचार मिले। सरकार की तरफ से जो उदासीनता इस तरफ आ रही है उसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। वहां पर इलाज के लिए जो मैडिसन्ज भेजी जाती हैं, इस के बारे में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि सरकार की तरफ से कितनी मुफ्त दवाईयां भेजी जाती हैं तो यह जवाब मिला था कि सात करोड़ 65 लाख समथिंग की दवाइयां भेजी जाती हैं। इसमें पर्टिकुलर महेन्द्रगढ़ के लिए 3 लाख 92 हजार की दवाइयां भेजी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि वहां पर अगर कोई सिरदर्द की भी दवाई मांगता है तो उसके हाथ में पर्ची पकड़ा दी जाती है कि बाहर की दुकान से लीजिए। ये अस्पताल एस.एल.आर. काटने के अलावा कुछ नहीं हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि वहां के नागरिकों की सेवा हो सके। एक और अफसोसपूर्ण और दुखद घटना एक अखबार के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अमर उजाला अखबार के अन्दर यह खबर आई है और पानीपत के सरकारी अस्पताल का यह फोटो खींचा हुआ है। उस अस्पताल के बैड के ऊपर दो कुत्ते बैठे हुए हैं इससे यह अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है कि यह आदमियों का अस्पताल है या कुत्तों का अस्पताल है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और यह देखे कि इसके नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं और क्या-क्या उनकी मदद हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है, तो एक नागरिक के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज मुख्य मंत्री जी ने सुबह आते ही कहा कि आज महिला दिवस है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहूँगा कि जब स्कूलों का दर्जा बढ़ाते हैं तो इनको उन स्कूलों का दर्जा बढ़ाना चाहिए जहां पर लड़कियां पढ़ती हैं. अगर कोई लड़की पढ़ती है तो परिवार पढ़ता है और एक परिवार पढ़ता है तो सारा गांव पढ़ता है। आपको लड़कियों के स्कूलों का दर्जा बढ़ाना चाहिए। रहा सवाल कम्प्यूटराईजेशन का। यह बहुत ही अच्छी बात है कि ये पहली कक्षा से बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कमरे नहीं हैं और वे बच्चे बाहर ग्राउन्ड में या पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो ये उन कम्प्यूटर्ज को कहां पर रखेंगे। पहले आप इन्फ्रास्ट्रचर को ठीक करें। जहां तक

आई०टी०की बात है यह बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसके लिए आपको अपने नागरिकों को देखना चाहिए कि वे कहां पर स्टैण्ड करते हैं। आपको पहले उनको इन सब चीजों की नौलिज देनी चाहिए ताकि जो कुछ भी आप अपनी स्टेट में करने जा रहे हैं वे उस बारे में भली-भांति से जानते हों। यह जो आपने नांगल चौधरी में साईबर कैफे खोला है, कनीना में खोला है। इसके बारे में आप अपने नागरिकों को शिक्षित करें। वे जो आपने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को और उद्योगों को यहां पर बुलाया है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह जरूरी है कि वे यहां के लोगों को उद्योगों में रोजगार दें। हमारे जिन बच्चों ने टैक्नीकल ऐजुकेशन प्राप्त की हो उन्हें नौकरियां दें। इस प्रकार का प्रबन्ध आपको करना चाहिए। वे उद्योगों में स्टाफ भरती करते समय हमारे बच्चों के बजाए बाहर के क्षेत्रों से बच्चों को लेते हैं। वे हमारे बच्चों को किसी छोटे पद पर भी रखने को तैयार नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे खासतौर पर इस ओर ध्यान दें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमती हो तो सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर शहीदों की बात की जा रही थी। यह जो कारगिल का युद्ध हुआ और उनमें जो जवान शहीद हुए उनको केन्द्र सरकार ने और इस सरकार ने बहुत सम्मान दिया। उनको दी जाने वाली राशि को पांच लाख से बढ़ा कर दस लाख कर दिया था यह बहुत ही अच्छी बात थी। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि आज जो जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वे जवान नहीं है, क्या उनका खून खून नहीं है, क्या उन जवानों के मरने से किसी मां की कोख खाली नहीं हो रही है, सरकार यह बताए कि उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या केन्द्र सरकार और यह राज्य सरकार कारगिल के युद्ध के वक्त राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते थे जो उस वक्त शहीद हुए जवानों के परिवारों को तो राहत राशि प्रदान कर रहे थे, और उनका सम्मान किया जा रहा था अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि जो जवान आज लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, उनको भी वही सम्मान दें।

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी आप जल्दी वाइंडअप करें।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के लिए यहां पर बातें कहीं जा रही हैं। मैं यहां पर महेन्द्रगढ़ के बारे में कहना चाहूँगा कि वहां पर नगरपालिका तो नाम की ही है, वहां पर गन्दगी के ढेर लगे रहते हैं। जब वहां के सैक्रेटरी और उप-मण्डल अधिकारी से इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है की हमारे पास धन का अभाव है। कृपा करके मुख्य मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें और वहां पर धन का प्रावधान करें। जन-स्वास्थ्य के लिए यह कहा जाता है कि इन्होंने प्रति व्यक्ति पानी 55 लीटर से 70 लीटर किया है। यह बहुत ही अच्छी बात होती अगर यह वास्तविकता में होता। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ के इलाके में वहां की नहर को आज 150 क्यूसिक पानी मिल रहा है जबकि वहां पर 650 क्यूसिक पानी की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आज

[राव दान सिंह]
के मौसम में वहां पानी की यह हालत है तो मई और जून के महीने में क्या हालात होंगे?

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी आप बैठ जाएं आपका समय समाप्त हो गया है।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 2000-2001.

Finance Minister : (Prof. Sampat Singh) Sir, I beg to present the Supplementary Estimates for the year 2000-2001.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now, Shri Krishan Lal Panwar, Chairperson of Estimates Committee, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2000-2001.

Shri Krishan Lal Panwar : (Chair person Estimates Committee) Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2000-2001.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 p.m. today.

*13.31 hrs. (The Sabha then * adjourned till 2.00 p.m. today i.e. 8th March, 2001.)

33155–H.V.S.–H.G.P., Chd.